सूर्योदय 6.03 सूर्यास्त 6:32

आज का तापमान

शिमला	16.2 न्यू	23.8 अधि
धर्मशाला	13.8 न्यू	28.0 अधि

बाजार

सेंसेक्स	74,902
निफ्टी	23,477

सोना 1,53,000 चांदी 2,34,000

भारतेन्दु शिखर

हिमाचल, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, जम्मू व उत्तराखंड में प्रसारित

आरएनआई नं. HPHIN/2000/02437 | शिमला | शुक्रवार, 11 सितंबर 2026 | 26 भाद्रपद, विक्रमी संवत 2083 | वर्ष 28, अंक 137, कुल पृष्ठ 12 | मूल्य : 5 रुपए | info@bhartendushikhar.com | 8894677702

न्यूज शॉर्ट्स

मिडटर्म चुनाव जीता तो हर वोटर को पांच लाख : ट्रंप

एजेंसी, वॉशिंगटन। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि नवंबर के मिडटर्म चुनाव में अगर रिपब्लिकन पार्टी प्रतिनिधि सभा और सीनेट, दोनों में बहुमत बरकरार रखती है, तो हर बालिग अमेरिकी को 5000 डॉलर (करीब 4.76 लाख रुपए) दिए जाएंगे। ट्रंप ने यह बयान डलास में रिपब्लिकन कन्वेंशन को संबोधित करते हुए दिया। उन्होंने इसे 'ट्रंप डिविडेंड' नाम दिया और कहा कि यह अमेरिका की 'आर्थिक ताकत और सफलता' की वजह से दिया जाएगा। ट्रंप ने ये भी कहा कि डिविडेंड की रकम अमेरिका में ही खर्च करनी होगी। हालांकि, उन्होंने यह नहीं बताया कि इसके लिए पैसा कहां से आएगा, भुगतान का दायरा क्या होगा और रकम किस तरह बांटी जाएगी। अमेरिका में करीब 26.98 करोड़ वयस्क हैं।, अगर सभी को 5,000 डॉलर दिए जाएं, तो कुल खर्च करीब 1.35 ट्रिलियन डॉलर यानी 128.25 लाख करोड़ रुपए होगा। यह रकम दुनिया के करीब 162 देशों की इकोनॉमी से ज्यादा है।

भाजपा ने सातों मोर्चों के बनाए नए प्रभारी

एजेंसी, नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने अपने सात प्रमुख मोर्चों के नए प्रभारी नियुक्त किए हैं। महासचिव हरीश द्विवेदी को भारतीय जनता युवा मोर्चा का प्रभारी बनाया गया है। भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डी. पुरंदेश्वरी को भाजपा महिला मोर्चा, राष्ट्रीय महासचिव सतीश पूनिया को अनुसूचित जनजाति (एसटी) मोर्चा, महासचिव संजय भाटिया को अनुसूचित जाति (एससी) मोर्चा, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वैजयंत पांडा को ओबीसी मोर्चा, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष लाल सिंह आर्या को किसान मोर्चा तथा गजेंद्र पटेल को अल्पसंख्यक मोर्चा का प्रभारी नियुक्त किया गया है। भाजपा के मुताबिक इन नियुक्तियों से संगठनात्मक गतिविधियों को नई गति मिलेगी और विभिन्न सामाजिक वर्गों के बीच पार्टी की पहुंच को और मजबूत करने में मदद मिलेगी।

कर्नाटक में वंदे मातरम के दो पैरा ही गाए जाएंगे

एजेंसी, बेंगलुरु। कर्नाटक सरकार ने वीरवार को सरकारी कार्यक्रमों में वंदे मातरम के सिर्फ पहले 2 पैरा गाने का आदेश जारी किया है। यह आदेश राज्य में होने वाले सरकारी कार्यक्रमों पर लागू होगा, लेकिन राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या राज्यपाल के शामिल होने वाले कार्यक्रमों को इससे बाहर रखा गया है। इसी साल 9 जुलाई को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने निर्देश दिया था कि सभी सरकारी कार्यक्रमों में राष्ट्रगान 'जन-गण-मन' के साथ 'वंदे मातरम' के सभी 6 पद गाए जाएं। इसके बाद 19 अगस्त को कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने वंदे मातरम को लेकर 1937 के अपने प्रस्ताव का पालन करने का फैसला किया। इस प्रस्ताव के तहत पार्टी कार्यक्रमों में राष्ट्रगीत के केवल 2 पैरा ही गाए जाएंगे।

रेलवे टेंडर घोटाला : लालू यादव तेजस्वी समेत 9 पर आरोप तय

दिल्ली कोर्ट ने 7 आरोपियों को किया बरी; होटलों के टेंडर से जुड़ा मामला

एजेंसी, नई दिल्ली। राऊज एवेन्यू कोर्ट ने रेलवे टेंडर घोटाला के मनी लॉड्रिंग मामले में राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) सुप्रीमो लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव के खिलाफ आरोप तय कर दिए हैं। स्पेशल जज विशाल गोगने ने आरोप तय करने का आदेश दिया। कोर्ट ने लालू यादव के दामाद राहुल यादव समेत सात लोगों को बरी करने का भी आदेश दिया।

कोर्ट ने इन तीनों के अलावा लारा प्रोजेक्ट्स, सरला गुप्ता, प्रेमचंद गुप्ता, सुजाता होटल्स, विनय कोचर और विजय कोचर के खिलाफ आरोप तय किया है। कोर्ट ने राहुल यादव, गौरव गुप्ता, नाथ मल कंकर्निया, विजय त्रिपाठी, डीएन

तुलस्यान, राजीव रेलान और अभिषेक फाइनेंस को बरी करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने 13 फरवरी को फैसला सुरक्षित रख लिया था। कोर्ट ने 28 जनवरी, 2019 को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर से दर्ज केस में लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव को एक-एक लाख रुपए के निजी मुचलके पर नियमित जमानत दी थी। कोर्ट ने 13 अक्तूबर, 2025 को रेलवे टेंडर घोटाले के सीबीआई से जुड़े मामले में लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव समेत दूसरे आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया था।

कोर्ट ने 17 सितंबर, 2018 को ईडी की ओर से दायर चार्जशीट पर संज्ञान लिया था। लालू यादव पर आरोप है कि उन्होंने रेलमंत्री रहते हुए रेलवे के दो होटलों को आईआरसीटीसी को ट्रांसफर किया और होटलों की देखभाल के लिए टेंडर जारी किए थे। रांची और पुरी के दो होटलों का आवंटन कोचर बंधु की कंपनी सुजाता होटल को ट्रांसफर कर दिया था।

3 अक्तूबर को होगी अगली सुनवाई

अदालत ने आरोप तय किए गए सभी आरोपियों को 3 अक्तूबर को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश होने का निर्देश दिया है। इसके बाद मामले की सुनवाई आगे बढ़ेगी।

सीजेआई सूर्यकांत बोले-14 साल की बच्ची से हिंसा गंभीर मामला

एजेंसी, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के विरोध प्रदर्शन में शामिल होने वाली 14 साल की लड़की को परेशान करने और उसके घर में तोड़-फोड़ के आरोपों को गंभीरता से लिया है। मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) की अध्यक्षता वाली बेंच ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कहा- अगर बच्चे के खिलाफ हिंसा करने वाले असामाजिक तत्व खुलेआम घूम रहे हैं और बच्ची को डराने की कोशिश कर रहे हैं, तो यह गंभीर बात हो सकती है। लड़की की एफआईआर पर कार्रवाई और उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करें। कोर्ट ने दिल्ली और यूपी सरकार से इस कार्रवाई पर रिपोर्ट भी मांगी है। जंतर-मंतर कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के प्रदर्शन के दौरान बच्ची के पिता पर हमला हुआ था। इस मामले में आरोपी स्वतंत्र भारद्वाज को जेल भेज दिया गया है। बच्ची और उसके पिता का आरोप है कि इसी मामले में उन्हें डराया-धमकाया जा रहा है। कोर्ट ने इसी मामले पर यह टिप्पणी की है।

एफआईआर पर तुरंत एक्शन लिया जाए

सीजेआई ने कहा- अगर ऐसे असामाजिक तत्व हैं, जिन्होंने बच्चे के खिलाफ हिंसा की है और वे खुलेआम घूम रहे हैं और बच्चे को डराने-धमकाने की कोशिश कर रहे हैं तो यह एक गंभीर बात है। एसजी मेहता ने कहा कि उन्हें बच्चे की सोशल मीडिया पोस्ट से इस मामले के बारे में पता चला था। वकील ने बताया कि ऐसे वीडियो हैं, जिनमें चार पुलिसकर्मी उन उपद्रवियों के साथ दिख रहे हैं जिन्होंने प्रदर्शनकारियों पर हमला किया था और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है।

भारत आएंगे चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग

एजेंसी, नई दिल्ली। ब्रिक्स समिट में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग भारत आएंगे। चीन के विदेश मंत्रालय ने वीरवार को जिनपिंग के भारत दौरे की पुष्टि की। जिनपिंग का यह 2020 में गलवान घाटी में हुई हिंसक झड़प के बाद भारत का पहला दौरा होगा। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जिनपिंग के बीच द्विपक्षीय बैठक होने की भी उम्मीद है। 15 जून 2020 को पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में हुई झड़प में 20 भारतीय सैनिक शहीद हुए थे। चीन ने बाद में अपने चार सैनिकों के मारे जाने की बात मानी थी। नई दिल्ली में 12-13 सितंबर को ब्रिक्स समिट आयोजित होगा। भारत व चीन के अधिकारी पिछले कई महीनों से दोनों देशों के रिश्तों को स्थिर करने की कोशिश कर रहे हैं।

◆ब्रिक्स समिट में होंगे शामिल

चीन के किंगदाओ में मालवाहक जहाज में आग लगने से 20 की मौत

एजेंसी, किंगदाओ। चीन के किंगदाओ शहर में वीरवार को मरम्मत के लिए खड़े एक विदेशी मालवाहक जहाज में अचानक आग लगने से 20 लोगों की मौत हो गई, जबकि 5 लोग लापता हैं। आग के वक्त जहाज पर कुल 42 लोग मौजूद थे। तुर्किए की सरकारी समाचार एजेंसी अनाडोलू तथा चीन की सरकारी समाचार एजेंसी शिन्हुआ के मुताबिक, जहाज में आग दिन में करीब 11:15 बजे लगी। हादसे के वक्त जहाज पर कुल 42 लोग सवार थे। स्थानीय अग्निशमन और बचाव विभाग के अनुसार, राहत एवं बचाव दल ने 12 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। वहीं, पांच घायलों को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनकी हालत स्थिर है।

भाजपा प्रवक्ता के खिलाफ पोस्ट डिलीट करेंगे सीजेपी नेता

दीपके, सौरव व रांका को समन; दोबारा ऐसी पोस्ट आई तो मेटा-एक्स हटाएंगे : हाईकोर्ट

एजेंसी, नई दिल्ली। भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया की मानहानि याचिका पर वीरवार को दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट के सामने सीजेपी प्रवक्ता सौरव दास और आशुतोष रांका ने भाटिया के खिलाफ किए गए एआई से बने विवादित पोस्ट हटाने पर सहमति जताई। दोनों पोस्ट 24 घंटे में हटाए जाएंगे। कोर्ट ने मामले में सौरव दास, आशुतोष रांका और सीजेपी फाउंडर अभिजीत दीपके को समन भी जारी किया है। साथ ही मेटा और एक्स से कहा कि अगर भविष्य में ऐसे पोस्ट की हूबहू कॉपी दोबारा डाली जाती है और भाटिया शिकायत करते हैं, तो उसे हटाने पर कार्रवाई की जाए। गौरव भाटिया खुद कोर्ट में पेश हुए। उन्होंने कहा कि उनकी तस्वीर के साथ फर्जी

बयान लगाया गया और इसे ऐसे पेश किया गया, जैसे बयान उन्होंने ही दिया हो। ग्राफिक में एक न्यूज एजेंसी के लोगो का भी इस्तेमाल किया गया था। भाटिया ने कहा कि पोस्ट को बड़ी संख्या में लोगों ने देखा है और इससे उनकी छवि को नुकसान हुआ। उनकी याचिका के मुताबिक, विवादित पोस्ट को 1.32 लाख से ज्यादा लोगों ने देखा था। भाटिया ने सीजेपी नेताओं के खिलाफ 2 करोड़ के हर्जाने की मांग की थी। साथ ही ऐसी पोस्ट को दोबारा शेयर करने पर रोक लगाने की मांग की है।

◆भाटिया बोले- तस्वीर के साथ फर्जी बयान लगाया

कोर्ट बोला- बिना जांचे पोस्ट करना सही नहीं

जस्टिस तुषार राव गेडेला ने सुनवाई के दौरान दास और रांका से पूछा कि क्या वे पोस्ट खुद हटाने को तैयार हैं। कोर्ट ने कहा कि विरोध करने के कई तरीके होते हैं, लेकिन बिना जांचे इस तरह किसी पर हमला करना सही नहीं है। कोर्ट ने कहा कि सभी को अपनी बात रखने का अधिकार है, लेकिन उसे सही तरीके से रखना चाहिए। कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर दोनों खुद पोस्ट हटाने को तैयार हैं, तो फिलहाल अदालत को पोस्ट हटाने का आदेश देने की जरूरत नहीं है।

मुंबई-गोवा हाईवे में देरी पर गडकरी बोले- शर्म आती है

एजेंसी, नई दिल्ली। केंद्रीय सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा, 'मुझे मुंबई-गोवा हाईवे के चौड़ीकरण में हो रही देरी को लेकर शर्मिंदगी महसूस होती है। ये काम 2016 तक पूरा होना था, लेकिन 15 साल में सिर्फ 94% ही पूरा हुआ है।' गडकरी ने यह बात पणजी में छह लेन वाले एलिवेटेड रोड कॉरिडोर के उद्घाटन समारोह में कही। उन्होंने कहा, 'हाईवे का काम पूरा होने के बाद मैं इसके उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल नहीं होऊंगा। मैं ऐसे ठेकेदारों को ब्लैकलिस्ट करने का रिकॉर्ड बनाना चाहता हूं।' गडकरी ने 22 जुलाई को राज्यसभा में बताया था कि पिछले 3 साल में नेशनल हाईवे निर्माण में खराब गुणवत्ता वाले काम के लिए 103 ठेकेदार और कंपनियों को ब्लैकलिस्ट किया गया और उन पर जुर्माना लगाया गया।

आपदा से निपटने के लिए दिल्ली में बनेगी आधुनिक और त्वरित प्रतिक्रिया प्रणाली

एजेंसी, नई दिल्ली। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सत्य निकेतन में राहत व बचाव अभियान के दौरान राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ) की त्वरित, साहसपूर्ण और समन्वित कार्रवाई के लिए पूरी एनडीआरएफ टीम के प्रति दिल्लीवासियों की ओर से आभार व्यक्त किया।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने वीरवार को दिल्ली सचिवालय में एनडीआरएफ के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में दिल्ली के लिए एक सशक्त और आधुनिक स्टेट डिजास्टर इमरजेंसी रिस्पांस फोर्स (एसडीईआरएफ) के गठन पर विस्तार से चर्चा हुई। मुख्यमंत्री के निर्देश पर दिल्ली में एसडीईआरएफ के गठन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

इस पहल का उद्देश्य दिल्ली में एक ऐसी प्रशिक्षित, सक्षम और त्वरित प्रतिक्रिया प्रणाली विकसित करना है, जो किसी भी आपदा या आपात स्थिति से प्रभावी ढंग से निपट सके।

◆सीएम बोलीं- आपदा से निपटने के लिए तैयार होगी सक्षम प्रतिक्रिया प्रणाली

हिमाचल के सीबीएसई स्कूलों में हरे रंग की थीम वाली होगी विद्यार्थियों की यूनिफॉर्म

अनिल कुमार शर्मा, भारतेन्दु संवाददाता, शिमला। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में वीरवार को शिक्षा विभाग की बैठक हुई। बैठक में सीबीएसई स्कूलों के शिक्षकों के ड्रेस कोड, विद्यार्थियों की यूनिफॉर्म और स्कूल भवनों के रंगों को अंतिम रूप देने के संबंध में चर्चा की गई।

बैठक में निर्णय लिया गया कि सीबीएसई स्कूलों के विद्यार्थियों की विशिष्ट यूनिफॉर्म हरे रंग की थीम पर आधारित होगी। इन स्कूलों की महिला शिक्षिकाएं हल्के लाइलैक यानी बैंगनी रंग की पोशाक पहनेंगी। पुरुष शिक्षकों के लिए हल्के नीले रंग की पैंट और शर्ट निर्धारित की गई है। सीबीएसई स्कूलों के भवनों को ऑलिव ग्रीन और सैंड बेज रंगों से रंगा जाएगा। शिक्षकों का ड्रेस कोड साफ-सुथरा, औपचारिक, शालीन और पेशेवर होगा। इसमें सहायक वस्तुओं का

◆भवनों को ऑलिव ग्रीन और सैंड बेज रंग से सजाया जाएगा

◆सीबीएसई स्कूलों के ढांचे और सुविधाओं के लिए 85 करोड़ रुपए जारी करेगी सरकार : सुक्खू

न्यूनतम इस्तेमाल किया जाएगा। ड्यूटी के दौरान शिक्षकों के लिए अपना पहचान पत्र पहनना अनिवार्य होगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार विद्यार्थियों को उनके घर के नजदीक गुणवत्तापूर्ण शैक्षणिक सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि सरकार ने सीबीएसई स्कूलों में आवश्यक आधारभूत ढांचे के विकास और विद्यार्थियों तथा शिक्षकों के लिए सुविधाओं को मजबूत करने के लिए 80 करोड़ रुपए जारी किए हैं। इन स्कूलों के लिए अतिरिक्त पांच करोड़ रुपये भी जारी किए जाएंगे।

युवा रोजगार मांगने वाले नहीं, रोजगार देने वाले बनें : नवीन

हल्द्वानी में भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन व मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने युवाओं से किया संवाद

एजेंसी, हल्द्वानी। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने युवाओं से राजनीति और सार्वजनिक जीवन में आगे आने और राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि बदलती अर्थव्यवस्था व तकनीक के दौर में युवाओं के लिए संभावनाओं के नए द्वार खुले हैं। आज का युवा केवल रोजगार प्राप्त करने वाला नहीं, बल्कि रोजगार और नए अवसरों का सृजन करने वाला भी बन रहा है।

अध्यक्ष नितिन नवीन ने हल्द्वानी में आयोजित युवा संवाद कार्यक्रम में युवाओं से करियर, रोजगार, उद्यमिता, कौशल विकास, तकनीक, खेल और उत्तराखंड के भविष्य से जुड़े विभिन्न विषयों पर संवाद किया। इस दौरान युवाओं ने रोजगार, स्वरोजगार और प्रदेश में बेहतर अवसरों से जुड़े सवाल पूछे तथा सरकार की योजनाओं को लेकर अपने अनुभव और सुझाव

साझा किए। भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश की युवा शक्ति को नई दिशा देने के साथ युवाओं के लिए नए अवसर सृजित किए जा रहे हैं।

डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया और खेलो इंडिया जैसी पहलों ने युवाओं को अपनी प्रतिभा और कौशल के अनुरूप आगे बढ़ने का मंच दिया है।

उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्टार्टअप, नवाचार और डिजिटल तकनीक जैसे क्षेत्रों में संभावनाएं बढ़ रही हैं। उत्तराखंड के युवा प्रतिभा और क्षमता से भरपूर हैं तथा उनकी ऊर्जा को प्रदेश के विकास से जोड़कर राज्य को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया जा सकता है। अध्यक्ष नवीन ने कहा कि उत्तराखंड जैसे पर्वतीय राज्य में स्थानीय स्तर पर रोजगार, स्वरोजगार, पर्यटन, कौशल विकास और उद्यमिता के अवसर बढ़ाना महत्वपूर्ण है। युवाओं के विचार और आकांक्षाएं प्रदेश के भविष्य की दिशा तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। उन्होंने युवाओं से भविष्य की चुनौतियों को अवसरों में बदलने और विकसित भारत के निर्माण में सक्रिय भागीदारी करने का आह्वान किया। उन्होंने सोशल मीडिया के सकारात्मक उपयोग पर जोर देते हुए कहा कि यह एक सशक्त माध्यम है। विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए सभी देशवासियों को एकजुट होकर कार्य करना होगा।

युवा शक्ति देश व उत्तराखंड की सबसे बड़ी ताकत : धामी

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि युवा शक्ति देश और उत्तराखंड की सबसे बड़ी ताकत है। उनकी सरकार ने चार जुलाई 2021 को जिम्मेदारी संभालने के बाद इस संकल्प के साथ काम किया कि 'पहाड़ की जवानी और पहाड़ का पानी, दोनों उत्तराखंड के काम आएं।' धामी ने कहा कि सरकारी विभागों में रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया को तेजी से आगे बढ़ाया गया है और अब तक करीब 34 हजार युवाओं को सरकारी सेवाओं में नियुक्ति दी जा चुकी है। भर्ती परीक्षाओं में अनियमितता करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की गई है।

35 लाख खातों में पहुंचे पेंशन-भत्तों के 1129 करोड़

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बोले-कांग्रेसियों ने काले कपड़े पता नहीं क्यों पहने

एजेंसी, पंचकूला। हरियाणा में 35 लाख लोगों के खाते में वीरवार को पैसे आए। ये पैसे बुढ़ापा-विधवा पेंशन, लाडो लक्ष्मी योजना और भावांतर भरपाई समेत 15 सरकारी योजनाओं के थे। कुल 1129 करोड़ रुपए सीधे खातों में ट्रांसफर हुए।

चंडीगढ़ में सीएम नायब सैनी ने बताया कि दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना की 11वीं किस्त जारी कर दी गई है। इसके तहत 10 लाख 10 हजार लाभार्थी महिलाओं के खाते में 212 करोड़ रुपए डाले गए। योजना की 11 किस्तों में कुल 2,254 करोड़ रुपए दिए जा चुके हैं। मीडिया से बातचीत में सीएम ने मानसून सेशन में कांग्रेस विधायकों के काले कपड़े पहनकर आने पर तंज किया। बोले-पता नहीं क्यों काले कपड़े पहने, जबकि भाजपा की सरकार बहुत अच्छे काम कर रही है।

4,520 परिवारों को दयालु योजना में 168 करोड़

सीएम ने बताया कि दयालु योजना के तहत 4520 परिवारों को 168 करोड़ 13 लाख 21 हजार की सहायता राशि दी गई। इसमें दयालु योजना-2 के 70 परिवार भी शामिल हैं। बता दें कि दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना योजना परिवार के कमाने वाले सदस्य की मृत्यु या स्थायी दिव्यांगता होने पर आर्थिक मदद देने के लिए है।

उद्योगों के 670 लाभार्थियों को 311 करोड़ रुपए

उद्योग व वाणिज्य विभाग की विभिन्न योजनाओं के तहत 670 लाभार्थियों को 311.25 करोड़ की प्रोत्साहन राशि जारी की गई। उद्यम एवं रोजगार नीति, प्लग एंड प्ले, टेक्सटाइल समेत दूसरे उद्योगों के लिए जारी योजनाओं के तहत ये राशि दी गई। वहीं, हर घर-हर गृहिणी योजना के तहत 5 लाख महिलाओं के खातों में जुलाई की 19 करोड़ 68 लाख सब्सिडी डाली गई। योजना में पात्र महिलाओं को हर महीने 500 में गैस सिलेंडर दिया जाता है।

6,177 किसानों को 49.89 करोड़

सीएम ने बताया कि कई बार किसान को भारी नुकसान होता है, जितने का माल आता उतने का बिकता भी नहीं। वो इसे मंडी में भी नहीं ले जा पाता। इसी के चलते भावांतर भरपाई योजना के तहत 6,177 किसानों को 49 करोड़ 89 लाख दिए गए। इसमें आलू के 6,012, फूलगोभी के 99 और शहद के 66 किसान शामिल हैं। इस योजना के तहत अगर किसान की तय फसल सरकार द्वारा निर्धारित संरक्षित मूल्य से कम भाव पर बिकती है।

जयंती पंडित गोविंद बल्लभ पंत की 139वीं जयंती पर मुख्यमंत्री ने दी श्रद्धांजलि, योगदान को किया नमन

राष्ट्र निर्माण में गोविंद का योगदान अविस्मरणीय: योगी

एजेंसी, लखनऊ। महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, देश के पूर्व गृहमंत्री व उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री भारत रत्न पंडित गोविंद बल्लभ पंत की 139वीं जयंती पर वीरवार को लोकभवन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनकी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी।

मुख्यमंत्री ने पंडित गोविंद बल्लभ पंत के स्वतंत्रता आंदोलन, राष्ट्र निर्माण व उत्तर प्रदेश के विकास में योगदान का उल्लेख करते हुए उनकी स्मृतियों को नमन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री पंडित गोविंद वल्लभ पंत की पावन जयंती है। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश सरकार व प्रदेश की जनता की ओर से वह पंत की स्मृतियों को नमन करते हुए उन्हें

विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि पंडित गोविंद बल्लभ पंत महान अधिवक्ता होने के साथ-साथ प्रमुख स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। वर्ष 1925 में काकोरी ट्रेन एक्शन के बाद ब्रिटिश हुकूमत ने क्रांतिकारियों के खिलाफ जो अभियोग दर्ज किया था, उसके खिलाफ क्रांतिकारियों की पैरवी मजबूती के साथ करने वाले महान नेताओं में पंडित गोविंद बल्लभ पंत प्रमुख थे।

उन्होंने देश की आजादी के आंदोलन में बढ़-चढ़कर भाग लिया। योगी ने कहा कि वर्ष 1937 में पंत को यूपी के प्रीमियर के रूप में चुना गया, लेकिन कुछ समय बाद उन्होंने पद से इस्तीफा देकर स्वाधीनता आंदोलन में अपनी सक्रिय भूमिका जारी रखी। भारत छोड़ो आंदोलन समेत समय-समय पर हुए स्वतंत्रता संग्राम के विभिन्न बड़े आंदोलनों में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।

प्रथम मुख्यमंत्री के रूप में सुशासन की रखी नींव

मुख्यमंत्री ने कहा कि 1947 में देश की आजादी के साथ पंडित गोविंद बल्लभ पंत उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री बने। उस समय उत्तराखंड भी उत्तर प्रदेश का हिस्सा था। ऐसे में इतने बड़े राज्य की व्यवस्था को सुशासन के मॉडल के रूप में प्रस्तुत करने के साथ ही आर्थिक उन्नयन और समाज के प्रत्येक वर्ग के हितों के लिए उन्होंने काम किया। पंत ने अनेक महत्वपूर्ण सुधार किए। उनके द्वारा प्रस्तुत लैंड रिफॉर्म मॉडल भी महत्वपूर्ण रहा। योगी ने कहा कि वर्ष 1954 में पंडित गोविंद बल्लभ पंत देश के गृह मंत्री बने। गृह मंत्री के रूप में उन्होंने देश के भीतर चल रहे भाषाई संघर्ष और समाज में नए विभाजन की नींव डालने के प्रयासों का सूझ-बूझ के साथ समाधान निकाला। हिंदी को राजभाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने में भी उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

अप्रेंटिसशिप आधारित डिग्री से बढ़ेंगे रोजगार के अवसर : रोहित ठाकुर

16 राजकीय महाविद्यालयों में एईडीपी लागू, विद्यार्थियों को छह माह की अप्रेंटिसशिप अनिवार्य

अनिल कुमार शर्मा, भारतेन्दु संवाददाता, शिमला। अप्रेंटिसशिप एम्बेडेड डिग्री प्रोग्राम (एईडीपी) को शैक्षणिक सत्र 2026-27 से प्रदेश के 16 राजकीय महाविद्यालयों में लागू करने की दिशा में उच्च शिक्षा विभाग ने महत्वपूर्ण कदम उठाया है। विभाग ने बोर्ड ऑफ अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग-उत्तरी क्षेत्र, कानपुर (बीओएटी-एनआर) के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर की उपस्थिति में बीओएटी-एनआर के निदेशक विवेक कुमार तथा संबंधित 16 महाविद्यालयों के प्रधानाचार्यों ने समझौते पर हस्ताक्षर किए।

शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि इस पहल का मुख्य उद्देश्य कक्षा में मिलने वाली शिक्षा और उद्योगों की आवश्यकताओं के बीच की दूरी को कम करना है। एईडीपी के माध्यम से विद्यार्थियों को मान्यता प्राप्त स्नातक डिग्री के साथ वास्तविक कार्यस्थल का व्यावहारिक अनुभव भी मिलेगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार कौशल आधारित शिक्षा को बढ़ावा देने और युवाओं के लिए रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध करवाने पर विशेष ध्यान दे रही है।

उन्होंने बताया कि एईडीपी के तहत विद्यार्थी बैंकिंग, वित्तीय सेवाएं एवं बीमा, खुदरा संचालन प्रबंधन तथा लॉजिस्टिक्स जैसे उद्योग-केंद्रित विषयों में अध्ययन करेंगे। पाठ्यक्रम के साथ कम से कम छह महीने की अनिवार्य अप्रेंटिसशिप भी होगी। विद्यार्थियों को प्रतिमाह न्यूनतम 10,900 रुपये का सुनिश्चित वजीफा दिया जाएगा। इससे उन्हें पढ़ाई के साथ कार्यस्थल का अनुभव हासिल करने और उद्योग की जरूरत के अनुसार व्यावहारिक कौशल विकसित करने का अवसर मिलेगा।

तीन उद्योग-केंद्रित कार्यक्रम शुरू : शिक्षा मंत्री ने कहा कि एईडीपी के तहत पांच पाठ्यक्रमों को लागू करने की मंजूरी दी गई है। पहले चरण में 16 राजकीय महाविद्यालयों में तीन कार्यक्रम शुरू किए गए हैं। इनमें बीकॉम बैंकिंग, वित्तीय सेवाएं एवं बीमा, बीकॉम खुदरा संचालन प्रबंधन तथा बीकॉम लॉजिस्टिक्स शामिल हैं। बीकॉम बीएफएसआई का संचालन 11 महाविद्यालयों, बीकॉम खुदरा संचालन प्रबंधन का दो तथा बीकॉम लॉजिस्टिक्स का तीन महाविद्यालयों में किया जा रहा है। पहले वर्ष में इन तीनों कार्यक्रमों में कुल 685 विद्यार्थियों ने प्रवेश लिया है।

उन्होंने कहा कि बीओएटी-एनआर के साथ हुआ समझौता उद्योगों के साथ शैक्षणिक संस्थानों के संबंधों को मजबूत करेगा और विद्यार्थियों के लिए अप्रेंटिसशिप के अवसर उपलब्ध करवाने में मदद करेगा। इसका लाभ विशेष रूप से ग्रामीण और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के विद्यार्थियों को मिलेगा। उन्हें कार्यस्थल का अनुभव, उद्योग आधारित कौशल और बेहतर रोजगार की संभावनाएं प्राप्त होंगी।

आने वाले वर्षों में होगा विस्तार : रोहित ठाकुर ने कहा कि एईडीपी के सफल क्रियान्वयन से आने वाले वर्षों में अधिक विद्यार्थियों को इन कार्यक्रमों से जोड़ा जाएगा। महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों, बीओएटी-एनआर और सीआरआईएसपी के सहयोग से उद्योगों से संपर्क, प्रशिक्षण, अप्रेंटिसशिप और रोजगार सहायता उपलब्ध करवाई जा रही है।

उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के बाद देश का तीसरा राज्य है, जहां इस प्रकार के अप्रेंटिसशिप आधारित डिग्री कार्यक्रम शुरू किए गए हैं। विद्यार्थियों से मिल रही सकारात्मक प्रतिक्रिया को देखते हुए इन कार्यक्रमों का विस्तार अन्य महाविद्यालयों तक करने की संभावनाओं पर काम किया जाएगा। बीए और बीएससी जैसे अन्य स्नातक पाठ्यक्रमों में भी अप्रेंटिसशिप आधारित कार्यक्रम शुरू करने का अध्ययन किया जाएगा।

शिक्षा मंत्री ने बताया कि प्रदेश के 21 राजकीय महाविद्यालयों में खुदरा प्रबंधन तथा पर्यटन एवं आतिथ्य के बीवॉक कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। इन पाठ्यक्रमों में बेहतर रोजगार परिणामों को देखते हुए सरकार ने इनके विस्तार का निर्णय लिया है।

दो बसों पर फ्लीट नियम, वास्तविक रूट और सीटों से तय होगा मोटर कर

भारतेन्दु संवाददाता, शिमला। हिमाचल प्रदेश सरकार ने मोटर वाहन नियमों में संशोधन का प्रारूप जारी कर एक ही मालिक की दो या इससे अधिक समान श्रेणी की बसों को 'यान फ्लीट' के रूप में परिभाषित करने का प्रस्ताव रखा है। इस संबंध में सरकार ने आम लोगों से 30 दिन के भीतर सुझाव और आपत्तियां मांगी हैं। प्रस्तावित संशोधन के बाद फ्लीट में शामिल प्रत्येक बस पर मोटर वाहन कर उसके वास्तविक संचालन वाले मार्ग और सीट क्षमता के आधार पर निर्धारित किया जाएगा।

नियमों में बदलाव का प्रस्ताव : हिमाचल प्रदेश मोटर यान नियम, 1999 में संशोधन के लिए जारी प्रारूप के अनुसार यदि किसी एक व्यक्ति या संस्था के नाम पर समान श्रेणी की दो या अधिक बसें पंजीकृत हैं और वे निर्धारित मार्गों पर संचालित होती हैं, तो उन्हें सामूहिक रूप से 'यान फ्लीट' माना जाएगा। यह व्यवस्था मंजिली बस, संविदा बस और सरकार की ओर से अधिसूचित अन्य परिवहन श्रेणियों के वाहनों पर लागू हो सकती है। हालांकि फ्लीट में शामिल प्रत्येक बस के लिए कर की गणना अलग-अलग की जाएगी।

वास्तविक रूट और सीट क्षमता बनेगा आधार : प्रस्तावित व्यवस्था में मोटर वाहन कर तय करने के लिए बस के वास्तविक संचालन वाले मार्ग को महत्वपूर्ण आधार बनाया जाएगा। यानी केवल कागजों में दर्ज या निर्धारित रूट की लंबाई के बजाय बस वास्तव में जितनी दूरी तय कर रही है, उसी के आधार पर कर की गणना की जाएगी। इसके साथ बस में उपलब्ध सीटों की संख्या भी कर निर्धारण में शामिल होगी। इससे बस संचालकों पर कर का निर्धारण वास्तविक संचालन और यात्री क्षमता के अनुरूप करने का प्रयास किया गया है।

30 दिन में मांगे सुझाव : सरकार ने प्रस्तावित नियमों पर आम जनता, बस संचालकों और संबंधित पक्षों से सुझाव एवं आपत्तियां आमंत्रित की हैं। इसके लिए 30 दिन की अवधि निर्धारित की गई है। इस अवधि में प्राप्त सुझावों और आपत्तियों पर विचार करने के बाद सरकार संशोधन को अंतिम रूप देगी। प्रस्तावित बदलाव लागू होने के बाद परिवहन विभाग को बसों के वास्तविक संचालन, रूट और सीट क्षमता के आधार पर कर निर्धारण में सुविधा मिलने की उम्मीद है।

मध्यस्थता अभियान से लंबित न्यायिक मामलों के त्वरित समाधान की उम्मीद बढ़ी

भारतेन्दु संवाददाता, शिमला। हिमाचल प्रदेश में लंबित मामलों के सौहार्दपूर्ण और शीघ्र निपटारे के उद्देश्य से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण शिमला की ओर से 'मीडिएशन फॉर द नेशन 3.0' के तहत विशेष मध्यस्थता अभियान 3.0 चलाया जा रहा है। मुख्य न्यायाधीश, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय एवं मुख्य संरक्षक, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के मार्गदर्शन में प्रदेशभर में संचालित इस अभियान के तहत लोगों को मध्यस्थता के माध्यम से विवादों का समाधान करने के लिए जागरूक किया जा रहा है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण शिमला के सचिव उमेश वर्मा ने बताया कि हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार जिले में अभियान को प्रभावी ढंग से लागू किया जा रहा है।

न्यायिक अधिकारियों को उपयुक्त मामले चिन्हित करने के निर्देश : उमेश वर्मा ने बताया कि 13 अगस्त 2026 को मुख्य न्यायाधीश एवं कार्यकारी अध्यक्ष, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में अभियान की निगरानी और समन्वय के लिए राज्य, उच्च न्यायालय, जिला तथा उपमंडल स्तर पर नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। जिला एवं सत्र न्यायाधीश को संबंधित सिविल एवं सत्र मंडल में अभियान का प्रभारी बनाया गया है। उन्होंने बताया कि सभी न्यायिक अधिकारियों को ऐसे मामलों की पहचान करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है, जिनका मध्यस्थता के माध्यम से प्रभावी और सौहार्दपूर्ण समाधान संभव है। चिन्हित मामलों को मध्यस्थता के लिए भेजा जाएगा। इन मामलों को न्यायालय की कारण सूची में 'मध्यस्थता के लिए रैफरल- मीडिएशन फॉर द नेशन 3.0' शीर्षक के अंतर्गत अलग से दर्शाने की व्यवस्था की गई है।

अधिवक्ताओं से भी अभियान में सहयोग की अपील : अभियान को सफल बनाने के लिए बार एसोसिएशनों और अधिवक्ताओं को भी सक्रिय रूप से जोड़ा जा रहा है। सचिव ने बताया कि अधिवक्ताओं के साथ-साथ बीमा कंपनियों और वित्तीय संस्थानों का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिवक्ताओं को भी उपयुक्त मामलों की पहचान कर उन्हें मध्यस्थता के माध्यम से निपटाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है।

> **जिला** विधिक सेवा प्राधिकरण शिमला के सचिव उमेश वर्मा ने आमजन, अधिवक्ताओं और वादकारियों से अपील की कि वे लंबित मामलों के जल्द और सौहार्दपूर्ण निपटारे के लिए मध्यस्थता प्रक्रिया का अधिक से अधिक लाभ उठाएं। उन्होंने कहा कि कई विवादों का समाधान आपसी बातचीत और सहमति से किया जा सकता है, जिससे पक्षकारों को लंबे समय तक न्यायिक प्रक्रिया में रहने से राहत मिल सकती है।

ज्वालामुखी में आंगनवाड़ी पदों के लिए फिर आवेदन आमंत्रित

भारतेन्दु संवाददाता, देहरा। बाल विकास परियोजना देहरा के अंतर्गत उपमंडल ज्वालामुखी में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के एक और सहायिका के तीन रिक्त पदों के लिए पुन: आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता का पद कमलोटा पंचायत के लाहसन केंद्र तथा सहायिका के पद कोपड़ा पंचायत के ठेहड़ा, गाहलियां के भगौर-1 और डोला खरियाणा के डोला केंद्र में रिक्त हैं। पात्र महिला उम्मीदवार 24 सितंबर, 2026 को शाम पांच बजे तक बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय देहरा में आवेदन जमा कर सकती हैं। आवेदिका संबंधित आंगनवाड़ी केंद्र के सर्वे क्षेत्र की निवासी, 18 से 35 वर्ष आयु की और न्यूनतम बारहवीं पास होनी चाहिए। परिवार की वार्षिक आय 50 हजार रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। चयन साक्षात्कार के आधार पर होगा, जिसके लिए 25 अंक निर्धारित हैं। पहले आवेदन कर चुकी पात्र महिलाओं को दोबारा आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है।

26 साल बाद शिमला जिला परिषद पर भाजपा का कब्जा

भारतेन्दु संवाददाता, शिमला। शिमला जिला परिषद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के चुनाव में भाजपा समर्थित प्रत्याशियों ने जीत दर्ज कर 26 वर्ष बाद दोनों शीर्ष पदों पर कब्जा कर लिया। चंदलोग-नेरूवा वार्ड से निर्वाचित भूपेंद्र सिंह सिसोदिया अध्यक्ष तथा टिक्कर वार्ड से निर्वाचित भरत सिंह कलांटा उपाध्यक्ष चुने गए। अध्यक्ष पद के चुनाव में सिसोदिया को 13 मत मिले, जबकि कांग्रेस समर्थित सुरेंद्र रेटका को 10 मत प्राप्त हुए और दो मत निरस्त हुए। उपाध्यक्ष पद पर भरत सिंह कलांटा को 14 और कांग्रेस समर्थित मीनाक्षी को 10 मत मिले, जबकि एक मत निरस्त हुआ। जीत के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं ने ढोल-नगाड़ों के साथ जश्न मनाया और नवनिर्वाचित पदाधिकारियों का स्वागत किया।

शिमला में भाजपा की जीत से बदले राजनीतिक समीकरण, कांग्रेस को लगा बड़ा झटका।

हर्ष महाजन ने बताया बड़ा राजनीतिक संदेश : राज्यसभा सांसद हर्ष महाजन ने शिमला जिला परिषद की जीत को प्रदेश की बदलती राजनीतिक परिस्थितियों का स्पष्ट संकेत बताया। उन्होंने कहा कि प्रदेश की 12 जिला परिषदों में से 11 में भाजपा का प्रभाव स्थापित होना अपने आप में बड़ा राजनीतिक संदेश है। महाजन ने कहा कि शिमला कई प्रभावशाली कांग्रेस नेताओं और मंत्रियों का गृह जिला होने के बावजूद कांग्रेस जिला परिषद के दोनों महत्वपूर्ण पद नहीं बचा सकी। उन्होंने दावा किया कि इससे प्रदेश में कांग्रेस सरकार के प्रति बढ़ते असंतोष का अंदाजा लगाया जा सकता है। महाजन ने कहा कि कर्मचारी, युवा, महिलाएं और ग्रामीण क्षेत्रों के लोग सरकार की कार्यप्रणाली से परेशान हैं और इसका असर अब चुनावी परिणामों में दिखाई दे रहा है।

102 दिन बाद चुनाव, भाजपा ने जताई जनता की जीत : राज्यसभा सांसद डॉ. सिकंदर कुमार ने कहा कि 102 दिनों के इंतजार के बाद जिला परिषद को अध्यक्ष और उपाध्यक्ष मिले हैं। उन्होंने भाजपा की जीत को लोकतंत्र और जनता की जीत बताया। डॉ. सिकंदर कुमार ने आरोप लगाया कि जिला परिषद के चुनाव लंबे समय तक टालकर लोकतांत्रिक प्रक्रिया को प्रभावित करने का प्रयास किया गया, लेकिन चुनाव होने पर जनता का रुख परिणामों के माध्यम से सामने आ गया। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस खेमे से भी भाजपा प्रत्याशियों के पक्ष में मतदान हुआ, जो कांग्रेस के भीतर बढ़ती निराशा का संकेत है।

कृष्णानगर में छह ग्राम चिट्टा बरामद, दो युवक गिरफ्तार

अनीश सूद , भारतेन्दु संवाददाता, शिमला। शिमला पुलिस की स्पेशल सेल ने नशे के खिलाफ कार्रवाई करते हुए कृष्णानगर में एक कमरे से करीब छह ग्राम हेरोइन (चिट्टा) बरामद की है। पुलिस ने इस मामले में दो युवकों को गिरफ्तार किया है। दोनों की पहचान सनमजीत सिंह उर्फ सनम (25) और सुमित सपरा (22), दोनों निवासी कृष्णानगर, शिमला के रूप में हुई है।

पुलिस के अनुसार आठ सितंबर को स्पेशल सेल टीम को गुप्त सूचना मिली थी। सूचना के आधार पर टीम ने कृष्णानगर स्थित एक रिहायशी कमरे की तलाशी ली। तलाशी के दौरान दोनों युवकों के संयुक्त कब्जे से करीब छह ग्राम हेरोइन बरामद हुई। पुलिस का कहना है कि नशीले पदार्थ को गोल्ड फ्लैक सिगरेट की डिब्बी में डालकर गद्दे के नीचे छिपाकर रखा गया था।

मामले में पुलिस थाना सदर शिमला में प्राथमिकी संख्या 119/2026 दर्ज की गई है। दोनों आरोपितों के खिलाफ स्वापक औषधि एवं मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम की धारा 21 और 29 के तहत मामला दर्ज किया गया है। गिरफ्तारी के बाद दोनों को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें तीन दिन के पुलिस हिरासत रिमांड पर भेज दिया गया। पुलिस ने बताया कि मामले की आगामी जांच जारी है। जांच के दौरान नशीले पदार्थ की आपूर्ति और आरोपितों की अन्य संभावित गतिविधियों के संबंध में जानकारी जुटाई जा रही है।

लोकतांत्रिक जनादेश का सम्मान करने की दी सलाह

शिमला जिला परिषद जीत पर जयराम ने सुक्खू सरकार को घेरा

अनिल कुमार शर्मा, भारतेन्दु संवाददाता, शिमला। पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने शिमला जिला परिषद के अध्यक्ष पद पर भूपेंद्र सिंह सिसोदिया और उपाध्यक्ष पद पर भारत सिंह कलांटा की जीत पर बधाई दी। उन्होंने इस जीत को लोकतंत्र और जनादेश की जीत बताते हुए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पर तीखा हमला बोला। जयराम ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री की ओर से सत्ता के कथित दुरुपयोग और विभिन्न हथकंडों के बावजूद भाजपा समर्थित प्रत्याशियों की जीत हुई है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने जिला परिषद सदस्यों पर दबाव बनाने और उन्हें विभिन्न मामलों में फंसाने की कोशिश की, लेकिन कोई भी प्रयास सफल नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि इस परिणाम से संविधान, लोकतंत्र और जनादेश का सम्मान करने का संदेश मिला है।

मुख्यमंत्री को हार से सबक लेने की नसीहत : नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि मुख्यमंत्री को पंचायत चुनावों में लगातार मिल रही हार से सबक लेना चाहिए। उनके अनुसार सरकार को मनमाने नियम बनाने और न्यायालय में कानूनी लड़ाई लड़ने के बजाय प्रदेश हित में अपनी ऊर्जा और समय लगाना चाहिए। उन्होंने दावा किया कि पंचायती राज और स्थानीय निकायों के चुनावों को लेकर सरकार को कई बार न्यायालय में असहज स्थिति का सामना करना पड़ा है। जयराम ठाकुर ने कहा कि शिमला जिला परिषद के चुनाव भी उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित तिथि पर हुए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि यदि सरकार के हाथ में होता तो यह चुनाव और टल सकते थे। उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था संविधान के अनुसार चलती है, किसी व्यक्ति की मनमानी के अनुसार नहीं।

रोहड़ू टैक्सी किराया विवाद में महिला से मिला पांच ग्राम चिट्टा

अनीश सूद, भारतेन्दु संवाददाता, शिमला। नशे के अवैध कारोबार और तस्करी के खिलाफ शिमला पुलिस का अभियान लगातार जारी है। इसी कड़ी में पुलिस थाना रोहड़ू की टीम ने एक महिला के कब्जे से पांच ग्राम चिट्टा (हेरोइन) बरामद किया है। पुलिस ने महिला के खिलाफ मामला दर्ज कर नियमानुसार कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार नौ सितंबर 2026 को एक महिला यात्री द्वारा टैक्सी का किराया नहीं चुकाने के संबंध में सूचना मिली थी। सूचना मिलने के बाद रोहड़ू पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की। जांच के दौरान पुलिस को महिला की गतिविधियों पर संदेह हुआ। इसके बाद नियमानुसार उसकी तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान महिला के कब्जे से पांच ग्राम चिट्टा बरामद हुआ। पुलिस ने महिला की पहचान नवीनलता (21) पुत्री नरेश कुमार, निवासी जुब्बल, जिला शिमला के रूप में की है। मामले में पुलिस थाना रोहड़ू में अभियोग संख्या 102/2026, दिनांक नौ सितंबर 2026 दर्ज किया गया है।

हिमाचल प्रदेश युवा कांग्रेस के नवनियुक्त प्रदेश महासचिव (संगठन) आर्यन चौहान ने शिमला में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू से की मुलाकात।

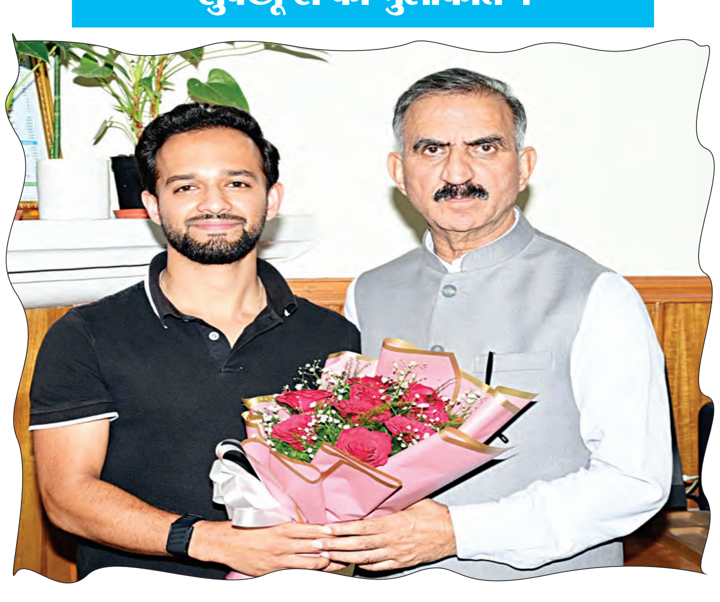

विजय 11 में 10 जिला परिषदों में भाजपा के अध्यक्ष-उपाध्यक्ष हुए निर्वाचित

जिला परिषद जीत से भाजपा ने दिया सत्ता परिवर्तन का संकेत

अनिल कुमार शर्मा, भारतेन्दु संवाददाता, शिमला। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल ने जिला परिषद शिमला के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद पर भाजपा की जीत को ऐतिहासिक करार दिया। उन्होंने कहा कि इस परिणाम ने प्रदेश की बदलती राजनीतिक परिस्थितियों का स्पष्ट संकेत दिया है। बिंदल के अनुसार, जनता का कांग्रेस सरकार से मोहभंग हो चुका है और आने वाले समय में भाजपा के पक्ष में जनसमर्थन बढ़ेगा। उन्होंने दावा किया कि मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने चुनाव में अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी और कई मंत्रियों को जिम्मेदारी सौंपी गई थी, लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस दोनों पदों पर जीत हासिल नहीं कर सकी।

कार्यकर्ताओं की मेहनत को बताया जीत की वजह : भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने जिला शिमला के नेताओं, पदाधिकारियों, निर्वाचित प्रतिनिधियों और कार्यकर्ताओं को जीत की बधाई दी। उन्होंने कहा कि भाजपा कार्यकर्ताओं ने विपरीत परिस्थितियों में संगठन के प्रति निष्ठा और एकजुटता बनाए रखी। बिंदल ने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में कर्मचारी, युवा, महिलाएं, किसान-बागवान और आम नागरिक परेशान हैं तथा सरकार पर आर्थिक बोझ बढ़ाने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जिला परिषदों के चुनाव परिणाम प्रदेश की आगामी राजनीतिक दिशा का संकेत दे रहे हैं। जनता कांग्रेस सरकार की नीतियों और कार्यप्रणाली का जवाब लोकतांत्रिक तरीके से दे रही है। उन्होंने विश्वास जताया कि आने वाले समय में भाजपा के पक्ष में जनसमर्थन और मजबूत होगा।

सत्ता के दबाव के बावजूद भाजपा ने दर्ज की जीत

डॉ. बिंदल ने आरोप लगाया कि जिला परिषद चुनाव में कांग्रेस ने सत्ता और प्रशासनिक प्रभाव का इस्तेमाल कर अपने प्रत्याशियों को जिताने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि तमाम दबावों के बावजूद भाजपा के निर्वाचित प्रतिनिधि और कार्यकर्ता एकजुट रहे और दोनों महत्वपूर्ण पदों पर जीत हासिल की। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में अंततः जनमत और जनविश्वास ही सर्वोपरि होता है। बिंदल ने बताया कि प्रदेश की 12 जिला परिषदों में से अब तक 11 के चुनाव संपन्न हुए हैं और इनमें 10 जिला परिषदों में भाजपा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। उन्होंने इसे कांग्रेस सरकार के खिलाफ जनता के स्पष्ट जनमत का संकेत बताया।

नेरचौक विद्युत उपमंडल ने बकाया बिलों को लेकर दी चेतावनी

मंडी। हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड के नेरचौक विद्युत उपमंडल ने सभी उपभोक्ताओं से अपने पुराने लंबित बिजली बिलों का शीघ्र भुगतान करने की अपील की है। विद्युत बोर्ड की ओर से जारी प्रेस नोट में उपभोक्ताओं को सूचित किया गया है कि वे 15 सितंबर 2026 से पहले अपने पुराने बकाया बिजली बिल जल्द से जल्द जमा करवा दें।

◆ **पुराने लंबित बिजली बिल 15 सितंबर तक जमा करने की अपील**

बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित समय सीमा के भीतर लंबित बिल का भुगतान नहीं करने वाले उपभोक्ताओं के खिलाफ नियमानुसार उचित कार्रवाई की जाएगी। विद्युत विभाग ने उपभोक्ताओं से आग्रह किया है कि वे किसी भी प्रकार की असुविधा से बचने के लिए अपने बकाया बिजली बिलों का समय पर भुगतान सुनिश्चित करें। विद्युत बोर्ड ने कहा कि उपभोक्ताओं का सहयोग आवश्यक है, ताकि बिजली आपूर्ति एवं विभागीय सेवाओं को सुचारू रूप से जारी रखा जा सके। बोर्ड की ओर से सभी उपभोक्ताओं से लंबित बिलों का भुगतान प्राथमिकता के आधार पर करने का अनुरोध किया गया है। प्रेस नोट में नेरचौक विद्युत उपमंडल की ओर से उपभोक्ताओं से सहयोग की अपील की गई है। निर्धारित तिथि के बाद बकाया राशि जमा नहीं करने पर विभाग द्वारा नियमों के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

खाद्य सुरक्षा निगरानी में मोबाइल लैब बनी कारगर, जुटाए 1579 नमूने

भारतेन्दु संवाददाता, शिमला। प्रदेश में खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने और मिलावट के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए स्वास्थ्य सुरक्षा एवं विनियमन विभाग की ओर से पांच मोबाइल फूड टेस्टिंग लैबोरेटरी वैन संचालित की जा रही हैं। संयुक्त आयुक्त (खाद्य सुरक्षा)-सह-निदेशक जितेंद्र सांजटा ने बताया कि वर्तमान में ये वैन शिमला, सोलन, कुल्लू, सिरमौर और बिलासपुर जिलों में सेवाएं दे रही हैं। इनके माध्यम से आम जनता और खाद्य कारोबार संचालकों को निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार मौके पर ही खाद्य पदार्थों की जांच की सुविधा मिल रही है।

◆ **मोबाइल लैब से खाद्य मिलावट पर कसा शिकंजा**

मौके पर होती है खाद्य पदार्थों की जांच : मोबाइल लैब में खाद्य सुरक्षा से जुड़े कई मानकों की जांच की जाती है। खाद्य तेल की गुणवत्ता जांचने के लिए टीपीसी मीटर और एसिड वैल्यू का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा रिफ्रैक्टोमीटर से टीएसएस और शुगर की जांच, आयोडीन व स्टार्च की पहचान तथा पानी की पीएच आधारित जांच की जाती है। इससे लोगों को खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता और संभावित मिलावट के बारे में मौके पर जानकारी मिलती है।

अब तक 1579 नमूने एकत्रित : जितेंद्र सांजटा के अनुसार मोबाइल लैब सुविधा से फील्ड स्तर पर खाद्य पदार्थों की सैंपलिंग और जांच में तेजी आई है। अब तक कुल 1579 खाद्य नमूने एकत्रित किए जा चुके हैं। इनमें बिलासपुर से 486, कुल्लू से 62, सिरमौर से 511 और सोलन से 520 नमूने शामिल हैं। व्यापक सैंपलिंग से खाद्य सुरक्षा निगरानी व्यवस्था मजबूत होने के साथ लोगों में खाद्य गुणवत्ता और मिलावट को लेकर जागरूकता भी बढ़ रही है।

सुरक्षित भोजन विभाग की प्राथमिकता : सांजटा ने लोगों से मोबाइल फूड टेस्टिंग लैबोरेटरी की सुविधा का अधिक से अधिक लाभ उठाने की अपील की। उन्होंने कहा कि सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण खाद्य पदार्थ उपलब्ध करवाना विभाग की प्राथमिकता है। मोबाइल वैन का जिला-वार रोस्टर और जांच शिविरों का कार्यक्रम विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है।

न्यूज ब्रीफ

सैंजी-लगा डुमक मार्ग की वन भूमि आपत्ति का होगा निस्तारण

उदित नैनवाल, जिला चमोली । सैंजी-लगा डुमक मोटर मार्ग के वन भूमि हस्तांतरण से जुड़ी आपत्ति का निस्तारण तथ्यों और अभिलेखों के आधार पर किया जाएगा। जिलाधिकारी गौरव कुमार की अध्यक्षता में जिला सभागार में संबंधित विभागों और ग्रामीण प्रतिनिधियों के साथ बैठक हुई। जिलाधिकारी ने वन विभाग, पीएमजीएसवाई और राजस्व विभाग से प्रकरण की अब तक की कार्रवाई की जानकारी ली और सभी पक्षों की चिंताओं को सुना। उन्होंने वर्ष 1920, 1930 और 1956 के पुराने मानचित्रों का अवलोकन कर वन, राजस्व एवं सिविल भूमि की स्थिति का मिलान किया। पीएमजीएसवाई को फाइनल एलाइनमेंट के आधार पर स्पष्ट आख्या देने तथा एसडीएम जोशीमठ को आवश्यक राजस्व कार्रवाई के निर्देश दिए गए। उन्होंने सभी विभागों को समन्वय से शीघ्र समाधान सुनिश्चित करने को कहा।

कर्णप्रयाग के अनुराग ने नीट में चमकाया विद्यालय का नाम

उदित नैनवाल, जिला चमोली । श्री गुरु राम राय पब्लिक स्कूल कर्णप्रयाग ने पूर्व छात्र अनुराग पुरोहित को नीट में शानदार सफलता हासिल करने पर सम्मानित किया। अनुराग ने नीट परीक्षा में 720 में से 655 अंक प्राप्त कर अखिल भारतीय स्तर पर 1202वीं रैंक और 99.93 पर्सेंटाइल हासिल की। चौथे प्रयास में मिली इस सफलता से विद्यालय और क्षेत्र का गौरव बढ़ा है। अनुराग वर्तमान में दून मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस प्रथम वर्ष के छात्र हैं और अब अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान में प्रवेश का लक्ष्य पूरा करने की दिशा में आगे बढ़े हैं। विद्यालय पहुंचकर उन्होंने गुरुजनों का आशीर्वाद लिया और कक्षा 11वीं व 12वीं के विद्यार्थियों को नीट की तैयारी के टिप्स दिए। उन्होंने कठिन परिश्रम, दृढ़ संकल्प और अनुशासन को सफलता का मूलमंत्र बताया। अनुराग ने वर्ष 2022 में विद्यालय से 93.60 प्रतिशत अंकों के साथ 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की थी। सामान्य परिवार से ताल्लुक रखने वाले अनुराग की सफलता में उनकी मां गीता देवी के संघर्ष की महत्त्वपूर्ण भूमिका रही। शिक्षकों ने उन्हें उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दीं।

पॉलीथिन अभियान से नाराज व्यापारियों का धरना प्रदर्शन

अनिल थपलियाल। देहरादून में नगर निगम की पॉलीथिन विरोधी कार्रवाई से नाराज व्यापारियों ने सांकेतिक धरना-प्रदर्शन किया। व्यापारियों ने आरोप लगाया कि छोटे दुकानदारों पर भारी चालान कर अनावश्यक दबाव बनाया जा रहा है। उन्होंने पॉलीथिन के खिलाफ अभियान का समर्थन करते हुए कार्रवाई उत्पादन, सप्लाई और वितरण के स्रोत से शुरू करने की मांग की। व्यापारियों ने चेतावनी दी कि उत्पीड़न जारी रहा तो करीब 11 व्यापारिक संस्थाएं बड़ा आंदोलन करेंगी। जरूरत पड़ने पर मेयर को दुकानों की चाबियां सौंपने की बात भी कही।

खड़गे की आह भाजपा को ले डूबेगी :धीरेंद्र प्रताप

अनिल थपलियाल, देहरादून। उत्तराखंड कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं प्रवक्ता धीरेंद्र प्रताप ने हल्द्वानी छुआछूत कांड को लेकर भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के सार्वजनिक अपमान से उपजी पीड़ा का असर 2027 के विधानसभा चुनाव में भाजपा पर पड़ेगा। डोईवाला विधानसभा क्षेत्र के लालतप्पड़ माजरी बालकुमारी में क्षतिग्रस्त पुल के निर्माण की मांग को लेकर आयोजित धरने में उन्होंने सरकार को चेतावनी दी कि जल्द निर्माण शुरू नहीं हुआ तो कांग्रेस उग्र आंदोलन करेगी। प्रदर्शन में नवीन जोशी, मनीष नागपाल समेत कांग्रेस कार्यकर्ता और स्थानीय लोग मौजूद रहे।

जीआरडी विवि के फ्रेशर्स ने किया ओएनजीसी संग्रहालय का शैक्षणिक भ्रमण

अनिल थपलियाल, देहरादून। जीआरडी उत्तराखंड विश्वविद्यालय के प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए ओएनजीसी सुबीर राहा ऑयल म्यूजियम का शैक्षणिक भ्रमण आयोजित किया गया। विद्यार्थियों ने संग्रहालय में तेल एवं प्राकृतिक गैस क्षेत्र, ऊर्जा संसाधनों, तकनीकी विकास और ओएनजीसी के योगदान की जानकारी ली। भ्रमण से विद्यार्थियों को कक्षा से बाहर अनुभवात्मक अधिगम का अवसर मिला और उन्होंने अपने शैक्षणिक ज्ञान को वास्तविक दुनिया से जोड़कर समझा। कार्यक्रम विश्वविद्यालय के पदाधिकारियों के मार्गदर्शन में आयोजित हुआ।

17 सितंबर को हरिपुर में यमुनाघाट का लोकार्पण करेंगे सीएम धामी

हरिपुर बनेगा मैदानी क्षेत्र का प्रवेश द्वार, प्रधानमंत्री मोदी के नाम होगी पहली आरती

◆ यमुनाघाट हरिपुर के विकास को देगा नई दिशा

भारतेंदु संवाददाता, देहरादून

कालसी क्षेत्र के हरिपुर में 17 सितंबर को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के पहले विकसित यमुनाघाट का लोकार्पण करेंगे। विश्वकर्मा दिवस और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के जन्मदिवस के अवसर पर आयोजित होने वाले कार्यक्रम में यमुना तट पर स्थापित मां यमुना की प्रतिमा का भी लोकार्पण प्रस्तावित है। इसके साथ ही हरिपुर को धार्मिक और सांस्कृतिक पर्यटन के प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित करने की दिशा में नई शुरुआत होगी। यमुना के पहाड़ी क्षेत्र से मैदानी भूभाग में प्रवेश के महत्वपूर्ण पड़ाव हरिपुर की भौगोलिक स्थिति इसे विशेष बनाती है।

यमुनाघाट और मां यमुना प्रतिमा का होगा लोकार्पण।

यहां यमुना के साथ टौंस, अमलावा और नौरा नदियों का संगम भी क्षेत्र की प्राकृतिक विशेषता है। मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण की ओर से विकसित यमुनाघाट पर स्नान और धार्मिक गतिविधियों से जुड़ी आवश्यक सुविधाएं तैयार की जा रही हैं। स्थानीय मान्यताओं में हरिपुर को 'यमुनाद्वार' और 'यमुना का हरिद्वार' कहा जाता रहा है।

क्षेत्र में प्राचीन समय से यज्ञ, पिंडदान, अस्थि विसर्जन और अन्य धार्मिक संस्कारों की परंपरा रही है। सरकार हरिपुर को धार्मिक पर्यटन के साथ स्थानीय जौनसारी संस्कृति, हस्तशिल्प, पारंपरिक खान-पान और लोककला से जोड़ने की योजना पर भी काम कर रही है। इससे आसपास के ग्रामीणों और युवाओं को रोजगार तथा स्वरोजगार के अवसर मिल सकते हैं।

प्रस्तावित श्रीकृष्ण-यमुना तीर्थ सर्किट में हरिपुर को महत्वपूर्ण पड़ाव के रूप में विकसित करने की संभावनाएं भी हैं। हालांकि पर्यटन विस्तार के साथ यमुना और आसपास के पर्यावरण का संरक्षण जरूरी होगा।

सहकारी बैंक के 12.31 लाख हड़पने वाला अभिकर्ता गिरफ्तार

अनिल थपलियाल, ऋषिकेश। उत्तराखंड को-ऑपरेटिव बैंक में खाताधारकों से जमा कराने के लिए ली गई 12 लाख 31 हजार 458 रुपये की धनराशि बैंक में जमा न कर गबन करने के आरोपी दैनिक जमा अभिकर्ता दीपक बढ़ई को दून पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया।

बैंक के सचिव एवं महाप्रबंधक एसएस राणा ने 24 मई 2026 को कोतवाली ऋषिकेश में तहरीर देकर बताया था कि आरोपी ने विभिन्न तिथियों में खाताधारकों से उक्त धनराशि ली, लेकिन बैंक में जमा नहीं की। तहरीर के आधार पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 316(5) में मुकदमा दर्ज किया गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर पुलिस ने साक्ष्य जुटाए और नौ सितंबर को आरोपी को उदयबाग, विकासनगर से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस आरोपी को न्यायालय में पेश कर रही है। टीम में उपनिरीक्षक विनेश कुमार समेत कांस्टेबल अभिषेक और तेज सिंह शामिल रहे।

पंडित गोविंद बल्लभ पंत के जीवन से लें प्रेरणा: मुख्यमंत्री धामी

◆ पंडित पंत के बताए रास्ते पर चलने का सीएम धामी ने दिया संदेश

भारतेंदु संवाददाता, देहरादून

पंडित गोविंद बल्लभ पंत की जयंती पर पूरे उत्तराखंड में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित कर उन्हें श्रद्धापूर्वक याद किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पंडित पंत को श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए कहा कि उनका जीवन और उनके विचार आज भी समाज और युवा पीढ़ी के लिए प्रेरणास्रोत हैं। उन्होंने कहा कि पंडित पंत हमारे लिए पाथेय हैं और उनके बताए मार्ग पर चलते हुए उत्तराखंड को विकास की सर्वोच्च ऊंचाइयों तक पहुंचाना सरकार का लक्ष्य है। मुख्यमंत्री ने पंडित पंत को प्रखर राजनीतिज्ञ और सच्चा देशभक्त बताते हुए कहा कि उनका महान व्यक्तित्व एवं कृतित्व सदैव देशवासियों का मार्गदर्शन करता रहेगा।

पंत ने देश को नई दिशा दी : सीएम धामी

उन्होंने कहा कि पंत ने देश को नई दिशा देने के साथ ही कुली बेगारी प्रथा और जमींदारी व्यवस्था के उन्मूलन के लिए निर्णायक संघर्ष किया

तथा सामाजिक बुराइयों को समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हिंदी को राजभाषा के रूप में प्रतिष्ठित कराने और उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री तथा देश के गृहमंत्री के रूप में आधुनिक भारत के निर्माण में भी उनका उल्लेखनीय योगदान रहा। पिथौरागढ़ में पंडित पंत की 139वीं जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में जिलाधिकारी आशीष भटगाईं, मुख्य विकास अधिकारी डॉ. दीपक सैनी, विभिन्न संगठनों के पदाधिकारियों और स्वतंत्रता सेनानियों के आश्रितों ने उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान वक्ताओं ने उनके जीवन संघर्ष, राष्ट्र निर्माण में योगदान और सामाजिक सुधार के प्रयासों पर प्रकाश डाला।

> **पंडित** पंत हमारे लिए पाथेय हैं और उनके बताए मार्ग पर चलते हुए उत्तराखंड को विकास की सर्वोच्च ऊंचाइयों तक पहुंचाना सरकार का लक्ष्य है। मुख्यमंत्री ने पंडित पंत को प्रखर राजनीतिज्ञ और सच्चा देशभक्त बताते हुए कहा कि उनका महान व्यक्तित्व एवं कृतित्व सदैव देशवासियों का मार्गदर्शन करता रहेगा। - **मुख्यमंत्री धामी**

देशभक्त बताते हुए कहा कि उनका महान व्यक्तित्व एवं कृतित्व सदैव देशवासियों का मार्गदर्शन करता रहेगा।

राष्ट्र निर्माण में पंत का योगदान अतुलनीय : प्रेमचंद अग्रवाल

पंडित गोविंद बल्लभ पंत को जयंती पर श्रद्धापूर्वक किया नमन।

अनिल थपलियाल

ऋषिकेश। भारत रत्न एवं महान स्वतंत्रता सेनानी पंडित गोविंद बल्लभ पंत की जयंती पर ऋषिकेश विधायक एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉ. प्रेमचंद अग्रवाल ने अपने कैंप कार्यालय में उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धापूर्वक नमन किया। डॉ. अग्रवाल ने कहा कि पंडित पंत का संपूर्ण जीवन राष्ट्रसेवा, त्याग, संघर्ष और जनकल्याण के लिए समर्पित रहा। स्वतंत्रता आंदोलन में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और स्वतंत्रता के बाद राष्ट्र निर्माण में भी उनका योगदान अतुलनीय रहा। उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने प्रशासनिक और सामाजिक क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण कार्य किए। उन्होंने कहा कि पंडित पंत ने देश की एकता, अखंडता और लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत करने के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया।

उनकी राष्ट्रभक्ति, दूरदर्शिता और जनसेवा की भावना आज भी समाज और युवा पीढ़ी के लिए प्रेरणास्रोत है। डॉ. अग्रवाल ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा उन्हें देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया जाना उनके महान योगदान का सम्मान है। उन्होंने सभी से पंडित पंत के आदर्शों और विचारों को आत्मसात कर राष्ट्र एवं समाज के प्रति अपने दायित्वों का निष्ठापूर्वक निर्वहन करने का आह्वान किया। इस अवसर पर सोमपाल, राधेश्याम, विजय रावत, सुमित अग्रवाल, रविंद्र सिंह सहित कई कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

चारधाम यात्रा के दूसरे चरण को लेकर प्रशासन मुस्तैद

शिव सिंह थलवाल

उत्तरकाशी। मानसून के बाद चारधाम यात्रा के दूसरे चरण को सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाने के लिए प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। जिलाधिकारी प्रशांत आर्य ने अधिकारियों की बैठक लेकर यात्रा मार्गों पर व्यवस्थाएं दुरुस्त करने और फील्ड में जाकर स्थलीय निरीक्षण करने के निर्देश दिए। उन्होंने गंगोत्री मार्ग के नगुण, रतूड़ीसेरा, बंदरकोट, चड़ेथी, लिमच्यागाड और पापड़गाड जैसे संवेदनशील स्थानों से मलबा हटाकर यातायात सुचारू रखने को कहा।

यमुनोत्री मार्ग के स्यानाचट्टी, पालीगाड, सिलाईबैंड और औजारी में पर्याप्त मशीनरी व कार्यबल तैनात करने के निर्देश दिए गए। बीआरओ की सुस्त कार्यप्रणाली पर नाराजगी जताते हुए नोटिस जारी करने को कहा गया। दोनों धामों के प्रमुख पड़ावों पर स्वच्छता, पेयजल और शौचालयों की व्यवस्था बेहतर करने के निर्देश दिए गए।

काइनेटिक वॉट्स एंड वोल्ट्स ने हरिद्वार में खोली नई डीलरशिप

अनिल थपलियाल

हरिद्वार में काइनेटिक वॉट्स एंड वोल्ट्स लिमिटेड ने अपनी नई डीलरशिप शुरू करने की घोषणा की है। काइनेटिक इंडिया की इलेक्ट्रिक वाहन इकाई के इस विस्तार से उत्तराखंड में कंपनी का खुदरा नेटवर्क और मजबूत होगा। कंपनी के अनुसार, नई डीलरशिप के माध्यम से ग्राहकों को इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद के साथ बेहतर सेवा सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी। यह कदम देश के उभरते और संभावनाशील बाजारों में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को अधिक सुलभ बनाने की कंपनी की रणनीति का हिस्सा है। उत्तरी भारत में विस्तार के तहत काइनेटिक वॉट्स एंड वोल्ट्स प्रमुख बाजारों में अपने नेटवर्क को मजबूत करने की योजना पर काम कर रही है।

कंपनी पूरे देश में खुदरा और सेवा नेटवर्क का विस्तार कर मजबूत इलेक्ट्रिक वाहन तंत्र तैयार करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। इस अवसर पर डीलर अक्षय वालिया ने कहा कि काइनेटिक वॉट्स एंड वोल्ट्स के साथ साझेदारी करना उनके लिए गर्व की बात है। उन्होंने कहा कि कंपनी की विरासत और इलेक्ट्रिक वाहन क्षेत्र में उसकी पहचान को हरिद्वार तक लाने का अवसर मिला है।

आत्महत्या रोकथाम को लेकर सामाजिक कार्यकर्ताओं को दिया गया प्रशिक्षण

अनिल थपलियाल

देहरादून। विश्व आत्महत्या निषेध जागरूकता दिवस पर फोरगिवनेस फाउंडेशन सोसाइटी की ओर से केदारपुरम में सामाजिक कार्यकर्ताओं के लिए निशुल्क कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला का उद्देश्य सामाजिक कार्यकर्ताओं को आत्महत्या की प्रवृत्ति पहचानने, प्रभावित व्यक्ति से संवेदनशील संवाद करने और समय रहते मदद उपलब्ध कराने के लिए प्रशिक्षित करना रहा। मनोवैज्ञानिक समाजसेवी डॉ. पवन शर्मा ने आत्महत्या से जुड़े विभिन्न पहलुओं और मनोवैज्ञानिक तकनीकों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि तनाव, अकेलापन, आर्थिक परेशानी, खराब स्वास्थ्य, रिश्तों में समस्या, असफल प्रेम संबंध और परीक्षा संबंधी दबाव जैसी परिस्थितियां व्यक्ति को आत्मघाती विचारों की ओर धकेल सकती हैं।

उन्होंने कहा कि किसी व्यक्ति के व्यवहार में जीवन से विरक्ति या निराशा के संकेत दिखाई दें तो उसकी बात को गंभीरता से सुनना चाहिए। बिना निर्णय सुनाए उसे भावनात्मक सहयोग और भरोसे का वातावरण देना जरूरी है। डॉ. शर्मा ने तनाव से बचने, सामाजिक रूप से सक्रिय रहने, स्वस्थ जीवनशैली अपनाने और नशे से दूर रहने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि समय पर मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ से संपर्क कर आत्महत्या की घटनाओं को रोका जा सकता है।

एसएसपी दून के नेतृत्व में नशा तस्करों पर जारी दून पुलिस का प्रहार

देहरादून में 436 ग्राम चरस के साथ तस्कर गिरफ्तार

विकास बलोनी

देहरादून। नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत कोतवाली नगर पुलिस ने 436 ग्राम चरस के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर पुलिस टीम ने नौ सितंबर को सरस्वती सोनी मार्ग स्थित मातावाला बाग के खाली प्लाट के गेट के पास चेकिंग के दौरान प्रमोद कुमार (34) निवासी ग्राम ऐथाई, चांदपुर, बिजनौर को पकड़ा। तलाशी में उसके कब्जे से चरस बरामद हुई। आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है।

पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वह चांदपुर से स्थानीय नशेड़ियों से थोड़ी-थोड़ी मात्रा में चरस सस्ते दामों पर खरीदकर देहरादून लाता था और यहां नशे के आदी लोगों को महंगे दामों पर बेचने की तैयारी में था। पुलिस के अनुसार आरोपी पूर्व में भी आपराधिक मामलों में जेल जा चुका है। उसके आपराधिक इतिहास की जानकारी जुटाई जा रही है। कार्रवाई करने वाली टीम में निरीक्षक कैलाश चंद्र भट्ट, उपनिरीक्षक ज्योति प्रसाद उनियाल समेत पुलिसकर्मी शामिल रहे।

एसएसपी देहरादून।

स्टाइपेंड बढ़ाने के आश्वासन पर आंदोलनरत डॉक्टरों को जल्द निर्णय की उम्मीद

अनिल थपलियाल

देहरादून। इंटर्न और पीजी डॉक्टरों के स्टाइपेंड समेत विभिन्न मांगों को लेकर चल रहे आंदोलन के बीच शासन-प्रशासन ने जल्द सकारात्मक निर्णय का आश्वासन दिया है। आंदोलनरत चिकित्सकों से वार्ता के दौरान अधिकारियों ने बताया कि स्टाइपेंड बढ़ाने को लेकर शासन स्तर पर लगातार विचार-विमर्श चल रहा है। सरकार का प्रयास है कि उत्तराखंड में इंटर्न और पीजी डॉक्टरों को अन्य राज्यों के समकक्ष अथवा उनसे अधिक स्टाइपेंड मिल सके। अधिकारियों ने कहा कि प्रक्रिया में आने वाली प्रशासनिक और तकनीकी अड़चनों को दूर किया जा रहा है। चिकित्सकों से शासन की प्रक्रिया पर भरोसा बनाए रखने की अपील की गई।

इस बीच मरीजों की सुविधाओं का भी ध्यान रखा जा रहा है। अधिकारियों के अनुसार आंदोलन के बावजूद आपातकालीन सेवाएं, आईसीयू और ऑपरेशन थिएटर सामान्य रूप से संचालित हो रहे हैं। बाह्य और भर्ती मरीजों को वरिष्ठ चिकित्सक सेवाएं दे रहे हैं। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि आंदोलन में केवल इंटर्न और पीजी डॉक्टर शामिल हैं। वरिष्ठ चिकित्सकों के हड़ताल पर होने की बात गलत है।

हाशिये के समुदायों की जरूरतों पर हुआ सार्वजनिक संवाद

अनिल थपलियाल, देहरादून। देहरादून में दून पुस्तकालय एवं शोध केन्द्र और साहस फाउंडेशन के संयुक्त तत्वावधान में हाशिये के समुदायों की जरूरतों पर सार्वजनिक संवाद हुआ। वक्ताओं ने कहा कि विकास योजनाओं में स्थानीय परिस्थितियों और समुदायों की वास्तविक आवश्यकताओं को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। स्थानीय ज्ञान आधारित विकेंद्रीकृत मॉडल अपनाने पर जोर दिया गया। कृषि, पलायन, रोजगार और पर्वतीय क्षेत्रों की चुनौतियों पर चर्चा करते हुए जमीनी अनुभवों को नीति निर्माण से जोड़ने की आवश्यकता बताई गई।

पर्वतीय प्रतिभाओं को मंच देने खेल महाकुंभ का हुआ शुभारंभ

मुख्यमंत्री ट्रॉफी में युवा खिलाड़ियों ने जीत के लिए बहाया पसीना

उदित नैनवाल

नारायणबगड़, जिला चमोली । राजकीय आदर्श इंटर कॉलेज नारायणबगड़ के खेल मैदान में बृहस्पतिवार को न्याय पंचायत स्तरीय मुख्यमंत्री ट्रॉफी (खेल महाकुंभ)-2026 का शुभारंभ हुआ। दो दिवसीय प्रतियोगिता में अंडर-14 और अंडर-19 बालक-बालिका वर्ग के खिलाड़ियों ने विभिन्न स्पर्धाओं में उत्साहपूर्वक प्रतिभाग किया। प्रतियोगिता का शुभारंभ ग्राम प्रधान केवर देवेंद्र कोहली ने किया।

पहले दिन दौड़, लंबी कूद, ऊंची कूद, खो-खो और कबड्डी समेत विभिन्न प्रतियोगिताओं में खिलाड़ियों ने अपनी प्रतिभा और खेल कौशल का प्रदर्शन किया। सीनियर बालक वर्ग की 800 मीटर दौड़ में राजकीय इंटर कॉलेज पैंतोली के बबलू ने प्रथम स्थान हासिल किया, जबकि नारायणबगड़ के अमित दूसरे और पैंतोली के हिमांशु तीसरे स्थान पर रहे।

जूनियर बालक वर्ग की 100 मीटर दौड़ में पैंतोली के दिव्यांशु प्रथम, आदित्य द्वितीय और नारायणबगड़ के आयुष तृतीय स्थान पर रहे। खेल महाकुंभ के संयोजक एवं प्रधानाचार्य डॉ. जीएस नेगी ने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करते हुए अधिक से अधिक प्रतिभाग करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि खेल युवाओं में अनुशासन, आत्मविश्वास और खेल भावना विकसित करने के साथ पर्वतीय क्षेत्रों की प्रतिभाओं को आगे बढ़ने का अवसर प्रदान करते हैं।

सरकारी जमीनों की नीलामी के विरोध में सामाजिक संगठनों ने खोला मोर्चा

अनिल थपलियाल

देहरादून। उत्तराखंड में सरकारी जमीनों को नीलामी और दीर्घकालीन लीज के माध्यम से निजी एवं व्यावसायिक उपयोग के लिए दिए जाने के विरोध में विभिन्न सामाजिक एवं जन संगठनों ने मोर्चा खोल दिया है। संगठनों के प्रतिनिधियों ने जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को ज्ञापन भेजकर उत्तराखंड इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बोर्ड को तत्काल भंग करने तथा सरकारी विभागों की जमीनों की बिक्री, नीलामी और लीज पर रोक लगाने की मांग की। वक्ताओं ने करीब सात हजार बीघा सरकारी जमीन से जुड़े प्रस्तावों पर सवाल उठाते हुए आवंटन और लीज की पूरी जानकारी सार्वजनिक करने तथा श्वेतपत्र जारी करने की मांग की। उन्होंने कहा कि निवेश और रोजगार के नाम पर तैयार की जा रही नीतियों में स्थानीय युवाओं, उद्यमियों, महिला समूहों और छोटे कारोबारियों को प्राथमिकता मिलनी चाहिए।

बड़े कॉरपोरेट को लाभ पहुंचाने का लगाया आरोप

वक्ताओं के अनुसार बड़ी आर्थिक शर्तों वाली निविदाओं में सामान्य स्थानीय कारोबारी प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते, जिससे बड़े कॉरपोरेट समूहों को लाभ मिलने की आशंका है। संगठनों ने कहा कि सरकारी भूमि जनता की सामूहिक संपत्ति है और उसका उपयोग व्यापक जनहित में होना चाहिए। उन्होंने पूर्व आवंटनों की समीक्षा और सभी प्रक्रियाओं में पारदर्शिता की मांग की। चेतावनी दी गई कि मांगों पर समयबद्ध सकारात्मक निर्णय नहीं हुआ तो देहरादून से बाहर आंदोलन को प्रदेशव्यापी स्वरूप दिया जाएगा। जल, जंगल और जमीन की रक्षा के लिए विभिन्न संगठनों को साथ लेकर व्यापक जनआंदोलन चलाने की बात कही गई।

पंजाब कांग्रेस बिना सीएम चेहरे के लड़ेगी 2027 का चुनाव

सचिन पायलट ने संगठन मजबूत करने पर दिया जोर, राहुल गांधी संभालेंगे चुनाव अभियान की कमान

भारतेंदु संवाददाता, चंडीगढ़

पंजाब कांग्रेस ने 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर अपनी रणनीति स्पष्ट करनी शुरू कर दी है। पार्टी चुनाव से पहले किसी भी नेता को मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित नहीं करेगी। पंजाब कांग्रेस के नए प्रभारी सचिन पायलट ने साफ किया है कि पार्टी सामूहिक नेतृत्व में चुनाव मैदान में उतरेगी। चुनाव अभियान की अगुवाई राहुल गांधी करेंगे। विधानसभा चुनाव में बहुमत मिलने के बाद ही मुख्यमंत्री के नाम पर फैसला किया जाएगा।

पायलट का यह बयान ऐसे समय आया है, जब पंजाब कांग्रेस में नेतृत्व और संगठन को लेकर लंबे समय से खींचतान की स्थिति बनी हुई है। प्रदेश अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग और पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के बीच राजनीतिक दूरी को लेकर लगातार चर्चा होती रही है। पार्टी के भीतर अलग-अलग नेताओं के समर्थक अपने-अपने नेतृत्व को आगे बढ़ाने की मांग करते रहे हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री का चेहरा पहले घोषित नहीं करने की रणनीति से कांग्रेस ने फिलहाल इस बहस को विराम देने का प्रयास किया है।

एकजुट होकर चुनाव लड़ने पर जोर : सचिन पायलट का मुख्य जोर पंजाब कांग्रेस को एकजुट करने और संगठन को मजबूत बनाने पर है। उनका मानना है कि चुनाव में किसी एक नेता को आगे करने के बजाय सभी वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं को सामूहिक रूप से मैदान में उतरना चाहिए। पार्टी के सामने सबसे बड़ी चुनौती अंदरूनी मतभेदों को दूर कर मजबूत चुनावी संगठन तैयार करने की है।

पायलट ने संकेत दिया है कि कांग्रेस के लिए किसी एक व्यक्ति का चेहरा प्राथमिकता नहीं है। पार्टी की सामूहिक ताकत, संगठन की सक्रियता और कार्यकर्ताओं की एकजुटता को चुनावी रणनीति का आधार बनाया जाएगा। इसके साथ ही राहुल गांधी के नेतृत्व में व्यापक अभियान चलाने की तैयारी की जा रही है।

चन्नी को चेहरा बनाने की मांग पर फिलहाल विराम : प्रदेश कांग्रेस में एक धड़ा पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी को चुनाव में प्रमुख चेहरा बनाने की मांग करता रहा है। वहीं, प्रदेश अध्यक्ष राजा वड़िंग की भूमिका को लेकर भी पार्टी के भीतर मतभेद सामने आते रहे हैं। चन्नी खेमे की ओर से वड़िंग को प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाने की मांग भी समय-समय पर उठती रही है।

ऐसे माहौल में पायलट के बयान ने मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर चल रही अटकलों पर फिलहाल विराम लगा दिया है। पार्टी अब किसी एक नेता के बजाय सामूहिक नेतृत्व को आगे रखकर चुनाव की तैयारी करेगी। चुनाव परिणाम आने के बाद निर्वाचित विधायकों और पार्टी नेतृत्व की सहमति से मुख्यमंत्री का चयन किया जाएगा।

2017 में अमरिंदर के नेतृत्व में मिली थी जीत : पंजाब में कांग्रेस ने 2017 का विधानसभा चुनाव कैप्टन अमरिंदर सिंह के नेतृत्व में लड़ा था और पार्टी को सत्ता हासिल हुई थी। इसके बाद 2022 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने भगवंत मान को मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित कर चुनाव लड़ा और सरकार बनाई। अब कांग्रेस ने 2027 के लिए अलग रणनीति अपनाने का संकेत दिया है।

पार्टी नेतृत्व का मानना है कि चुनाव से पहले मुख्यमंत्री पद के चेहरे को लेकर नेताओं के बीच प्रतिस्पर्धा और गुटबाजी से बचना जरूरी है। सामूहिक नेतृत्व की रणनीति से सभी प्रमुख नेताओं को साथ लेकर चलने की कोशिश की जाएगी।

पायलट के सामने गुटबाजी खत्म करने की चुनौती : पंजाब कांग्रेस प्रभारी के रूप में सचिन पायलट के सामने सबसे बड़ी चुनौती प्रदेश संगठन में चल रही गुटबाजी को खत्म करना है। वह जल्द पंजाब का दौरा कर वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ बैठकें कर सकते हैं। उनका प्रयास अलग-अलग खेमों में बंटे नेताओं को एक मंच पर लाने का रहेगा। आगे राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के संभावित पंजाब अभियान के दौरान भी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की एकजुटता पर नजर रहेगी।

सत्ता में लौटते ही नयागांव को न्यू चंडीगढ़ बनाने का सुखबीर का बड़ा वादा

भारतेंदु संवाददाता, मोहाली। शिरोमणि अकाली दल ने वीरवार को मोहाली के खरड़ में 'पंजाब बचाओ रैली' आयोजित कर आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारियों का संदेश दिया। रैली में पार्टी प्रधान एवं पूर्व उपमुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल समेत कई वरिष्ठ नेता और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए। सुखबीर बादल ने आम आदमी पार्टी सरकार पर निशाना साधते हुए पंजाब के विकास, बिजली, बुनियादी सुविधाओं और आम लोगों से जुड़े मुद्दे उठाए। उन्होंने कहा कि पंजाब में अकाली दल की सरकार बनने पर नयागांव को न्यू चंडीगढ़ में शामिल किया जाएगा और क्षेत्र की लंबे समय से चली आ रही समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर समाधान कराया जाएगा।

सुखबीर बादल ने कहा कि अकाली दल ने अपने शासनकाल में पंजाब के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण परियोजनाएं शुरू की थीं। उन्होंने मौजूदा सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि लोगों को बुनियादी सुविधाओं के लिए भी परेशान होना पड़ रहा है। बिजली व्यवस्था का उल्लेख करते हुए उन्होंने सरकार पर लोगों की समस्याओं का समाधान करने में विफल रहने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि अकाली दल पंजाब के हितों और अधिकारों की रक्षा के लिए लगातार आवाज उठाता रहेगा।

अकाली दल प्रधान ने गरीबों और मजदूरों की जमीन के मालिकाना हक का मुद्दा भी प्रमुखता से उठाया। उन्होंने कहा कि यदि पार्टी सत्ता में आती है तो गांवों में लंबे समय से लाल डोरे वाली जमीन पर रह रहे गरीब परिवारों को उनकी जमीन का मालिकाना हक दिलाने के लिए कदम उठाए जाएंगे। छोटी जमीन पर घर बनाकर रह रहे परिवारों की रजिस्ट्री कराने की दिशा में भी काम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इससे वर्षों से जमीन के अधिकार की प्रतीक्षा कर रहे परिवारों को राहत मिलेगी।

सुखबीर बादल ने अकाली दल और भाजपा के पुराने गठबंधन का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि दोनों दलों का गठबंधन लंबे समय तक पंजाब की राजनीति में रहा, लेकिन बाद में यह टूट गया। उन्होंने पंजाब के अधिकारों और राज्य से जुड़े संस्थानों में दिल्ली के हस्तक्षेप को लेकर भी सवाल उठाए। उन्होंने कार्यकर्ताओं से गांव-गांव जाकर लोगों से संपर्क बढ़ाने और पार्टी संगठन को मजबूत करने का आह्वान किया।

डेराबस्सी के पूर्व विधायक एनके शर्मा ने भी रैली को संबोधित करते हुए प्रदेश सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि मौजूदा सरकार ने पंजाब को कर्ज के बोझ में दबा दिया है और उसका ध्यान विकास से अधिक प्रचार तथा विज्ञापनों पर है। शर्मा ने कहा कि अकाली सरकार के समय बड़े एयरपोर्ट, चौड़ी सड़कें, बिजली उत्पादन परियोजनाएं, 200 फुट सड़कें तथा आइटी सिटी, मेडिसिटी और एजुकेशन सिटी जैसी परियोजनाएं शुरू की गई थीं।

2020 बाद भर्ती 85 हजार कर्मचारियों का डीए 42 से बढ़कर 60 प्रतिशत हुआ

सरकार ने कर्मचारियों की मांगों पर दिया भरोसा, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को भी राहत

भारतेंदु संवाददाता, चंडीगढ़। पंजाब सरकार ने वर्ष 2020 के बाद भर्ती हुए कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को 42 से बढ़ाकर 60 प्रतिशत करने का फैसला किया है। सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास तथा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डा. बलजीत कौर ने कहा कि इससे करीब 85 हजार कर्मचारियों को सीधा लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि सरकार कर्मचारियों की मांगों के समाधान के लिए बातचीत का रास्ता अपनाएगी और जल्द ही मुख्यमंत्री भगवंत मान के साथ उनकी बैठक करवाने का प्रयास किया जाएगा।

कर्मचारी संगठनों की हड़ताल वापस लेने पर मंत्री ने उनका धन्यवाद करते हुए कहा कि इससे आम लोगों को राहत मिलेगी। उन्होंने बताया कि पिछली सरकार की कई देनदारियां वर्तमान सरकार को विरासत में मिली हैं। सरकार पिछले समय में तीन बार महंगाई भत्ता जारी कर चुकी है और करीब 6100 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है। डीए के भुगतान को लेकर सरकार ने अदालत के समक्ष भी अपना पूरा पक्ष और योजना रखी है।

डा. बलजीत कौर ने कहा कि पंजाब सरकार ने पिछले चार वर्षों में 70 हजार से अधिक नई नियुक्तियां कर रोजगार के क्षेत्र में रिकॉर्ड बनाया है। आउटसोर्स और अनुबंध कर्मचारियों से जुड़े मामलों पर भी सरकार सकारात्मक रूप से काम कर रही है तथा कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी की गई है। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार अपने वादों से पीछे नहीं हटेगी।

आंगनबाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं के संबंध में उन्होंने कहा कि उन्हें महिलाओं के लिए चल रही 1000 और 1500 रुपये की मासिक योजनाओं में शामिल किया गया है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में वार्षिक वृद्धि पर सरकार सकारात्मक है। उन्हें बीमा योजना के दायरे में लाने की भी तैयारी है, जिससे 33 हजार से अधिक कार्यकर्ताओं को लाभ मिलेगा। इसके अलावा छह हजार आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की हाल में भर्ती की गई है। कर्मचारियों के खिलाफ जारी पत्रों और अन्य मांगों पर भी कैबिनेट उपसमिति मुख्यमंत्री के साथ बैठक कराने का प्रयास करेगी।

जीरकपुर में दिव्यांग से पर्स-मोबाइल छीनकर बाइक सवार फरार

भारतेंदु संवाददाता, मोहाली। जीरकपुर के पालम एन्क्लेव में बाइक सवार दो युवकों ने दिव्यांग व्यक्ति से पर्स और मोबाइल फोन छीन लिया। पर्स में करीब पांच हजार रुपये नकद, क्रेडिट कार्ड, दिव्यांगता प्रमाण पत्र, पहचान पत्र और अन्य जरूरी दस्तावेज थे। पीड़ित सुरिंदर पाल ने पुलिस को शिकायत देकर आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। सुरिंदर पाल ने बताया कि जरनैल एन्क्लेव में उनका संस्थान है। वह सुबह करीब 10 बजे रोज की तरह घर से संस्थान जा रहे थे। रास्ते में पीछे से बाइक पर आए दो युवकों ने अचानक उनके हाथ से पर्स छीन लिया और तेज रफ्तार से फरार हो गए। वह दिव्यांग हैं और चलने में परेशानी होती है, इसलिए आरोपियों का पीछा नहीं कर सके। घटना के बाद स्थानीय लोगों में भी चिंता है। लोगों का कहना है कि इलाके में लगातार स्नैचिंग की घटनाओं से असुरक्षा बढ़ रही है। उन्होंने पुलिस से क्षेत्र में गश्त बढ़ाने, संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखने और आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने की मांग की है। पुलिस शिकायत के आधार पर मामले की जांच कर रही है।

नशा कारोबारियों पर कार्रवाई पर मेयर ने मांगी खुली छूट

प्रशासक से मांगी अनुमति, पुलिस-प्रशासन पर निष्क्रियता का आरोप, खुद कार्रवाई की चेतावनी

भारतेंदु संवाददाता, चंडीगढ़। शहर में नशे के कारोबार के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग को लेकर मेयर सौरभ जोशी ने प्रशासक से बड़ी कार्रवाई की अनुमति मांगी है। उन्होंने कहा कि यदि नशे के कारोबारियों के खिलाफ उपायुक्त और पुलिस विभाग प्रभावी कार्रवाई नहीं करते हैं तो उन्हें कार्रवाई करने की अनुमति दी जाए। मेयर ने कहा कि वह नशा कारोबारियों के घरों पर बुलडोजर चलवाने के लिए भी कदम उठाएंगे।

सेक्टर-17 प्लाजा में 'नशे को इंकार, उज्ज्वल भविष्य को करे स्वीकार' थीम के तहत नौवें राष्ट्रीय पोषण माह के अंतर्गत आयोजित कार्यक्रम में मेयर ने नशे के खिलाफ अभियान को मजबूत करने की जरूरत बताई। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं को नशे से दूर रखना और उन्हें स्वस्थ जीवनशैली अपनाने के लिए प्रेरित करना है। युवाओं को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करने के साथ नशा बेचने वालों पर कठोर कार्रवाई जरूरी है।

मेयर ने पुलिस और प्रशासन की भूमिका पर सवाल उठाते हुए कहा कि नशे के कारोबार को किसी भी स्तर पर बढ़ावा नहीं मिलने दिया जाना चाहिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि नशे के खिलाफ कार्रवाई में ढिलाई स्वीकार नहीं की जाएगी। यदि संबंधित विभाग कार्रवाई नहीं करते हैं तो वह स्वयं कार्रवाई के लिए अनुमति मांगेंगे।

कार्यक्रम में स्कूलों के एसएसएस स्वयंसेवकों ने नुक्कड़ नाटक के माध्यम से नशे के दुष्प्रभावों को प्रदर्शित किया। नाटक के जरिए युवाओं को नशे की गिरफ्त में आने से बचने और समाज में जागरूकता फैलाने का संदेश दिया गया। एनएसएस स्वयंसेवकों ने भी कार्यक्रम में भाग लिया।

इस अवसर पर प्रशासक गुलाब चंद कटारिया, गृह सचिव मंदीप बराड़, नगर निगम के स्पेशल सेक्रेटरी हरप्रीत सिंह सूदन समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान युवाओं को नशे से दूर रहने, स्वस्थ जीवनशैली अपनाने और समाज को नशामुक्त बनाने में योगदान देने के लिए प्रेरित किया गया।

मेयर ने कहा कि नशे के खिलाफ लड़ाई केवल सरकारी स्तर पर कार्रवाई तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, बल्कि इसमें समाज के हर वर्ग की भागीदारी जरूरी है। उन्होंने अभिभावकों, शिक्षकों और सामाजिक संगठनों से युवाओं पर नजर रखने तथा उन्हें खेल और रचनात्मक गतिविधियों से जोड़ने की अपील की। उन्होंने कहा कि नशे का कारोबार करने वाले लोग युवाओं के भविष्य को नुकसान पहुंचा रहे हैं, इसलिए उनके खिलाफ सख्त और प्रभावी कार्रवाई समय की जरूरत है। कार्यक्रम में स्वयंसेवकों ने लोगों को नशे के कारण होने वाले स्वास्थ्य और सामाजिक नुकसान के बारे में जानकारी दी। नुक्कड़ नाटक के माध्यम से यह संदेश दिया गया कि नशे की शुरुआत अक्सर छोटी आदत से होती है, जो आगे चलकर गंभीर समस्या बन सकती है।

बठिंडा में 630 किमी सड़कों की मशीनों से होगी सफाई

भारतेंदु संवाददाता, बठिंडा। शहर की सफाई व्यवस्था को आधुनिक और प्रभावी बनाने के लिए नगर निगम की ओर से मैकेनिकल स्वीपिंग परियोजना को विस्तार दिया जा रहा है। स्थानीय निकाय विभाग के सचिव घनश्याम थोरी ने परियोजना का निरीक्षण कर अधिकारियों को सफाई व्यवस्था में तेजी लाने के निर्देश दिए। वर्तमान में शहर में करीब 100 किलोमीटर सड़कों की साप्ताहिक मैकेनिकल सफाई की जा रही है।

निरीक्षण के दौरान थोरी ने शहर की अंदरूनी सड़कों की सफाई पर विशेष जोर दिया। उन्होंने करीब 630 किलोमीटर अंदरूनी सड़कों पर साप्ताहिक मैकेनिकल स्वीपिंग और डीप क्लीनिंग का काम जल्द शुरू करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सफाई व्यवस्था केवल मुख्य सड़कों तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, बल्कि गलियों और अंदरूनी मार्गों तक भी इसका प्रभाव दिखाई देना चाहिए। आधुनिक मशीनरी के उपयोग से सफाई के साथ शहर के सौंदर्यीकरण को भी बढ़ावा मिलेगा।

सचिव ने मुख्य सड़कों की सफाई से संबंधित करीब 164 किलोमीटर के लंबित निविदा कार्यों को भी शीघ्र पूरा करने को कहा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रक्रिया में अनावश्यक देरी न हो और काम जल्द धरातल पर शुरू कराया जाए। साथ ही मैकेनिकल स्वीपिंग की नियमित निगरानी और सफाई कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

थोरी ने कहा कि किसी भी योजना की सफलता तभी मानी जाएगी, जब उसका लाभ लोगों को जमीन पर दिखाई दे।

अमृतसर, आनंदपुर साहिब और तलवंडी साबो में आदेश उल्लंघन पर कार्रवाई

पंजाब के तीन पवित्र शहरों में मांस पर रोक आठ महीने बाद गजट में प्रकाशित हुआ आदेश

भारतेंदु संवाददाता, चंडीगढ़। पंजाब सरकार ने राज्य के तीन पवित्र शहरों में मांस की बिक्री और इस्तेमाल पर रोक संबंधी आदेश को अब असाधारण गजट में प्रकाशित कर दिया है। यह प्रतिबंध अमृतसर के चारदीवारी क्षेत्र, रूपनगर जिले के श्री आनंदपुर साहिब और बठिंडा जिले के तलवंडी साबो (श्री दमदमा साहिब) की संबंधित नगर पालिका सीमाओं में लागू होगा।

पंजाब सरकार के नौ सितंबर 2026 के असाधारण गजट में पशुपालन, मत्स्य पालन एवं डेयरी विकास विभाग की ओर से जारी आदेश प्रकाशित किया गया है। हालांकि, आदेश पर 23 दिसंबर 2025 की तारीख दर्ज है। यानी प्रतिबंध संबंधी आदेश जारी होने के करीब साढ़े आठ महीने बाद इसे सरकारी गजट में प्रकाशित किया गया है।

आदेश में कहा गया है कि संबंधित क्षेत्रों में मांस की बिक्री और इस्तेमाल पर रोक तत्काल प्रभाव से लागू होगी। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ राज्य में लागू संबंधित कानूनों और नियमों के तहत कार्रवाई की जाएगी।

विभाग के अनुसार यह कार्रवाई गृह मामले विभाग की 15 दिसंबर 2025 की अधिसूचना में दिए गए निर्देशों के अनुपालन में की गई है। इसके बाद पशुपालन विभाग ने 23 दिसंबर 2025 को प्रतिबंध संबंधी आदेश जारी किया था, जिसे अब नौ सितंबर 2026 को गजट में प्रकाशित किया गया है। अमृतसर के मामले में पूरे शहर पर प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। आदेश विशेष रूप से चारदीवारी वाले शहर के क्षेत्र पर लागू होगा।

गुलजार आत्महत्या मामले में एससी आयोग ने जांच का दिया भरोसा

भारतेंदु संवाददाता, संगरूर। संगरूर के दिड़बा हलके के गांव तूरबंजारा निवासी दलित मजदूर गुलजार सिंह की आत्महत्या के मामले में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने सख्त संज्ञान लिया है। आयोग के चेयरमैन किशोर मकवाना ने गांव पहुंचकर पीड़ित परिवार से मुलाकात की और उनकी समस्याएं सुनीं। उन्होंने परिवार को न्याय का भरोसा दिलाते हुए कहा कि दोषी पाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। इससे पहले दिड़बा के एसडीएम ने गुलजार सिंह की पत्नी पाल कौर को पांच लाख रुपये की सहायता राशि का चेक सौंपा। किशोर मकवाना ने कहा कि गुलजार सिंह नशे के खिलाफ आवाज उठा रहे थे। परिवार ने उन्हें धमकियां मिलने के आरोप लगाए हैं।

जीरकपुर के दयालपुर में डिस्पेंसरी मिली बंद, इलाज को भटक रहे ग्रामीण मरीज

भारतेंदु संवाददाता, जीरकपुर। गांवों में गरीब और जरूरतमंद लोगों को घर के पास स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से खोली गई दयालपुर की सरकारी डिस्पेंसरी की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं। वीरवार को डिस्पेंसरी पर ताला लटका मिला। इलाज और दवा लेने पहुंचे मरीजों को निराश होकर लौटना पड़ा। ग्रामीणों का कहना है कि यह पहली बार नहीं है। कई बार डॉक्टर समय पर नहीं पहुंचतीं और मरीजों को घंटों इंतजार करने के बाद भी स्वास्थ्य सुविधा नहीं मिल पाती।

दयालपुर के अलावा आसपास की सोसायटियों, कॉलोनियों, झुग्गियों और छोटे मकानों में रहने वाले हजारों लोग इस डिस्पेंसरी पर निर्भर हैं। इनमें बड़ी संख्या आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की है। ग्रामीणों के अनुसार डिस्पेंसरी बंद मिलने पर सामान्य बीमारी और दवा के लिए भी उन्हें डेराबस्सी जाना पड़ता है। इससे उनका समय और आने-जाने का खर्च दोनों बढ़ जाते हैं। बुजुर्गों, महिलाओं और बच्चों को सबसे अधिक परेशानी होती है।

स्थानीय लोगों ने डॉक्टर के व्यवहार और नियमित उपस्थिति को लेकर भी सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि लोग गांव में ही जांच और दवा मिलने की उम्मीद लेकर पहुंचते हैं, लेकिन कई बार दरवाजे पर ताला देखकर वापस लौटना पड़ता है। ग्रामीणों ने स्वास्थ्य विभाग से पूरे मामले की जांच कराने की मांग की है।

मामले में एक और गंभीर बात सामने आई है। सरकारी डिस्पेंसरी की चाबी एक निजी दुकानदार के पास रखी जाती है। दुकानदार ने बताया कि कोई मरीज आने पर वह चाबी देकर डिस्पेंसरी खुलवा देता है।

पंजाब के पूर्व कैबिनेट मंत्री भगत चुन्नी लाल का निधन, 93 वर्ष की उम्र में ली अंतिम सांस

भारतेंदु संवाददाता, जालंधर। पंजाब के पूर्व कैबिनेट मंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता भगत चुन्नी लाल का गुरुवार सुबह 93 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्होंने जालंधर के बस्ती इलाके स्थित अपने आवास पर अंतिम सांस ली। उनके निधन की खबर से राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई। उनका अंतिम संस्कार गुरुवार शाम करीब पांच बजे बस्ती शेख श्मशानघाट में किया जाएगा। भाजपा नेता शीतल अंगुराल समेत कई नेताओं ने उनके निधन पर शोक जताया है।

भगत चुन्नी लाल पंजाब सरकार में वर्तमान कैबिनेट मंत्री मोहिंद्र भगत के पिता थे। उनका जन्म एक दिसंबर 1932 को सियालकोट में हुआ था, जो अब पाकिस्तान में है। भारत-पाकिस्तान विभाजन के बाद उनका परिवार जालंधर आकर बस गया। राजनीति में सक्रिय होने से पहले वह खेल सामग्री के कारोबार से जुड़े थे और विदेशों में खेल सामान का निर्यात करते थे। उनकी पत्नी शीला देवी का पहले ही निधन हो चुका है। परिवार में चार बेटे और चार बेटियां हैं।

भगत चुन्नी लाल ने वर्ष 1985 में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में जालंधर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़कर अपनी राजनीतिक पारी शुरू की, हालांकि उन्हें हार का सामना करना पड़ा। बाद में वह भाजपा में शामिल हो गए। वर्ष 1997 में भाजपा के टिकट पर जालंधर दक्षिण से चुनाव जीतकर पहली बार पंजाब विधानसभा पहुंचे। वर्ष 2007 में उन्होंने इसी सीट से दोबारा जीत दर्ज की।

परिसीमन के बाद जालंधर दक्षिण सीट का स्वरूप बदलकर जालंधर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र बना। वर्ष 2012 में भगत चुन्नी लाल ने भाजपा प्रत्याशी के रूप में जालंधर पश्चिम से जीत दर्ज की और तीसरी बार विधायक बने। वर्ष 2011 में तत्कालीन विधानसभा उपाध्यक्ष सतपाल गोसाईं के इस्तीफे के बाद उन्हें पंजाब विधानसभा का डिप्टी स्पीकर चुना गया।

वर्ष 2012 से 2017 तक प्रकाश सिंह बादल के नेतृत्व वाली अकाली-भाजपा सरकार में वह कैबिनेट मंत्री रहे। उनके पास स्थानीय निकाय, चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान, श्रम तथा वन एवं वन्यजीव जैसे महत्वपूर्ण विभाग रहे। इसी अवधि में वह पंजाब विधानसभा में भाजपा विधायक दल के नेता भी रहे। जालंधर पश्चिम की राजनीति में उनका लंबे समय तक प्रभाव रहा।

समीकरण पायलट से मुलाकात के बाद कांग्रेस नेताओं ने पंजाब की समस्याएं राज्यपाल के सामने रखीं

नशे के मुद्दे पर राज्यपाल से मिले कांग्रेस नेता

भारतेंदु संवाददाता, चंडीगढ़। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री एवं सांसद चरणजीत सिंह चन्नी और सांसद सुखजिंदर सिंह रंधावा ने गुरुवार को राज्यपाल गुलाबचंद कटारिया से मुलाकात कर प्रदेश के मौजूदा हालात पर चर्चा की। दोनों नेता दिल्ली में पंजाब कांग्रेस के नवनियुक्त प्रभारी सचिन पायलट से मुलाकात के बाद पंजाब लौटे थे। इसके बाद राज्यपाल से हुई इस भेंट को राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। प्रतिनिधिमंडल में पूर्व मंत्री तृप्त राजिंदर सिंह बाजवा, पूर्व सांसद शेर सिंह घुबाया, विधायक बरिंदरजीत सिंह पाहड़ा और युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष शुभम शर्मा समेत अन्य नेता भी शामिल रहे।

कांग्रेस नेताओं ने राज्यपाल के समक्ष पंजाब में नशे के बढ़ते कारोबार और इससे पैदा हो रही स्थिति को लेकर चिंता जताई। सीमावर्ती क्षेत्रों में लगातार सामने आ रही नशा तस्करी की घटनाओं का भी मुद्दा उठाया गया। सांसद सुखजिंदर सिंह रंधावा पहले भी नशे और इससे जुड़े मामलों को केंद्र सरकार तथा संसद में उठाते रहे हैं। नेताओं ने प्रदेश में कानून-व्यवस्था की स्थिति पर भी चिंता व्यक्त की और प्रभावी कार्रवाई की आवश्यकता बताई।

बैठक के दौरान नशे के खिलाफ आवाज उठाने वाले गुलजार सिंह की मौत और उससे जुड़े विवाद का मुद्दा भी उठाए जाने की संभावना है। इसके अलावा मुख्यमंत्री भगवंत मान के कार्यक्रम में काला झंडा दिखाने वाले प्रदर्शनकारी के साथ कथित पुलिस मारपीट तथा कानून-व्यवस्था से जुड़े अन्य मामलों पर भी चर्चा हुई। कांग्रेस नेताओं ने राज्यपाल को प्रदेश की स्थिति से अवगत कराते हुए संबंधित मामलों में उचित कार्रवाई की आवश्यकता पर जोर दिया।

राज्यपाल से मुलाकात से एक दिन पहले चन्नी और रंधावा ने दिल्ली में पंजाब कांग्रेस प्रभारी सचिन पायलट से मुलाकात की थी। पंजाब में वर्ष 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए यह मुलाकात भी अहम मानी गई। पायलट पार्टी को सामूहिक नेतृत्व के साथ चुनाव मैदान में उतारने और संगठन को मजबूत करने की रणनीति पर जोर दे रहे हैं। ऐसे में वरिष्ठ नेताओं की लगातार सक्रियता को चुनावी तैयारियों से जोड़कर देखा जा रहा है।

पंजाब कांग्रेस में अलग-अलग नेताओं के बीच मतभेद और संगठनात्मक स्तर पर खींचतान लंबे समय से चर्चा में रही है। ऐसे में पायलट के सामने सभी गुटों को साथ लेकर चलने और संगठन को मजबूत करने की बड़ी चुनौती है। उनके जल्द पंजाब दौरे पर आने की संभावना है। इस दौरान प्रदेश कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर संगठन की स्थिति, चुनावी तैयारियों तथा आपसी समन्वय पर चर्चा की जा सकती है।

कांग्रेस अब धीरे-धीरे 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारियों में सक्रिय होती दिखाई दे रही है। पार्टी नेतृत्व का जोर संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करने, नेताओं के बीच समन्वय बढ़ाने और प्रदेश के प्रमुख मुद्दों को जनता के बीच उठाने पर है।

कश्मीर में फिर लौटेगा फिल्मों की शूटिंग का सुनहरा दौर

फिल्म महोत्सव को बताया शुभ शुरुआत।

भारतेंदु संवाददाता, श्रीनगर। दिग्गज फिल्म निर्माता-निर्देशक रमेश सिप्पी ने कश्मीर में बदले माहौल का स्वागत करते हुए कहा कि घाटी में फिल्मों की शूटिंग का सुनहरा दौर फिर लौटेगा। श्रीनगर के आइनाक्स में चल रहे इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के दौरान पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि कश्मीर का माहौल अब काफी बेहतर हुआ है। इससे लोगों में यहां आने का भरोसा बढ़ेगा और फिल्मों की शूटिंग तथा निर्माण गतिविधियां फिर तेज होंगी। 'शोले' जैसी ऐतिहासिक फिल्म देने वाले सिप्पी ने पुराने दिनों को याद करते हुए कहा कि एक समय कश्मीर के बिना फिल्मों की कल्पना मुश्किल थी। डल झील, गुलमर्ग और पहलगाम में कई यादगार गीतों और फिल्मों की शूटिंग हुई है। बाद के वर्षों में परिस्थितियों के कारण यह सिलसिला धीमा पड़ गया। उन्होंने कहा कि कश्मीर जैसी प्राकृतिक खूबसूरती दुनिया में कहीं और आसानी से नहीं मिलती। सिप्पी ने जम्मू-कश्मीर सरकार और स्थानीय लोगों की भी सराहना की। उन्होंने कहा कि अच्छी कहानी और कलाकार हों तो कश्मीर में आसानी से फिल्म बनाई जा सकती है।

◆ स्थानीय लोग बेहतर बताएंगे कश्मीर की कहानियां

अफरवट में घूमता रेस्टोरेंट दिखाएगा हिमालय का नजारा

अफरवट चोटी पर प्रस्तावित रेस्टोरेंट में पर्यटक घूमते डाइनिंग क्षेत्र से देखेंगे हिमालय की चारों दिशाएं

भारतेंदु संवाददाता, श्रीनगर। गुलमर्ग की अफरवट चोटी पर पर्यटकों को हिमालय का अनोखा अनुभव देने के लिए एक आइकॉनिक हाई-एल्टीट्यूड रिवॉल्विंग रेस्टोरेंट विकसित करने की तैयारी शुरू हो गई है। करीब 10 हजार फीट की ऊंचाई पर प्रस्तावित इस रेस्टोरेंट का डाइनिंग क्षेत्र धीरे-धीरे 360 डिग्री घूमेगा। इससे पर्यटक अपनी सीट पर बैठे-बैठे चारों दिशाओं में फैली बर्फीली पर्वत श्रृंखलाओं और हिमालय की चोटियों का बदलता दृश्य देख सकेंगे। परियोजना को स्विट्जरलैंड के सास-फी स्थित रिवॉल्विंग रेस्टोरेंट से प्रेरित माना जा रहा है, लेकिन इसका डिजाइन अफरवट की स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप तैयार किया जाएगा।

गंडोला से आगे नया पर्यटन अनुभव : गुलमर्ग आने वाले पर्यटकों के लिए गंडोला पहले से ही प्रमुख आकर्षण है। केबल कार गुलमर्ग से पर्यटकों को कोंगदूरी और फिर अफरवट की ऊंची ढलानों तक पहुंचाती है। अब इसी अनुभव को आगे बढ़ाते हुए चोटी पर ऐसा रेस्टोरेंट तैयार करने की योजना है, जहां भोजन के साथ लगातार बदलते हिमालयी दृश्यों का आनंद लिया जा सके। जम्मू-कश्मीर केबल कार कॉरपोरेशन लिमिटेड ने परियोजना के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट, वास्तु एवं इंजीनियरिंग डिजाइन और निविदा दस्तावेज तैयार करने के लिए सलाहकार नियुक्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

स्विस अवधारणा, कश्मीरी परिस्थितियों के अनुसार निर्माण : परियोजना की प्रेरणा स्विट्जरलैंड के मिटेलालिन माउंटेन स्टेशन स्थित रिवॉल्विंग रेस्टोरेंट से ली गई है। वहां डाइनिंग क्षेत्र लगभग एक घंटे में 360 डिग्री घूमता है। अफरवट में भी इसी तरह का अनुभव देने की योजना है। हालांकि भारी बर्फबारी, तेज हवाओं, अत्यधिक ठंड और भूकंपीय गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए भवन की संरचना तैयार की जाएगी। डिजाइन में स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप मजबूत निर्माण सामग्री और सुरक्षित इंजीनियरिंग व्यवस्था को प्राथमिकता दी जाएगी।

◆ गुलमर्ग में हिमालयी वादियों के बीच मिलेगा अनूठा भोजन अनुभव

भारी बर्फबारी, तेज हवाओं और अत्यधिक ठंड को ध्यान में रखकर तैयार होगा ढांचा।

स्विस मॉडल से प्रेरित, कश्मीर के अनुरूप डिजाइन

इस परियोजना की प्रेरणा स्विट्जरलैंड के सास-फी स्थित मिटेलालिन माउंटेन स्टेशन के रिवॉल्विंग रेस्टोरेंट से ली गई है। वहां डाइनिंग एरिया धीरे-धीरे घूमता है और पर्यटक एक ही स्थान से अलग-अलग दिशाओं में फैले स्विस आल्प्स का दृश्य देख पाते हैं। हालांकि अफरवट में बनने वाला रेस्टोरेंट स्विस मॉडल की हूबहू नकल नहीं होगा। इसका डिजाइन अफरवट की भारी बर्फबारी, तेज हवाओं, अत्यधिक ठंड और पहाड़ी परिस्थितियों को ध्यान में रखकर तैयार किया जाएगा।

पुरानी संरचना की मजबूती भी जांची जाएगी

प्रस्तावित रेस्टोरेंट को अफरवट टॉप स्टेशन पर मौजूद पुरानी नींव संरचना के आसपास विकसित करने की योजना है। निर्माण से पहले इस संरचना की मजबूती की जांच कराई जाएगी। इसके लिए संरचनात्मक परीक्षण, गैर-विनाशकारी परीक्षण और सामग्री की जांच जैसी प्रक्रियाएं अपनाई जाएंगी। विशेषज्ञों की रिपोर्ट के आधार पर तय होगा कि पुरानी संरचना को मजबूत कर इस्तेमाल किया जा सकता है या पूरी तरह नई संरचना तैयार करनी होगी।

पर्यावरण संरक्षण पर भी रहेगा जोर : अफरवट की प्राकृतिक सुंदरता को देखते हुए परियोजना में पर्यावरणीय पहलुओं को विशेष महत्व दिया जाएगा। निर्माण से पहले अल्पाइन पारिस्थितिकी तंत्र, प्राकृतिक दृश्यों और स्थानीय पर्यावरण पर संभावित प्रभाव का अध्ययन किया जाएगा। पानी की उपलब्धता और जरूरत के साथ सौर ऊर्जा तथा अन्य नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के इस्तेमाल की संभावनाएं भी देखी जाएंगी। उद्देश्य ऐसी पर्यटन सुविधा विकसित करना है, जो प्राकृतिक वातावरण के साथ संतुलन बनाए रखे।

522 ग्राम हेरोइन बरामदगी मामले में आरोपी की तलाश राज्यों तक पहुंची

हुलिया बदलकर जालंधर में छिपा तस्कर गिरफ्तार, एनसीबी ने तीन दिन में दबोचा

एक महीने में चार कार्रवाइयों के दौरान एनसीबी ने 6.920 किलो हेरोइन की जब्त।

भारतेंदु संवाददाता, जम्मू। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) की जम्मू इकाई ने अपनी हिरासत से फरार हुए मादक पदार्थ तस्कर आकिब बशीर को तीन दिन बाद पंजाब के जालंधर से गिरफ्तार कर लिया। पुलवामा जिले के काकापोरा निवासी बशीर को तीन सितंबर को सांबा जिले में एक यात्री बस से 522 ग्राम हेरोइन के साथ पकड़ा गया था। उसे एनसीबी की हिरासत में रखा गया था, लेकिन छह-सात सितंबर की रात जम्मू के नरवाल इलाके से वह फरार हो गया।

फरार होने के बाद बशीर पहले नरवाल फल मंडी के पास जंगल में छिपा रहा। इसके बाद वह पठानकोट के रास्ते जालंधर पहुंचा और अपने संपर्कों के जरिये वहां शरण ली। सुरक्षा एजेंसियों से बचने के लिए उसने दाढ़ी-मूंछ और बाल साफ कर लिए तथा कपड़े बदलकर अपना हुलिया पूरी तरह बदलने की कोशिश की।

एनसीबी के अनुसार, खुफिया जानकारी और जमीनी कार्रवाई के आधार पर जांच टीमों ने बशीर की लोकेशन का पता लगाया। उसे उस समय गिरफ्तार किया गया, जब वह जालंधर से दिल्ली या किसी अन्य राज्य की ओर निकलने की तैयारी कर रहा था। गिरफ्तारी अभियान में एनसीबी के साथ जम्मू-कश्मीर पुलिस और पंजाब पुलिस भी शामिल रही। एनसीबी ने बताया कि जम्मू-कश्मीर में मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ चल रहे अभियान के तहत पिछले एक महीने में चार अलग-अलग मामलों में कुल 6.920 किलोग्राम हेरोइन जब्त की गई है। इन मामलों में अब तक छह आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। जांच में हेरोइन की तस्करी के दो प्रमुख मार्ग सामने आए हैं, जिनमें पाकिस्तान से उरी सेक्टर और पंजाब के रास्ते जम्मू-कश्मीर तक नशीले पदार्थ पहुंचाने की आशंका है।

सुनिधि चौहान ने कश्मीर को बताया जन्नत, कॉन्सर्ट की जताई इच्छा

भारतेंदु संवाददाता, श्रीनगर। अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में हिस्सा लेने कश्मीर पहुंचीं प्रसिद्ध बॉलीवुड गायिका सुनिधि चौहान घाटी की प्राकृतिक सुंदरता, मेहमाननवाजी और खानपान से बेहद प्रभावित हुईं। उन्होंने कश्मीर को 'जन्नत' बताते हुए कहा कि यहां आकर उनकी रूह ताजा हो गई। उन्होंने उम्मीद जताई कि भविष्य में उन्हें कश्मीर में अपना संगीत कार्यक्रम करने का अवसर मिलेगा।

चौहान ने बताया कि यह कश्मीर का उनका पहला दौरा है। उन्होंने कहा कि फिल्मों और टेलीविजन के माध्यम से वह पहले से कश्मीर की सुंदरता से परिचित थीं, लेकिन यहां आकर अनुभव बिल्कुल अलग रहा। उन्होंने कहा कि घाटी के नजारे देखकर उनकी आंखें खुल गईं और उन्हें महसूस हुआ कि वह वास्तव में जन्नत में हैं। उन्होंने यहां की मेहमाननवाजी और भोजन की भी जमकर तारीफ की।

फिल्म महोत्सव के महत्व पर सुनिधि ने कहा कि ऐसे आयोजन कम जानी-मानी फिल्मों और फिल्मकारों को पहचान दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

स्थानीय दर्शकों की भागीदारी से उत्साहित

सुनिधि ने महोत्सव में स्थानीय दर्शकों की भागीदारी की भी सराहना की। उन्होंने कहा कि फिल्म प्रेमियों को स्क्रीनिंग में पहुंचते देखना उत्साह बढ़ाने वाला है। ऐसे आयोजन लोगों को नई फिल्मों और विचारों से सीखने तथा उन्हें समझने का अवसर देते हैं। उन्होंने कहा कि अच्छी फिल्मों को लगातार प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। चौहान ने कश्मीर को फिल्मों की शूटिंग के लिए बेहद उपयुक्त स्थान बताया। उन्होंने कहा कि घाटी के खूबसूरत प्राकृतिक दृश्य किसी भी फिल्म को बेहतर बना सकते हैं।

अखरोट तोड़ते समय पेड़ से गिरा व्यक्ति, मौत

भारतेंदु संवाददाता, श्रीनगर। दक्षिण कश्मीर के कुलगाम जिले के जैबल लम्मर इलाके में अखरोट तोड़ते समय पेड़ से गिरने से 46 वर्षीय मुख्तार अहमद नजार की मौत हो गई। बताया गया कि वह अपने बगीचे में अखरोट तोड़ने के लिए पेड़ पर चढ़े थे। इसी दौरान अचानक संतुलन बिगड़ने से वह ऊंचाई से नीचे गिर गए और गंभीर रूप से घायल हो गए। परिजनों व स्थानीय लोगों ने उन्हें तत्काल अस्पताल पहुंचाया, जहां उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। मृतक की पहचान गुलाम नबी नजार के पुत्र मुख्तार अहमद नजार के रूप में हुई है। घटना के बाद इलाके में शोक की लहर है। अधिकारियों ने मामले की जांच शुरू कर कानूनी कार्रवाई की बात कही है। कश्मीर में सितंबर-अक्टूबर के दौरान अखरोट तोड़ने का मौसम रहता है। ऊंचे और कमजोर पेड़ों से गिरने के कारण इस दौरान हर वर्ष कई लोग घायल होते हैं या जान गंवा बैठते हैं। हादसे ने अखरोट तोड़ने के दौरान सुरक्षा बरतने की जरूरत को फिर सामने ला दिया है।

न्यूज ब्रीफ

बिश्नाह में चोरी का पर्दाफाश, दो क्विंटल सामान बरामद; तीन गिरफ्तार

भारतेंदु संवाददाता, जम्मू। जम्मू पुलिस ने बिश्नाह थाना क्षेत्र में हुई चोरी के मामले को सुलझाते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर करीब दो क्विंटल चोरी का सैनिटरी और बाथरूम फिटिंग का सामान बरामद किया है। पुलिस के अनुसार, 2 सितंबर 2026 को मिली शिकायत के आधार पर बिश्नाह थाने में मामला दर्ज किया गया था। जांच के दौरान पुलिस टीम ने दीपक पटेल निवासी छतरपुर, हाल निवासी बड़ी ब्राह्मणा, पंकज पुम्बा निवासी दौलियां, बड़ी ब्राह्मणा और कुनाल सिंह निवासी तेली बस्ती, बड़ी ब्राह्मणा को गिरफ्तार किया। पूछताछ के बाद उनकी निशानदेही पर चोरी का सामान बरामद किया गया। पुलिस ने वारदात में कथित तौर पर इस्तेमाल कार और मोटरसाइकिल भी जब्त कर ली हैं। पुलिस अब आरोपियों की अन्य चोरी की घटनाओं में संभावित संलिप्तता की जांच कर रही है। साथ ही चोरी की अतिरिक्त संपत्ति बरामद करने के लिए भी कार्रवाई जारी है।

गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बसोहली में अप्रेंटिसशिप योजना को लेकर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित

भारतेंदु संवाददाता, बसोहली। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बसोहली में राष्ट्रीय अप्रेंटिसशिप प्रोत्साहन योजना को लेकर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। विद्यार्थियों को अप्रेंटिसशिप के अवसरों, पात्रता, पंजीकरण प्रक्रिया और रोजगार संभावनाओं की जानकारी दी गई। रिसोर्स पर्सन साहिल कुमार ने बताया कि अप्रेंटिसशिप से विद्यार्थियों को व्यावहारिक अनुभव और उद्योगों की जरूरत के अनुरूप कौशल मिलता है। उन्होंने पोर्टल पर पंजीकरण की प्रक्रिया समझाते हुए विद्यार्थियों की मौके पर सहायता भी की। संवादात्मक सत्र में विद्यार्थियों ने चयन और प्रशिक्षण से जुड़े सवाल पूछे। कार्यक्रम में करीब 80 विद्यार्थियों और शिक्षकों ने भाग लिया।

पुनर्वास से पहले चला बुलडोजर, सतवारी चौक पर 20 दुकानें ध्वस्त, दुकानदारों में आक्रोश

भारतेंदु संवाददाता, जम्मू। जम्मू नगर निगम ने सतवारी चौक पर करीब 20 दुकानों को ध्वस्त कर दिया। कार्रवाई से दुकानदारों में आक्रोश है। प्रभावित दुकानदारों का कहना है कि ये दुकानें करीब 50 वर्षों से संचालित थीं और वे नियमित रूप से नगर निगम को किराया देते थे। उनका आरोप है कि बिना पर्याप्त सूचना या नोटिस के कार्रवाई की गई। नगर निगम अधिकारी ने कहा कि प्रभावित दुकानदारों को छह महीने में वैकल्पिक स्थान पर स्थानांतरित किया जाएगा। व्यापारिक संगठनों ने भी दुकानदारों के पुनर्वास और वैकल्पिक स्थल की मांग उठाई है।

छन्नी हिम्मत में पार्क सौंदर्यीकरण को मिली पांच लाख की राशि

भारतेंदु संवाददाता, जम्मू। बहू विधानसभा क्षेत्र के वार्ड नंबर 50, सेक्टर-4 छन्नी हिम्मत में पार्क के सौंदर्यीकरण एवं विकास कार्य का उद्घाटन विधायक चौधरी विक्रम सिंह रंधावा ने किया। कार्य के लिए विधायक ने अपने सीडीएफ फंड से पांच लाख रुपये की राशि उपलब्ध कराई है। इस दौरान भाजपा जिला महामंत्री कुलबीर चारक समेत स्थानीय लोग मौजूद रहे। विधायक ने कहा कि बहू विधानसभा क्षेत्र का विकास उनकी प्राथमिकता है और जनता की जरूरतों के अनुसार विकास कार्यों को गति दी जाएगी।

जम्मू-वाराणसी विशेष ट्रेन का आदेश रेलवे ने किया रद्द

भारतेंदु संवाददाता, जम्मू। यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे ने जम्मू तवी और वाराणसी के बीच विशेष ट्रेन चलाने की घोषणा की थी, लेकिन अब इस संबंध में जारी आदेश रद्द कर दिया गया है। वाराणसी-जम्मू तवी आरक्षित विशेष ट्रेन संख्या 04239 को गुरुवार को वाराणसी से चलाने की जानकारी दी गई थी। इसके ठहराव समेत अन्य विवरण भी जारी किए गए थे, लेकिन रेलवे ने बाद में ट्रेन संचालन का आदेश वापस ले लिया।

नियमित ट्रेनों से सफर जारी : जम्मू तवी से वाराणसी के लिए पहले से नियमित ट्रेनों का संचालन हो रहा है। यात्रियों के लिए बेगमपुरा एक्सप्रेस और कोलकाता एक्सप्रेस प्रमुख विकल्प हैं। विशेष ट्रेन का आदेश रद्द होने के बाद भी इन दोनों ट्रेनों का नियमित संचालन जारी रहेगा।

बेगमपुरा एक्सप्रेस रोजाना : बेगमपुरा एक्सप्रेस प्रतिदिन जम्मू तवी से दोपहर 1:45 बजे रवाना होती है। करीब 22 घंटे 45 मिनट का सफर तय करने के बाद ट्रेन अगले दिन दोपहर 12:30 बजे वाराणसी पहुंचती है। इस ट्रेन से जम्मू और वाराणसी के बीच बड़ी संख्या में यात्री यात्रा करते हैं।

कोलकाता एक्सप्रेस भी विकल्प: कोलकाता एक्सप्रेस भी जम्मू तवी से प्रतिदिन चलती है। यह ट्रेन रात करीब 8:30 बजे जम्मू तवी से रवाना होकर लगभग 28 घंटे 30 मिनट की यात्रा के बाद वाराणसी जंक्शन पहुंचती है। रेलवे की ओर से विशेष ट्रेन का आदेश रद्द किए जाने के बाद यात्रियों को वाराणसी जाने के लिए नियमित ट्रेनों की सेवाओं पर निर्भर रहना होगा।

◆ यात्रियों को नियमित ट्रेनों से करना होगा सफर

सावलकूट परियोजना के लिए पांच कंपनियों ने लगाई बोली

पांच कंपनियों ने 5,129 करोड़ रुपये के पैकेज की बोली लगाई, तीन जिलों में होगा परियोजना का निर्माण

भारतेंदु संवाददाता, श्रीनगर। चिनाब नदी पर प्रस्तावित जम्मू-कश्मीर की सबसे बड़ी 1,850 मेगावाट क्षमता वाली सावलकूट जलविद्युत परियोजना के निर्माण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बढ़ा है। राष्ट्रीय जलविद्युत निगम (एनएचपीसी) ने परियोजना के प्रथम पैकेज के लिए 5,129 करोड़ रुपये की निविदा प्रक्रिया में पांच प्रमुख कंपनियों की बोलियां खोली हैं। इनमें अडानी इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, पटेल इंजीनियरिंग लिमिटेड, लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड और रित्विक प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड शामिल हैं।

नौ वर्ष में पूरा होगा पहला पैकेज: एनएचपीसी ने बुधवार को प्रथम पैकेज की बोली प्रक्रिया शुरू की। कई बार समयसीमा बढ़ने और देरी के बाद यह प्रक्रिया दोपहर तीन बजे शुरू हुई। प्रथम पैकेज में मुख्य रूप से सिविल और हाइड्रो-मैकेनिकल कार्य शामिल हैं।

चार दशक से लंबित है परियोजना

चिनाब नदी पर प्रस्तावित सावलकूट परियोजना लंबे समय से अटकी हुई है। प्रशासनिक अड़चनों, पर्यावरण संबंधी चिंताओं और पाकिस्तान की आपत्तियों के कारण परियोजना को करीब चार दशक तक आगे बढ़ाने में मुश्किलें आती रहीं। वर्ष 2025 में भारत-पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि के निलंबन के बाद केंद्र सरकार ने पश्चिमी नदियों पर जलविद्युत परियोजनाओं को गति देने पर जोर दिया।

मंजूरियों के बाद शुरू होगा निर्माण

अधिकारियों के अनुसार, परियोजना का निर्माण कार्य औपचारिक रूप से शुरू करने से पहले सार्वजनिक निवेश बोर्ड से मंजूरी और उसके बाद आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति की स्वीकृति मिलना बाकी है। स्वीकृतियां मिलने के बाद परियोजना के निर्माण की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।

बडगाम में तेंदुए के हमले से 16 भेड़ें मरीं 17 घायल, पशुपालक ने मांगा मुआवजा

बाडीपोरा गांव में बाड़े में घुसकर जंगली जानवर ने भेड़ों पर किया हमला

भारतेंदु संवाददाता, बडगाम। बडगाम जिले के चाडूरा इलाके में बुधवार और गुरुवार की दरमियानी रात तेंदुए के हमले की आशंका से पशुपालक को भारी नुकसान हुआ। चाडूरा के बाडीपोरा गांव में एक पशु बाड़े में घुसे जंगली जानवर ने भेड़ों के झुंड पर हमला कर दिया। इस घटना में 16 भेड़ों की मौत हो गई, जबकि 17 अन्य घायल हो गईं। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है।

भेड़ों के मालिक इम्तियाज अहमद चोपन ने बताया कि रात के समय जंगली जानवर पशुओं के बाड़े में घुस आया और भेड़ों के झुंड पर हमला कर दिया। हमले में कई भेड़ों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कई घायल हो गईं। चोपन ने आशंका जताई कि हमला तेंदुए ने किया है, हालांकि अभी तक संबंधित विभाग की ओर से हमलावर जानवर की पहचान की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। घटना की जानकारी मिलने के बाद इलाके के लोग भी मौके पर पहुंचे।

इम्तियाज अहमद चोपन ने बताया कि उनका परिवार अपनी आजीविका के लिए पशुपालन पर निर्भर है। भेड़ों की मौत और बड़ी संख्या में पशुओं के घायल होने से उन्हें काफी आर्थिक नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि पशुधन उनके परिवार की आय का प्रमुख साधन है और इस घटना से रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने में भी परेशानी सामने आ सकती है।

जांच के बाद होगी स्थिति स्पष्ट

स्थानीय लोगों ने सरकार से प्रभावित पशुपालक को जल्द राहत देने की भी मांग की है। फिलहाल तेंदुए के हमले की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। वन्यजीव विभाग की जांच और घटनास्थल के निरीक्षण के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि भेड़ों पर हमला तेंदुए ने किया था।

हीरानगर में खैर की लकड़ी के 29 लट्ठे जब्त

भारतेंदु संवाददाता, हीरानगर। कठुआ वन मंडल ने तस्करी विरोधी अभियान के दौरान हीरानगर के तरनाह ब्लॉक स्थित छन्न चकरी क्लोजर से खैर की लकड़ी के 29 लट्ठे बरामद किए। जब्त लकड़ी की मात्रा 0.93689 घन मीटर बताई गई है। वन विभाग को खैर के पेड़ों की अवैध कटाई की सूचना मिली थी, जिसके बाद टीम ने तड़के करीब तीन बजे तरनाह नदी के पास तलाशी अभियान चलाया। अभियान के दौरान लकड़ी ले जा रहे दो वाहनों में सवार संदिग्धों ने कथित तौर पर वन कर्मियों पर 10 से 15 राउंड फायरिंग की और अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए। सूचना मिलने के बाद पुलिस ने मौके से करीब एक किलोमीटर दूर दोनों वाहन मारुति ओमनी और मारुति वैगनआर को कब्जे में ले लिया। वन विभाग, वन सुरक्षा बल और पुलिस की संयुक्त टीम ने तलाशी के दौरान नदी के तल और आसपास से खैर के 29 लट्ठे बरामद किए।

URANIUM CORPORATION OF INDIA LIMITED
(A Government of India Enterprise)
PO: Jaduguda Mines, Distt.: Singhbhum (East), Jharkhand - 832102
website www.uraniumcorp.in

ADVERTISEMENT NO. 12/2026

UCIL invites applications from Indian citizens latest by 15-09-2026 for the following post on contract basis:
The eligibility criteria & **job specifications of the post are as under:**

1.	**POST NAME**	Senior Expert (HRM/Amdinistration)	
2.	**NO. OF POST**	01(One)	
3.	**REMUNERATION**	**Category of Employee**	**Consolidated Monthly Emoluments**
		Retired from CPSE in the Scale of Rs.1,00,000 -2,60,000/-(IDA) and above	Rs.1,00,000/-(Rs One Lakh) per month
		Retired from Central Govt. in the level 13 i.e. Rs.1,23,100 - 2,15,900/-(CDA) and above	Rs.1,00,000/- minus monthly Basic Pension drawn at the time of retirement from Government service.
4.	**ELIGIBILITY CRITERIA**	a) **Age:** Not more than 65 years (as on closing date of receiving application) b) **Qualification:** Retired Officers having Post Graduate Diploma in Personnel Management and Industrial Relation or MBA(HRM) or MSW from a Government recognized University. Desirable: Candidate having Degree in Law will be preferred Should have retired from the regular post in Government/PSU in the scale of pay of Rs.1,00,000/-2,60,000/-(IDA) & above or Level 13 Rs. 1,23,100 - 2,15,900/-(CDA) & above. **Post Qualification Experience:** Should have minimum 20years of working experience in Government/PSUs/ Autonomous Organization. Experience in the field of HRM/Administration shall be preferred.	
5.	**DUTIES & RESPONSIBILITY**	The duties and responsibilities includes (but not limited to) providing expert opinions on HRM issues, RTI issues, conduct-Discipline and Appeal matters, Liaising with Govt. Agencies/ Autonomous Bodies including Ministries, Employee related legal issues, PSU Policies, Corporate Governance and Administrative matters pertaining to CPSES.	
6.	**PROCEDURE FOR APPLYING:**	Eligible and interested Retired Officers of Govt./PSU may apply online through recruitment portal of UCIL by visiting UCIL. website **www.uraniumcorp.in** for the post of **Senior Expert (HRM/Administration)** latest by **15.09.2026** without which application will be rejected.	

cbc 48134/11/0039/2627

प्राकृतिक संतुलन बिगाड़कर खुद विनाश की राह बना रहा हिमाचल

तुलसी राम डोगरा
स्वतंत्र लेखक, पालमपुर

हिमाचल प्रदेश विगत कुछ वर्षों से मानसून के दौरान भीषण प्राकृतिक आपदाओं का सामना कर रहा है। हर वर्ष बादल फटना, पहाड़ दरकना, भूस्खलन, बाढ़ और उफनते नदी-नाले राज्य के जनजीवन को अस्त-व्यस्त कर रहे हैं। लोगों के आशियाने उजड़ रहे हैं, करोड़ों रुपए की संपत्ति नष्ट हो रही है तथा विकास कार्य लगातार प्रभावित हो रहे हैं। बरसात का मौसम आते ही प्रदेशवासियों के मन में भय और असुरक्षा का वातावरण व्याप्त हो जाता है कि न जाने इस बार प्रकृति किस रूप में कहर बरपाएगी।

गत 21 जुलाई को कांगड़ा जिले के शाहपुर उपमंडल की बोह घाटी में बादल फटने से 150 से अधिक परिवार बेघर हो गए। राहत की बात यह रही कि कोई जनहानि नहीं हुई। जिला प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई करते हुए प्रभावित परिवारों को राहत शिविरों में सुरक्षित स्थानांतरित कर उनके रहने और भोजन की समुचित व्यवस्था की, जो प्रशंसनीय है, किंतु जिन लोगों ने वर्षों की मेहनत से अपने घर बनाए थे, वे कुछ ही क्षणों में मलबे में तब्दील हो गए। विशेषकर बुजुर्गों की आंखों के सामने जीवनभर की कमाई उजड़ती देखना अत्यंत पीड़ादायक है।

वर्ष 2023 और 2025 की भीषण वर्षा, बादल फटने, भूस्खलन और जलप्रलय ने भी प्रदेश को गहरे जख्म दिए। अनेक लोगों की मृत्यु हुई, कई आज भी लापता हैं और हजारों परिवारों के आशियाने नष्ट हो गए। गत वर्ष मंडी जिले के डयोड क्षेत्र में धरती फटने से विशाल गड्ढे बन गए तथा कई मकानों में दरारें पड़ गईं। वहीं बिलासपुर जिले के बरठी क्षेत्र में भूस्खलन से हुई बस दुर्घटना में अनेक लोगों की असामयिक मृत्यु ने पूरे प्रदेश को झकझोर दिया। समेज की विनाशकारी बाढ़ में भी कई लोगों ने अपने प्राण गंवाए और अनेक शव आज तक नहीं मिल सके। प्रश्न यह है कि क्या प्रकृति से निरंतर हो रही छेड़छाड़ का दुष्परिणाम हमें इस रूप में भुगतना पड़ रहा है? विकास के नाम पर पहाड़ों का अंधाधुंध कटान, फोरलेन निर्माण, अवैज्ञानिक निर्माण कार्य, जंगलों की कटाई, नदियों-नालों में बेतरतीब खनन तथा प्राकृतिक संतुलन से खिलवाड़ कहीं इन आपदाओं की तीव्रता बढ़ाने के कारण तो नहीं बन रहे? शांत और हरित पर्वतों का सीना छलनी कर हम स्वयं विनाश को आमंत्रित कर रहे हैं। बुजुर्गों का मानना है कि देवभूमि के प्राकृतिक और सांस्कृतिक संतुलन की उपेक्षा भी चिंताजनक है। चाहे इसे आस्था मानें या वैज्ञानिक दृष्टि से पर्यावरणीय असंतुलन, दोनों ही हमें प्रकृति के प्रति संवेदनशील बनने का संदेश देते हैं। आज प्रदेश का शायद ही कोई जिला हो जो मानसून के प्रकोप से अछूता हो। मंडी, कांगड़ा, कुल्लू-मनाली, चंबा, शिमला, रामपुर बुशहर और लाहौल-स्पीति सहित अनेक क्षेत्रों में हर वर्ष भारी वर्षा और भूस्खलन जनजीवन को प्रभावित कर रहे हैं। सड़कें, पुल, विद्युत एवं संचार व्यवस्था, जलापूर्ति, पावर प्रोजेक्ट और वन संपदा व्यापक नुकसान झेल रहे हैं। इससे विकास परियोजनाओं में भी लगातार विलंब हो रहा है।

समय की मांग है कि पर्यावरणविदों, भू-वैज्ञानिकों, भारतीय मौसम विभाग, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण तथा संबंधित विशेषज्ञों द्वारा इन आपदाओं के कारणों पर गहन एवं वैज्ञानिक अध्ययन किया जाए। साथ ही अवैज्ञानिक निर्माण, अंधाधुंध खनन और प्रकृति के असीम दोहन पर कठोर नियंत्रण लगाया जाए। विकास आवश्यक है, किंतु प्रकृति के संतुलन की कीमत पर नहीं। यदि हमने समय रहते प्रकृति की चेतावनी को नहीं समझा, तो यह देवभूमि निरंतर विनाश की ओर बढ़ती जाएगी। प्रकृति बार-बार हमें संकेत दे रही है कि उसके नियमों का सम्मान करें, अन्यथा उसके रौद्र रूप का सामना करने के लिए सदैव तैयार रहना होगा।

(ये लेखक के निजी विचार हैं)

अंग्रेजी माध्यम की जल्दबाजी में कहीं कमजोर न पड़ जाए बच्चों की बुनियादी शिक्षा

डॉ. राकेश शर्मा, सहायक आचार्य, एचपीयू शिमला

हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में अंग्रेजी माध्यम को लागू करने का निर्णय पहली दृष्टि में आधुनिक, आकर्षक और प्रतिस्पर्धी शिक्षा व्यवस्था की दिशा में उठाया गया कदम प्रतीत हो सकता है, लेकिन जब इस निर्णय को बाल मनोविज्ञान, शैक्षिक सिद्धांतों, ग्रामीण परिस्थितियों और विद्यालयों की वास्तविक स्थिति के संदर्भ में देखा जाता है, तो इसके गंभीर दुष्परिणाम सामने आने लगते हैं।

शिक्षा का उद्देश्य बच्चों को ज्ञान, समझ और चिंतन की क्षमता प्रदान करना होता है, न कि केवल किसी विदेशी भाषा में दक्ष बनाना। दुर्भाग्यवश, अंग्रेजी माध्यम लागू करने की होड़ में इस मूल उद्देश्य को कहीं पीछे छोड़ दिया गया है। वर्ष 2018 में हिमाचल प्रदेश सरकार ने चरणबद्ध तरीके से सरकारी स्कूलों में अंग्रेजी माध्यम लागू करने की घोषणा की थी। शुरुआत पहली कक्षा से की गई, लेकिन बाद के वर्षों में यह व्यवस्था अन्य कक्षाओं तक विस्तारित कर दी गई। परिणामस्वरूप कई विद्यालयों में दूसरी, तीसरी और चौथी कक्षाओं के विद्यार्थियों को अचानक गणित, पर्यावरण अध्ययन तथा अन्य विषय अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाए जाने लगे। जिन बच्चों ने प्रारंभिक शिक्षा हिंदी माध्यम में आरंभ की थी, उन्हें बीच शैक्षणिक यात्रा में ही अंग्रेजी माध्यम में ढालने का प्रयास किया गया। यह परिवर्तन न तो स्वाभाविक था और न ही शैक्षिक दृष्टि से उचित। यूनेस्को, यूनिसेफ तथा विश्वभर के शिक्षा विशेषज्ञ लंबे समय से इस बात पर बल देते आए हैं कि प्रारंभिक शिक्षा मातृभाषा अथवा स्थानीय भाषा में ही होनी चाहिए। भारत की राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी कम-से-कम कक्षा पांच तक मातृभाषा या स्थानीय भाषा में शिक्षा देने की अनुशंसा करती है। इसका कारण स्पष्ट है। जब कोई पांच या छह वर्ष का बच्चा विद्यालय में प्रवेश करता है, तब उसकी समझ, अभिव्यक्ति और अनुभवों की दुनिया उसकी मातृभाषा से निर्मित होती है। यदि उसी समय उस पर एक नई भाषा को माध्यम बनाकर शिक्षा थोपी जाए, तो उसका ध्यान विषयवस्तु को समझने के बजाय भाषा को समझने में लग जाता है। इससे सीखने की प्रक्रिया कमजोर हो जाती है। हिमाचल प्रदेश के ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्रों में स्थिति और भी चुनौतीपूर्ण है।

अधिकांश बच्चे घरों में हिंदी, पहाड़ी या जनजातीय बोलियों के माध्यम से संवाद करते हैं। ऐसे बच्चों को अचानक अंग्रेजी माध्यम में गणित, विज्ञान और सामाजिक विषय पढ़ाना उनके लिए दोहरी कठिनाई पैदा करता है। पहले उन्हें भाषा समझनी पड़ती है और फिर विषय। परिणामस्वरूप वे न भाषा में दक्ष हो पाते हैं और न ही विषयों की मूल अवधारणाओं को सही ढंग से समझ पाते हैं। इस पूरी प्रक्रिया का सबसे चिंताजनक पहलू यह है कि नीति निर्माण और जमीनी वास्तविकताओं के बीच भारी अंतर दिखाई देता है। सरकार ने आदेश तो जारी कर दिए, लेकिन क्या विद्यालयों को इसके लिए तैयार किया गया था? क्या सभी शिक्षकों को पर्याप्त प्रशिक्षण मिला? क्या अंग्रेजी माध्यम की गुणवत्तापूर्ण पाठ्यपुस्तकें, शिक्षण सामग्री और संसाधन उपलब्ध कराए गए?

क्या बच्चों और अभिभावकों को इस परिवर्तन के लिए मानसिक रूप से तैयार किया गया? इन प्रश्नों के उत्तर अधिकांश मामलों में नकारात्मक हैं। वास्तविकता यह है कि अनेक विद्यालयों में हिंदी माध्यम से शिक्षण करने वाले शिक्षकों को कुछ औपचारिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों के बाद अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाने की जिम्मेदारी सौंप दी गई। एक शिक्षक जो वर्षों से हिंदी में पढ़ा रहा हो, उससे यह अपेक्षा करना कि वह कुछ दिनों की कार्यशाला के बाद अंग्रेजी में गणित, विज्ञान और अन्य विषयों को उसी दक्षता से पढ़ाने लगेगा, व्यवहारिक नहीं है।

परिणामस्वरूप कई स्थानों पर शिक्षक स्वयं असहज हैं और विद्यार्थी भ्रमित। इस स्थिति के लिए केवल राजनीतिक नेतृत्व ही नहीं, बल्कि शिक्षा विभाग की अफसरशाही भी समान रूप से जिम्मेदार है। शिक्षा से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय सचिवालय और निदेशालय के वातानुकूलित कार्यालयों में बैठकर लिए जाते हैं, जबकि इन निर्णयों का प्रभाव दूरस्थ ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्रों के बच्चों पर पड़ता है। नीति बनाने वाले अधिकारी शायद ही कभी यह समझने का प्रयास करते हैं कि एक बहुस्तरीय कक्षा में पढ़ाने वाला शिक्षक किन चुनौतियों का सामना करता है या सीमित संसाधनों वाले विद्यालय में पढ़ने वाला बच्चा किस प्रकार सीखता है।

(ये लेखक के निजी विचार हैं)

संपादकीय

ब्रिक्स की असली परीक्षा

नई दिल्ली में 12 और 13 सितंबर को होने वाला ब्रिक्स शिखर सम्मेलन इस बहुपक्षीय संगठन के लिए महत्वपूर्ण अवसर है। स्थापना के 20 वर्ष पूरे कर रहा यह मंच अब उस मुकाम पर पहुंच चुका है, जहां उसकी सफलता का आकलन केवल घोषणाओं और बैठकों की संख्या से नहीं, बल्कि सदस्य देशों के बीच वास्तविक सहयोग और धरातल पर दिखने वाले परिणामों से किया जाना चाहिए। वर्ष 2006 में स्थापना के समय ब्रिक्स से बहुत बड़ी उम्मीदें नहीं थीं, लेकिन दो दशकों में इसका विस्तार और बढ़ता प्रभाव उल्लेखनीय रहा है।

आज विश्व की लगभग आधी आबादी और वैश्विक जीडीपी के करीब 40 प्रतिशत हिस्से का प्रतिनिधित्व करने वाला ब्रिक्स अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था में महत्वपूर्ण स्थान बना चुका है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता इसकी विविधता है। भारत और चीन के बीच रणनीतिक प्रतिस्पर्धा के बावजूद दोनों इस मंच पर सहयोग करते हैं। इसी तरह ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात जैसे क्षेत्रीय प्रतिद्वंद्वी भी साझा हितों के मुद्दों पर एक मंच पर आते हैं। यही विविधता ब्रिक्स को किसी एक विचारधारा तक सीमित होने के बजाय व्यावहारिक सहयोग का लचीला मंच बनाती है।

भारत की अध्यक्षता में इस दिशा में व्यापक प्रयास किए गए। देश के 30 शहरों में 35 से अधिक विषयों पर 350 से ज्यादा बैठकें आयोजित की गईं। इनमें केंद्र और राज्य सरकारों के साथ उद्योग, शोध संस्थानों तथा समाज के विभिन्न वर्गों की भागीदारी रही। इसका उद्देश्य केवल औपचारिक घोषणाओं तक सीमित रहने के बजाय ऐसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाना था, जिनका सीधा संबंध आर्थिक विकास और आम लोगों के जीवन से है। लॉजिस्टिक्स, ऊर्जा भंडारण, छोटे उद्योगों की वैश्विक पहुंच, नए उद्यमों के लिए पूंजी, सीमा शुल्क प्रक्रिया और जलवायु संकट जैसे विषयों को प्राथमिकता मिलना इसी सोच का हिस्सा है।

भारत ने आयुष, पारंपरिक चिकित्सा और मानसिक स्वास्थ्य जैसे विषयों को भी ब्रिक्स के विमर्श में स्थान दिया है। इससे संगठन का दायरा केवल व्यापार और अर्थव्यवस्था तक सीमित नहीं रहा, बल्कि मानव-केंद्रित विकास की ओर भी बढ़ा है। प्रधानमंत्री मोदी की 'मानवता सर्वोपरि' की सोच से जुड़ा यह दृष्टिकोण ब्रिक्स को विकासशील देशों की साझा आवश्यकताओं से जोड़ने में उपयोगी साबित हो सकता है।

शिखर सम्मेलन में डॉलर पर निर्भरता कम करने की चर्चा भी महत्वपूर्ण होगी। इसका अर्थ तत्काल किसी साझा मुद्रा का निर्माण करना नहीं है। फिलहाल ऐसी साझा मुद्रा के लिए आवश्यक आर्थिक सहमति और संप्रभुता से जुड़े समझौते कठिन दिखाई देते हैं। व्यावहारिक रास्ता यही है कि चुनिंदा द्विपक्षीय व्यापार में स्थानीय मुद्राओं का इस्तेमाल बढ़े, डिजिटल भुगतान प्रणालियों को जोड़ा जाए और वित्तीय संसाधनों तक सदस्य देशों की पहुंच आसान बनाई जाए। इससे अंतरराष्ट्रीय व्यापार में विकल्प बढ़ेंगे और किसी एक मुद्रा या बाजार पर अत्यधिक निर्भरता घटाने में मदद मिल सकती है।

ब्रिक्स के सामने एक और बड़ी चुनौती न्यू डेवलपमेंट बैंक की प्रभावशीलता बढ़ाने की है। भारत में बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए बैंक ने उल्लेखनीय वित्तीय सहायता दी है, लेकिन वैश्विक स्तर पर उसकी क्षमता अभी विश्व बैंक और एशियाई विकास बैंक जैसी संस्थाओं से काफी पीछे है। यदि ब्रिक्स को प्रभावी आर्थिक मंच बनाना है तो एनडीबी की ऋण प्रक्रिया को सरल, तेज और अधिक व्यापक बनाना होगा। स्थानीय मुद्राओं में वित्त पोषण बढ़ाना भी इस दिशा में उपयोगी कदम हो सकता है।

व्यापारिक प्रतिबंधों और ऊंचे टैरिफ के दौर में ब्रिक्स की भूमिका और महत्वपूर्ण हो जाती है। सदस्य देशों को अपनी आपूर्ति श्रृंखलाओं, व्यापार मार्गों और भुगतान प्रणालियों में विविधता लाने पर ध्यान देना होगा। यही व्यावहारिक सहयोग इस संगठन को वैश्विक आर्थिक अस्थिरता के बीच अधिक उपयोगी बना सकता है।

अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि भारत की अध्यक्षता में शुरू हुई पहलों का भविष्य क्या होगा। अगले वर्ष चीन को अध्यक्षता मिलने के बाद क्या इन प्रयासों को निरंतरता मिलेगी और क्या वे स्थायी संस्थागत ढांचे का रूप ले पाएंगे? यही ब्रिक्स की वास्तविक परिपक्वता की परीक्षा होगी। नई दिल्ली शिखर सम्मेलन की सफलता भी इसी आधार पर मापी जानी चाहिए कि बैठकों और घोषणाओं के बाद जमीन पर कितना बदलाव आया। यदि सदस्य देश अपनी विविधताओं के बावजूद ठोस आर्थिक, तकनीकी और मानवीय सहयोग को आगे बढ़ाते हैं, तो ब्रिक्स आने वाले वर्षों में वैश्विक व्यवस्था का और प्रभावशाली तथा उपयोगी मंच बन सकता है।

-शिवांश धाकड़

कविता

खामोशी

डॉ. उर्मिल कौंडल, टीजीटी, नॉन मेडिकल, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय टावा, त. बल्ह, जिला मंडी

आंख खुलते ही पाया, खुद को उस कैद में दम घुट रहा था जहां,
मानो किसी ने अंधेरी कोठरी में लाकर धकेल दिया हो।।
जहां अंधेरे और खामोशी के शिवाय कुछ भी नहीं
काले नाग की तरह डसती है
यह खामोशी और अंधेरा...।
अच्छा लगता था उजाला कभी मुझे भी,
अच्छी लगती थी वो रंगीन सुबह जो संकेत देती थी
एक सुखद दिन का....।
अजीब सा अहसास होता था तब,
लेकिन इस उजाले को
अंधेरे में बदल डाला उन दरिंदों ने,
जो इंसान के भेष में भेड़िए
बन बैठे हैं,
अपनी प्यास बुझाने की खातिर दूसरों का खून चूसते हैं।
न जाने कितनी नारियों को,
सफेद कफन पहना दिया होगा इन जालिमों ने।
क्या वे कभी यह नहीं सोचते कि जिंदगी का इतना लंबा सफर
कैसे तय कर पाएंगी वे अकेली?
कैसे सहन कर पाएंगी वे लोगों की नफरत भरी निगाहें?
अब आदत सी हो गई है
उन्हें सहने की यह सब
खामोशी भी जड़ हो गई है
उस हिमालय की तरह जो
बर्फ की सफेद चादर ओढ़े शांत
और स्थिर खड़ा है सदियों से.....।

छात्र आंदोलन की आड़ में राजनीतिक एजेंडा या वास्तव में अधिकारों की लड़ाई?

शिशु गुप्ता
राजनीतिक विश्लेषक

आज देश के सामने सबसे बड़ा प्रश्न यह नहीं है कि कोई संगठन प्रदर्शन क्यों कर रहा है? लोकतंत्र में विरोध करना प्रत्येक नागरिक का संवैधानिक अधिकार है। वास्तविक प्रश्न यह है कि विरोध की दिशा क्या है, उसकी भाषा कैसी है और उसका अंतिम उद्देश्य क्या है?

यदि कोई आंदोलन वास्तव में छात्रों के अधिकारों के लिए है, तो उसके केंद्र में शिक्षा, रोजगार, शोध, छात्रवृत्ति और विश्वविद्यालयों की समस्याएं दिखाई देनी चाहिए, लेकिन जब प्रदर्शन का स्वरूप धीरे-धीरे राजनीतिक नारों, उत्तेजक भाषणों और अशोभनीय अभिव्यक्तियों में बदलने लगे, तब यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि क्या यह अब भी छात्र हित का आंदोलन है या किसी व्यापक राजनीतिक एजेंडे का हिस्सा बन चुका है। सबसे अधिक चिंता उस मानसिकता को लेकर है जो अभद्र भाषा, गाली-गलौज और सार्वजनिक अशिष्टता को आधुनिकता तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रतीक मान बैठी है। यह कैसी पीढ़ी तैयार की जा रही है, जो लोक-लाज को पिछड़ापन और अशिष्टता को साहस समझने लगी है? यदि शिक्षण संस्थानों से निकलने वाला शिक्षित वर्ग संवाद के स्थान पर अपशब्दों को अपनी पहचान बनाए, तो यह केवल शिक्षा व्यवस्था ही नहीं, सामाजिक संस्कारों पर भी प्रश्नचिन्ह है।

शिक्षा का उद्देश्य केवल डिग्री प्राप्त करना नहीं होता। शिक्षा व्यक्ति को विवेक, संयम, संवाद और मर्यादा सिखाती है। यदि शिक्षित होने का अर्थ केवल ऊंची आवाज, कटु भाषा और सामाजिक मर्यादाओं की अवहेलना रह जाए, तो हमें आत्ममंथन करना होगा कि कहीं हम ज्ञान के स्थान पर केवल सूचना तो नहीं बांट रहे। आधुनिक होना और असभ्य होना दो अलग-अलग बातें हैं। प्रगतिशील होना और सार्वजनिक जीवन में शालीनता बनाए रखना एक-दूसरे के विरोधी नहीं हैं। जो लोग अभद्रता को क्रांति और अशिष्टता को स्वतंत्रता का पर्याय बना रहे हैं, वे वास्तव में लोकतांत्रिक संवाद की गरिमा को कमजोर कर रहे हैं। यह भी विचारणीय है कि जिन शक्तियों ने लोकतांत्रिक चुनावों में जनता का विश्वास प्राप्त नहीं किया, वे कहीं ऐसे आंदोलनों को सरकार-विरोधी राजनीतिक मंच में बदलने का प्रयास तो नहीं कर रहीं। यह आरोप तभी सार्थक होगा जब उसके समर्थन में ठोस तथ्य हों; इसलिए किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले प्रमाणों और तथ्यों की जांच आवश्यक है, लेकिन यदि किसी आंदोलन का फोकस लगातार छात्र समस्याओं से हटकर केवल राजनीतिक टकराव पर केंद्रित होता जाए, तो जनता ऐसे प्रश्न अवश्य पूछेगी। भारत की युवा शक्ति से अपेक्षा है कि वह विचारों की लड़ाई विचारों से लड़े, तर्कों से लड़े, तथ्यों से लड़े। गाली-गलौज, अश्लील नारों और सामाजिक मर्यादाओं को तोड़कर कोई भी आंदोलन नैतिक विजय प्राप्त नहीं कर सकता। लोकतंत्र में असहमति आवश्यक है, लेकिन असहमति की भी एक संस्कृति होती है। जिस दिन विरोध की भाषा से शालीनता समाप्त हो जाती है, उसी दिन उसके नैतिक बल का क्षरण प्रारंभ हो जाता है। यदि छात्र आंदोलन वास्तव में छात्रों के लिए है, तो उसे छात्र हितों पर केंद्रित रहना होगा। यदि वह राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं का माध्यम बनता है, तो जनता उसे उसी दृष्टि से देखेगी। और यदि आधुनिकता के नाम पर मर्यादा, संस्कार और सभ्यता का उपहास उड़ाया जाएगा, तो यह न केवल शिक्षा की आत्मा का अपमान होगा, बल्कि उस भारतीय सांस्कृतिक चेतना का भी, जिसने सदियों से स्वतंत्रता और जिम्मेदारी-दोनों को साथ लेकर चलना सिखाया है।

(ये लेखक के निजी विचार हैं)

व्यक्तित्व विशेष

कई भाषाओं में छाईं श्रीया सरन

श्रीया सरन
जन्म : 11 सितंबर 1982

श्रीया सरन का फिल्मी सफर कई भाषाओं और अलग-अलग तरह की भूमिकाओं से होकर गुजरा है। 11 सितंबर 1982 को जन्मीं श्रीया सरन ने अभिनय की दुनिया में कदम रखने से पहले नृत्य को अपना करियर बनाने का सपना देखा था। वर्ष 2001 में तेलुगु फिल्म इष्टम से उन्होंने अपने अभिनय करियर की शुरुआत की। इसके बाद संतोषम ने उन्हें व्यावसायिक सफलता दिलाई और दक्षिण भारतीय फिल्म जगत में उनकी पहचान मजबूत होने लगी। उन्होंने तेलुगु के साथ तमिल और हिंदी फिल्मों में भी लगातार काम किया। हिंदी सिनेमा में उनकी शुरुआत तुझे मेरी कसम से हुई, जबकि आवारापन में उनके अभिनय को समीक्षकों ने सराहा। तमिल फिल्म शिवाजी में रजनीकांत के साथ काम करने के बाद उनकी लोकप्रियता और बढ़ी। यह फिल्म उस समय तमिल सिनेमा की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्मों में शामिल रही।

श्रीया सरन ने केवल भारतीय भाषाओं तक खुद को सीमित नहीं रखा। वर्ष 2008 में उन्होंने अंग्रेजी फिल्म द अदर एंड ऑफ द लाइन में मुख्य भूमिका निभाई। इसके बाद मिडनाइट्स चिल्ड्रन में उनके अभिनय को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी सराहना मिली। तेलुगु फिल्म मनम में उनके प्रदर्शन ने उन्हें आलोचनात्मक प्रशंसा दिलाई। वहीं दृश्यम और दृश्यम 2 जैसी फिल्मों ने उन्हें हिंदी दर्शकों के बीच एक बार फिर मजबूत पहचान दिलाई। गौतमिपुत्र सातकर्णी और आरआरआर जैसी फिल्मों में भी उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाईं।

श्रीया की खासियत यह रही कि उन्होंने अपने करियर में अलग-अलग भाषाओं, शैलियों और कलाकारों के साथ काम करते हुए खुद को एक ही तरह की भूमिकाओं तक सीमित नहीं किया। रोमांटिक फिल्मों से लेकर गंभीर और पारिवारिक कथानकों तक उन्होंने विविध किरदार निभाए। दक्षिण भारतीय सिनेमा में स्थापित पहचान बनाने के बाद हिंदी फिल्मों में भी उन्होंने अपनी अलग जगह बनाई। अभिनय के साथ उनका नृत्य के प्रति लगाव भी लगातार दिखाई देता रहा है।

परिवार के सपने पूरे करते-करते अपने सपनों को भूल जाता मध्यमवर्गीय आदमी

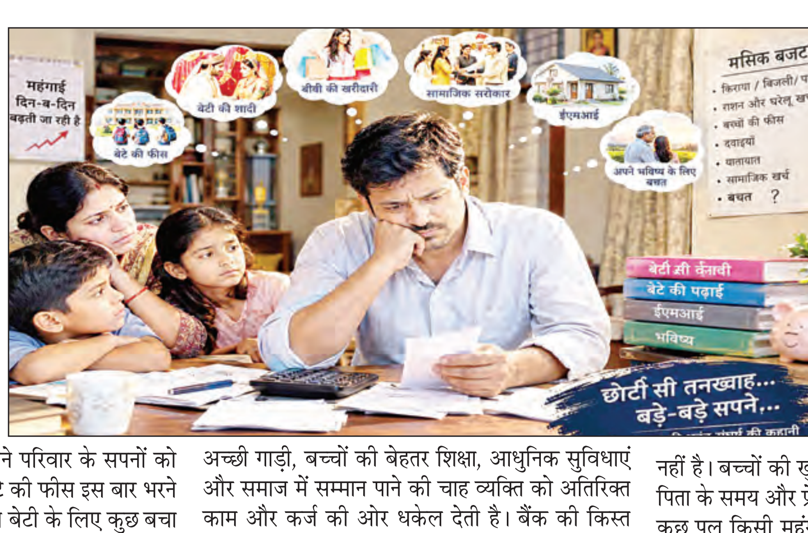

डॉ कौमार्या मनोज

'है छोटी सी तनख्वाह मेरी,
क्या-क्या इससे कर पाऊं मैं।
कौन जरूरत पूरी कर लूं,
किस जरूरत को दबाऊं मैं।'

ये पंक्तियां मध्यमवर्गीय परिवार के उस व्यक्ति की जिंदगी की पूरी कहानी बयां कर देती हैं, जो सीमित आय में असीमित जिम्मेदारियों को पूरा करने की कोशिश करता है। महंगाई के इस दौर में जब रोजमर्रा की जरूरतों से लेकर शिक्षा, स्वास्थ्य, मकान और सामाजिक दायित्व तक हर चीज महंगी होती जा रही है, तब एक आम आदमी की तनख्वाह महीने की शुरुआत में जितनी बड़ी दिखाई देती है, महीने के अंत तक उतनी ही छोटी लगने लगती है। वेतन हाथ में आते ही उसका हिसाब शुरू हो जाता है और जरूरतें एक-दूसरे के सामने खड़ी दिखाई देने लगती हैं।

एक मध्यमवर्गीय व्यक्ति दिन-रात मेहनत करता है। उसकी सबसे बड़ी चिंता अपने परिवार की खुशियां होती हैं। बेटे की फीस भरनी है, बेटी के भविष्य के लिए बचत करनी है, घर का राशन लाना है, पत्नी की जरूरी इच्छाएं पूरी करनी हैं, बुजुर्ग माता-पिता की जरूरतों का ध्यान रखना है और साथ ही भविष्य के लिए कुछ रकम बचानी है। इसके अलावा सामाजिक जिम्मेदारियां भी हैं। शादी-ब्याह, बीमारी, त्योहार और अचानक आने वाले खर्च उसकी आर्थिक योजना को कई बार पूरी तरह बिगाड़ देते हैं।

'जब मिलती तनख्वाह मुझे तो,
बैठे हिसाब-किताब लगाऊं मैं।
क्या खरीदूं, क्या न खरीदूं मैं,
मन को खुद बहलाऊं मैं।'

तनख्वाह मिलते ही व्यक्ति सबसे पहले हिसाब-किताब बैठाता है। मकान का किराया या कर्ज की किस्त, बच्चों की फीस, बिजली-पानी का बिल, राशन, यात्रा और दूसरी आवश्यकताओं का खर्च पहले ही तय होता है। इसके बाद बची रकम से वह अपने सपनों को पूरा करने की कोशिश करता है। कई बार किसी जरूरी सामान की खरीदारी टालनी पड़ती है। कभी परिवार की जरूरत को प्राथमिकता देकर अपनी इच्छा छोड़नी पड़ती है। इस तरह छोटी-छोटी इच्छाओं को टालते-टालते जीवन आगे बढ़ता जाता है।

मध्यमवर्गीय व्यक्ति की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि वह अपने परिवार के सपनों को अपने सपनों से ऊपर रखता है। बेटे की फीस इस बार भरने के बाद सोचता है कि अगले महीने बेटी के लिए कुछ बचा लूंगा। पत्नी के लिए जरूरी सामान खरीदते हुए मन में आता है कि अपनी जरूरत अगले महीने पूरी कर लूंगा। खुद के लिए नए कपड़े, घूमने-फिरने या मनोरंजन की योजनाएं अक्सर इसलिए टल जाती हैं क्योंकि परिवार की कोई दूसरी जरूरत सामने आ जाती है।

'बेटे की फीस इस बार भरूं मैं,
बेटी का अगली बार भरूंगा।
बीबी की मैं करवाऊं खरीदी,
अपनी अगली बार करूंगा।'

यह त्याग देखने में छोटा लगता है, लेकिन एक व्यक्ति के पूरे जीवन में ऐसे हजारों त्याग जमा होते जाते हैं। आज के दौर में जल्दी सब कुछ हासिल करने की इच्छा ने भी मध्यमवर्गीय जीवन को कठिन बना दिया है। अपना घर, अच्छी गाड़ी, बच्चों की बेहतर शिक्षा, आधुनिक सुविधाएं और समाज में सम्मान पाने की चाह व्यक्ति को अतिरिक्त काम और कर्ज की ओर धकेल देती है। बैंक की किस्त और उधार की रकम चुकाने की चिंता कई बार उसकी मानसिक शांति तक छीन लेती है।

समस्या केवल कम तनख्वाह की नहीं है। असली चुनौती सीमित आय और बढ़ती जरूरतों के बीच संतुलन बनाने की है। आम आदमी के सपने छोटे नहीं होते। वह भी अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देना चाहता है, परिवार को बेहतर जीवन देना चाहता है और अपने भविष्य को सुरक्षित करना चाहता है। लेकिन आय और खर्च के बीच बढ़ता अंतर उसके सपनों को लगातार चुनौती देता रहता है। महीने के शुरुआती दिनों में जेब भरी होती है तो उम्मीदें भी बड़ी होती हैं, लेकिन महीने का अंतिम सप्ताह आते-आते वही व्यक्ति खर्चों को लेकर चिंतित दिखाई देने लगता है।

ऐसे में जरूरी है कि हम अपनी आय के अनुसार जीवनशैली तय करें। जरूरत और इच्छा के बीच अंतर समझना होगा। हर चीज तुरंत हासिल करने की होड़ में खुद को कर्ज के बोझ तले दबाना समझदारी नहीं है। बच्चों की खुशियां महंगे सामान से अधिक माता-पिता के समय और प्रेम में होती हैं। परिवार के साथ बिताए कुछ पल किसी महंगी यात्रा से कम महत्वपूर्ण नहीं होते। इसलिए आर्थिक अनुशासन के साथ जीवन में संतुलन भी जरूरी है।

हमें यह भी समझना होगा कि जीवन केवल कमाने और खर्च करने का नाम नहीं है। काम जरूरी है, लेकिन परिवार के लिए समय, स्वास्थ्य, आराम और स्वयं के लिए कुछ पल भी उतने ही जरूरी हैं। यदि व्यक्ति सारी जिंदगी भविष्य को बेहतर बनाने के प्रयास में वर्तमान को ही भूल जाए तो भविष्य आने तक जीवन का बड़ा हिस्सा बीत चुका होगा। इसलिए सपने जरूर देखें, लेकिन अपनी चादर और अपनी हैसियत के अनुसार। छोटी तनख्वाह निश्चित रूप से दर्द देती है, लेकिन सीमित साधनों में भी संतुलित और खुशहाल जीवन संभव है।

(ये लेखक के निजी विचार हैं)

'भारतेन्दु शिखर

प्रकाशक, मुद्रक, संपादक एवं स्वामी शिवांश धाकड़ द्वारा शर्मा भवन, न्यू रणजीत नगर, एप्पल फ्रूट मंडी, नजदीक ढली टनल, शिमला (हि.प्र.) 171006 से प्रकाशित एवं बायोसर्ट इंटरनेशनल प्रा. लि. प्लॉट नंबर 8, फेज-2 इंडस्ट्रियल एरिया, नगरोटा बगवां, जिला कांगड़ा (हि.प्र.), पिन नंबर-176047 से मुद्रित। समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन के लिए पीआरबी एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी तथा इनसे उत्पन्न समस्त विवाद शिमला न्यायालय के अधीन होंगे।

आरएनआई संदर्भ संख्या-HPHIN/2000/02437
ई-मेल : bhartendunewsmedia@gmail.com, फोन नंबर : 88946-77702

एआई से दृष्टिबाधितों की राह होगी आसान, गोगल्स और ऐप से मिलेगी मदद

एजेंसी, मेरठ

कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) अब दृष्टिबाधित लोगों के लिए आसपास की दुनिया को समझने और आत्मनिर्भर बनने में मददगार साबित हो रही है। मेरठ में राष्ट्रीय दृष्टिबाधित संघ (एनएबी) के पुनर्वास एवं संसाधन केंद्र के शुभारंभ के दौरान एआई आधारित तकनीक का लाइव डेमो दिखाया गया। इसमें बताया गया कि विशेष गोगल्स और मोबाइल एप की मदद से दृष्टिबाधित व्यक्ति रास्ते की पहचान कर सकते हैं और आसपास की वस्तुओं के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। एआई से बातचीत के माध्यम से उपयोगकर्ता आवाज में अपने आसपास की स्थिति के बारे में सवाल पूछ सकता है। इसके जवाब भी उसे आवाज के जरिए मिलते हैं। सामने कौन व्यक्ति है, रास्ते में कोई बाधा तो नहीं, आसपास कौन सी वस्तु रखी है या किसी स्थान पर क्या मौजूद है, इसकी जानकारी तकनीक उपलब्ध करा सकती है। इससे अकेले आवागमन करने में दृष्टिबाधित लोगों को काफी मदद मिल सकती है।

लाइव डेमो के दौरान तकनीक के कई उपयोग बताए गए। एआई की सहायता से कंप्यूटर चलाने, दैनिक कामकाज समझने और रसोई से जुड़े कार्यों में भी मदद मिलने की संभावना है। इसका उद्देश्य दृष्टिबाधित लोगों को अधिक आत्मनिर्भर बनाना और उनकी रोजमर्रा की चुनौतियों को कम करना है। एनएबी मेरठ की ओर से दृष्टिबाधित लोगों को शिक्षा और तकनीकी प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। संस्था के अनुसार अब तक 3500 से अधिक दृष्टिबाधित लोगों को कंप्यूटर शिक्षा दी जा चुकी है। नई तकनीक को प्रशिक्षण और पुनर्वास कार्यक्रमों से जोड़कर उन्हें रोजगार और दैनिक जीवन में अधिक सक्षम बनाने पर जोर दिया जा रहा है। एआई आधारित सुविधाएं इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही हैं।

मायावती ने आकाश आनंद को पार्टी से बाहर किया, ईशान आनंद को मिली अहम जिम्मेदारी

आकाश आनंद की विदाई के बाद ईशान आनंद की बसपा में एंट्री

एजेंसी, लखनऊ

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच बहुजन समाज पार्टी में बड़ा बदलाव सामने आया है। पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने अपने बड़े भतीजे आकाश आनंद को बसपा से बाहर कर दिया है। साथ ही छोटे भतीजे ईशान आनंद को पार्टी में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी देकर सक्रिय राजनीति के बड़े मंच पर आगे बढ़ाया है। मायावती ने ईशान आनंद का सोशल मीडिया अकाउंट भी सार्वजनिक किया है।

मायावती ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के माध्यम से पार्टी में हुए बदलावों की जानकारी दी। इसके बाद राज्यसभा सदस्य रहे अशोक सिद्धार्थ ने सक्रिय राजनीति से संन्यास लेने का फैसला किया। मायावती ने उनके इस निर्णय पर प्रतिक्रिया देते हुए इसे 'देर आए, दुरुस्त आए' बताया। इसके बाद उन्होंने अशोक सिद्धार्थ के दामाद और अपने बड़े भतीजे आकाश आनंद को पार्टी से बाहर करने का फैसला किया। मायावती ने स्पष्ट किया कि आकाश आनंद अब पार्टी की गतिविधियों और जिम्मेदारियों से पूरी तरह स्वतंत्र हैं। इससे पहले भी आकाश आनंद को बसपा के पदों और जिम्मेदारियों से हटाया जा चुका था।

अब उन्हें पार्टी से बाहर किए जाने के बाद संगठन में उनकी भूमिका पूरी तरह समाप्त हो गई है। वहीं, ईशान आनंद को मायावती ने संगठन में आगे बढ़ाने का फैसला किया है। ईशान आनंद बसपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आनंद कुमार के छोटे बेटे और मायावती के छोटे भतीजे हैं। वह आकाश आनंद के छोटे भाई हैं। पिछले कुछ समय से पार्टी के भीतर ईशान आनंद की सक्रियता बढ़ती दिखाई दे रही थी।

ईशान आनंद को नई जिम्मेदारी दिए जाने के बाद मायावती ने उनका सोशल मीडिया अकाउंट भी सार्वजनिक किया। इसे उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी की नई रणनीति के संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। बसपा संगठन में बदलाव के साथ युवा नेतृत्व को आगे बढ़ाने पर भी जोर दे रही है। मायावती के इस फैसले से बसपा की आगामी चुनावी रणनीति में बदलाव की संभावना है। पार्टी अब नए सिरे से संगठन को मजबूत करने और चुनावी तैयारियों को गति देने में जुटी है।

आकाश आनंद को बाहर करने और ईशान आनंद को आगे लाने का फैसला ऐसे समय हुआ है, जब उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दल अपनी तैयारियां तेज कर रहे हैं। ईशान आनंद की राजनीतिक भूमिका आने वाले समय में कितनी बढ़ती है, इस पर भी राजनीतिक नजरें टिकी हैं। फिलहाल मायावती ने उन्हें संगठन में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी देकर सक्रिय भूमिका के लिए तैयार करने का संकेत दिया है।

कन्हैया की छठी पर भजनों से गूंजा राम मंदिर, कृष्ण भक्ति में झूमे श्रद्धालु

एजेंसी, मीरजापुर। चुनार नगर के गंगेश्वर नाथ स्थित राम मंदिर में बुधवार रात भगवान श्रीकृष्ण की छठी धूमधाम से मनाई गई। मंदिर परिसर को फूल-पत्तियों से सजाया गया था। विधि-विधान से पूजन और मंत्रोच्चार के बाद देर रात तक भजन संध्या का आयोजन हुआ। भजनों की धुन पर श्रद्धालु कृष्ण भक्ति में झूमते रहे।

मुख्य अतिथि श्री काशी विश्वनाथ मंदिर के अर्चक श्रीकांत मिश्र 'छोटे गुरुजी' ने कन्हैया का पूजन-अर्चन कराया। पूजन के बाद श्रद्धालुओं में प्रसाद वितरित किया गया। भजन संध्या में देवेंद्र झा और राघवेंद्र शर्मा ने भजनों की प्रस्तुति दी। 'नंद घर आनंद भयो' और 'श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारी' जैसे भजनों पर श्रद्धालु देर रात तक भक्तिरस में डूबे रहे। तबले पर सौरभ, नाल पर हिमांशु सिंह, पैड पर अंकित मिश्रा और कीबोर्ड पर गौरव ने संगत की। आयोजक वरिष्ठ अधिवक्ता शशिकांत मिश्र ने बताया कि हर वर्ष भगवान श्रीकृष्ण के जन्म के छठे दिन छठी महोत्सव आयोजित किया जाता है।

कार्यक्रम में कविता मिश्रा, अर्चा मिश्रा, योगेश पांडेय, शिवकांत पाठक, अनिल मिश्रा, मनीष राय, राजू यादव समेत बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। महिलाओं और बच्चों ने भी उत्साह से भाग लिया। चुनार कोतवाली परिसर में भी भगवान श्रीकृष्ण की छठी मनाई गई। पुजारी अनिल मिश्र ने पूजन कराया। आराधना मिश्रा और महिला कांस्टेबलों ने भजन-कीर्तन किया। इस दौरान कांस्टेबल विमलेश सिंह समेत अन्य पुलिसकर्मी मौजूद रहे। इस अवसर पर मंदिर में श्रद्धालुओं ने भगवान श्रीकृष्ण के जयकारे लगाए। भक्ति गीतों और कीर्तन से पूरा वातावरण भक्तिमय बना रहा। आयोजन के दौरान श्रद्धालुओं ने सुख-समृद्धि की कामना की और प्रसाद ग्रहण किया।

न्यूज ब्रीफ

जन्म-मृत्यु प्रमाणपत्र बनवाने में छूटे पसीने, देरी वाले आवेदनों पर सख्ती

एजेंसी, मेरठ। जन्म और मृत्यु प्रमाणपत्र बनवाने की प्रक्रिया में देरी होने पर लोगों की मुश्किलें बढ़ रही हैं। 21 दिनों के भीतर आवेदन करने पर नगर निगम स्तर पर प्रमाणपत्र आसानी से बन जाता है। इसके बाद देरी की अवधि के अनुसार सत्यापन की प्रक्रिया भी बदल जाती है। 21 दिन से एक साल तक देरी होने पर सीएमओ कार्यालय से सत्यापन कराना पड़ता है। एक से दो साल की देरी वाले आवेदनों के लिए एसडीएम स्तर से प्रक्रिया पूरी की जाती है। वहीं, दो साल से अधिक पुराने मामलों में प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट से सत्यापन कराने का नियम है। सबसे अधिक परेशानी दो साल से ज्यादा पुराने आवेदनों में सामने आ रही है। ऐसे आवेदकों को प्रमाणपत्र बनवाने के लिए अलग-अलग कार्यालयों में जाना पड़ रहा है। इससे समय और श्रम दोनों अधिक लग रहे हैं। नगर निगम में हर महीने औसतन चार हजार जन्म प्रमाणपत्र और करीब एक हजार मृत्यु प्रमाणपत्र के आवेदन आते हैं।

आगरा में मदरसे की मान्यता पर चल रहे अंग्रेजी माध्यम स्कूल, 73 को नोटिस

एजेंसी, आगरा। जिले में मदरसे की मान्यता लेकर अंग्रेजी माध्यम की कक्षाएं संचालित करने के आरोप में 73 संस्थानों को नोटिस जारी किए गए हैं। पड़ताल में कई जगह दोहरी व्यवस्था सामने आई। कुछ संस्थानों के बोर्ड पर हाईस्कूल, जबकि कुछ पर एजुकेशन अकादमी का नाम लिखा मिला। कई मदरसों में कोई बोर्ड भी नहीं लगा था। लड़ामदा स्थित एमएमएलयू हाईस्कूल के बोर्ड पर मदरसे का उल्लेख नहीं मिला। यहां प्लेग्रुप से कक्षा दसवीं तक पढ़ाई कराने का दावा किया जा रहा है। अधिकारियों की जांच में सामने आए इन मामलों के बाद संस्थानों से जवाब मांगा गया है। कुछ संचालकों ने आधुनिक शिक्षा देने की बात कही, जबकि कई संचालक जानकारी देने से बचते नजर आए। कुछ ने संस्थान बंद होने की भी बात कही।

अछनेरा स्टेशन पर वायुसेना जवान की ट्रेन से कटकर मौत

एजेंसी, आगरा। अछनेरा रेलवे स्टेशन पर बुधवार सुबह दर्दनाक हादसे में वायुसेना के जवान नैनाराम की ट्रेन से कटकर मौत हो गई। राजस्थान के नागौर निवासी नैनाराम प्रयागराज में वायुसेना में तैनात थे। वह पत्नी और बच्चों के साथ जोधपुर-हावड़ा एक्सप्रेस से प्रयागराज जा रहे थे। ट्रेन के अछनेरा स्टेशन पर रुकने के दौरान नैनाराम नीचे उतर गए। इसी दौरान वह ट्रेन की चपेट में आ गए और गंभीर हादसा हो गया। हादसे की जानकारी मिलते ही रेलवे और पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंचे। घटना के बाद परिवार में चीख-पुकार मच गई। बताया गया कि जवान अपने परिवार के साथ प्रयागराज लौट रहे थे। नैनाराम की तैनाती प्रयागराज में थी। हादसे की सूचना पर संबंधित अधिकारियों ने आवश्यक कार्रवाई शुरू की। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजने की प्रक्रिया की गई। जवान की मौत से परिवार और परिचितों में शोक का माहौल है। पुलिस ने घटना की परिस्थितियों की जांच शुरू कर दी है।

आजमगढ़ में किसानों को 90 दिन की मुफ्त मधुमक्खी पालन ट्रेनिंग

एजेंसी, आजमगढ़। किसानों की आय बढ़ाने और पर्यावरण संतुलन को बढ़ावा देने के लिए उद्यान विभाग 90 दिवसीय निःशुल्क वैज्ञानिक मधुमक्खी पालन प्रशिक्षण आयोजित करेगा। प्रशिक्षण 16 सितंबर से 15 दिसंबर तक औद्यानिक प्रयोग एवं प्रशिक्षण केंद्र बस्ती और राजकीय उद्यान चंद्रशेखर पार्क प्रयागराज में होगा। उप निदेशक एवं प्रभारी जिला उद्यान अधिकारी जयकरण सिंह ने बताया कि कम भूमि और कम पूंजी में अधिक आय देने वाले इस अनुपूरक उद्यम से किसान अतिरिक्त आमदनी हासिल कर सकते हैं। प्रशिक्षण में सभी वर्गों के पुरुष और महिला किसान या अभ्यर्थी भाग ले सकेंगे। इसके लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता आठवीं पास निर्धारित की गई है। इच्छुक अभ्यर्थी 16 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। प्रशिक्षण के दौरान किसानों को मधुमक्खी पालन की वैज्ञानिक तकनीक और व्यवसाय से जुड़ी जरूरी जानकारी दी जाएगी। विभाग का उद्देश्य किसानों को स्वरोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराने के साथ कृषि और बागवानी गतिविधियों को बढ़ावा देना है।

अमरोहा में जल प्रदूषण की जांच, लखनऊ से पहुंची टीम ने लिए 30 सैंपल

एजेंसी, गजरौला। औद्योगिक क्षेत्र में जल प्रदूषण की शिकायतों के बाद प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड लखनऊ की टीम ने बुधवार को विभिन्न क्षेत्रों का निरीक्षण किया। टीम में चीफ इंजीनियर, प्रोफेसर और अभियंता शामिल रहे। अधिकारियों ने नाईपुरा और बुधनगर में ग्रामीणों से बातचीत कर पानी की गुणवत्ता की जानकारी ली। ग्रामीणों ने बताया कि पानी के रंग में बदलाव दिखाई दे रहा है और इससे बीमारी फैलने की आशंका है। शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए टीम ने हैंडपंप समेत विभिन्न स्थानों से करीब 25 से 30 पानी के नमूने लिए। इसके बाद टीम अलीपुर भी पहुंची और वहां से भी पानी के नमूने लिए गए। अधिकारियों के क्षेत्र में पहुंचने के बाद औद्योगिक इकाइयों में भी हलचल देखी गई। लिए गए नमूनों की जांच के बाद पानी की गुणवत्ता की स्थिति स्पष्ट होगी।

दरोगाखेड़ा से भारी वाहनों की एंट्री बंद, रिंग रोड से होगा आवागमन

एजेंसी, लखनऊ

जुनाबगंज में राष्ट्रीय राजमार्ग पर नो-एंट्री प्वाइंट शुरू किए जाने के बाद अब दरोगाखेड़ा से स्कूटर्स इंडिया और गौरी की ओर जाने वाले भारी वाहनों के लिए भी यातायात व्यवस्था में बदलाव किया गया है। यातायात पुलिस ने दरोगाखेड़ा से भारी वाहनों की आवाजाही पर सात दिन के लिए ट्रायल के तौर पर रोक लगा दी है। यह व्यवस्था गुरुवार से लागू की गई है।

ट्रायल के दौरान सुबह छह बजे से रात 11 बजे तक भारी वाहनों को दरोगाखेड़ा से स्कूटर्स इंडिया और गौरी की तरफ जाने की अनुमति नहीं होगी। ऐसे वाहनों को निर्धारित वैकल्पिक मार्ग के रूप में रिंग रोड का इस्तेमाल करना होगा। यातायात पुलिस का उद्देश्य इस व्यवस्था के जरिए संबंधित मार्ग पर भारी वाहनों का दबाव कम करना और यातायात को सुचारु बनाए रखना है।

जुनाबगंज में राष्ट्रीय राजमार्ग पर नो-एंट्री व्यवस्था लागू होने के बाद दरोगाखेड़ा क्षेत्र में भी वाहनों के आवागमन को नियंत्रित करने की जरूरत महसूस की गई। इसी के तहत सात दिन का ट्रायल शुरू किया गया है। इस दौरान यातायात की स्थिति, वाहनों की संख्या और वैकल्पिक मार्ग पर पड़ने वाले दबाव का आकलन किया जाएगा। ट्रायल अवधि पूरी होने के बाद व्यवस्था की समीक्षा की जाएगी। इसके बाद यातायात पुलिस तय करेगी कि भारी वाहनों की नो-एंट्री को आगे भी जारी रखा जाए या इसमें बदलाव किया जाए।

यूपी चुनाव में पिछड़ों पर फोकस, कांग्रेस बनाएगी विशेष वार रूम

एजेंसी, लखनऊ

◆ **कांग्रेस** का अभियान केवल चुनावी मुद्दों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पिछड़ा वर्ग के लोगों से सीधा संपर्क बढ़ाने पर भी जोर होगा। वार रूम के जरिए स्थानीय समस्याओं और मांगों की जानकारी जुटाकर संगठन को मजबूत किया जाएगा। साथ ही पार्टी के संदेश को गांवों और कस्बों तक पहुंचाने के लिए कार्यकर्ताओं को सक्रिय किया जाएगा।

उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने पिछड़े वर्ग के मतदाताओं के बीच अपनी पकड़ मजबूत करने की रणनीति तैयार की है। पार्टी अब पिछड़ों को साधने के लिए विशेष अभियान चलाएगी। इसके तहत हर 10 जिले पर एक विशेष वार रूम स्थापित करने की तैयारी है। इन वार रूमों का संचालन कांग्रेस के पिछड़ा वर्ग विभाग की ओर से किया जाएगा। पार्टी की योजना इसी माह इन्हें स्थापित करने की है।

कांग्रेस की रणनीति के केंद्र में सामाजिक न्याय, आरक्षण, संविधान और 'जितनी आबादी-उतना अधिकार' जैसे मुद्दे रहेंगे। पार्टी इन विषयों को लेकर पिछड़े वर्ग के मतदाताओं के बीच पहुंचेगी और उन्हें अपनी विचारधारा से जोड़ने का प्रयास करेगी। वार रूम के माध्यम से संबंधित जिलों में अभियान की निगरानी और संगठनात्मक गतिविधियों को गति देने की तैयारी है।

उत्तर प्रदेश की राजनीति में पिछड़ा वर्ग महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। राज्य में अन्य वर्गों की तुलना में पिछड़े वर्ग के मतदाताओं की अनुमानित संख्या करीब 45 प्रतिशत बताई जाती है। इसी वजह से सभी प्रमुख राजनीतिक दल इस बड़े मतदाता वर्ग को अपने पक्ष में करने की कोशिश करते रहे हैं। कांग्रेस भी अब इसी दिशा में अपनी सक्रियता बढ़ा रही है।

पार्टी लंबे समय से सामाजिक न्याय और आरक्षण से जुड़े मुद्दों को उठाती रही है। अब चुनावी तैयारी के दौरान इन मुद्दों को पिछड़ा वर्ग तक पहुंचाने के लिए संगठनात्मक स्तर पर विशेष व्यवस्था की जा रही है। प्रत्येक 10 जिलों के समूह के लिए बनाए जाने वाले वार रूम में पिछड़ा वर्ग विभाग की भूमिका अहम रहेगी।

कांग्रेस का प्रयास केवल चुनावी मुद्दों तक सीमित रहने के बजाय पिछड़े वर्ग के लोगों के साथ संगठनात्मक संपर्क बढ़ाने का भी है। वार रूम के जरिए जिलों में होने वाली गतिविधियों को समन्वित करने और पार्टी के संदेश को ज्यादा प्रभावी तरीके से लोगों तक पहुंचाने की योजना है। पार्टी संविधान और सामाजिक न्याय के मुद्दों को भी अभियान का हिस्सा बनाएगी। 'जितनी आबादी-उतना अधिकार' के साथ आरक्षण से जुड़े विषयों को प्रमुखता देकर पिछड़े वर्ग के मतदाताओं को जोड़ने का प्रयास किया जाएगा।

कानपुर में एक्सपायर्ड सीरप बांटने का आरोप तथ्यहीन, सीएमओ ने किया खंडन

एजेंसी, कानपुर। कानपुर में बाढ़ पीड़ितों को एक्सपायर्ड सीरप बांटे जाने के आरोपों को मुख्य चिकित्सा अधिकारी इंद्रदेव सिंह ने तथ्यहीन बताया है। उन्होंने संबंधित खबर का पूरी तरह खंडन करते हुए कहा कि बाढ़ राहत शिविर में ऐसी कोई एक्सपायर्ड दवा वितरित नहीं की गई।

सीएमओ के अनुसार दो सितंबर को आयोजित बाढ़ राहत कैंप में ट्राइमेथोप्रिम एंड सल्फामेथॉक्साजोल आईपी सीरप का वितरण नहीं हुआ था। विभागीय स्तर पर मामले की जांच करने के बाद दवाओं के रिकॉर्ड और उपलब्ध स्टॉक की भी पड़ताल की गई। जांच में एक्सपायर्ड सीरप बांटे जाने के आरोप की पुष्टि नहीं हुई।

सीएमओ ने बताया कि राहत शिविर में उपलब्ध कराई गई दवाओं का रिकॉर्ड विभाग के पास मौजूद है। स्टॉक की स्थिति और विभागीय अभिलेख भी आरोपों से मेल नहीं खाते हैं। उन्होंने कहा कि बाढ़ प्रभावित लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए विभाग की ओर से शिविर लगाए गए थे। स्वास्थ्य विभाग ने स्पष्ट किया कि दवा वितरण में निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया जाता है।

कानपुर में सेवानिवृत्त सिंचाई कर्मी ने दी जान, सुसाइड नोट में बीमारी का जिक्र

एजेंसी, कानपुर। चकेरी थानाक्षेत्र के सनिगवां स्थित सावित्री नगर में गुरुवार सुबह सेवानिवृत्त सिंचाई विभाग कर्मी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतक की पहचान 72 वर्षीय रामरतन साहू के रूप में हुई है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार वह बीमारी को लेकर परेशान चल रहे थे। घटना के बाद एक सुसाइड नोट भी मिला है, जिसमें बीमारी के कारण यह कदम उठाने की बात लिखी गई है। परिजनों के अनुसार, गुरुवार सुबह रामरतन ने खुद को आग लगा ली। घटना की जानकारी मिलते ही स्वजन उन्हें उपचार के लिए कांशीराम अस्पताल लेकर पहुंचे। वहां चिकित्सकों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। अस्पताल प्रशासन की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जानकारी जुटाई।

पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पोस्टमार्टम हाउस में मृतक के स्वजन मौजूद हैं। पुलिस सुसाइड नोट की भी जांच कर रही है और यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि रामरतन किन स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों से जूझ रहे थे। फिलहाल पुलिस ने घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है। अधिकारियों का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के बाद ही मौत की परिस्थितियों के संबंध में स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। पुलिस परिजनों से भी घटना के संबंध में जानकारी जुटा रही है। मामले की जांच जारी है। पुलिस ने परिजनों से भी पूछताछ शुरू कर दी है। अधिकारियों के अनुसार पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के बाद ही मौत की परिस्थितियों को लेकर स्थिति स्पष्ट होगी।

संभल में गंगा का जलस्तर घटा, लेकिन गांवों में बाढ़ की दुश्वारियां अभी भी बरकरार

◆ **जलभराव से प्रभावित प्राथमिक विद्यालय, दूसरे स्थान पर पढ़ाई**

एजेंसी, संभल

नरौरा गंगा बैराज पर गुरुवार सुबह गंगा के जलस्तर में 0.02 मीटर की मामूली कमी दर्ज की गई। जलस्तर घटकर 177.86 मीटर पहुंच गया, लेकिन संभल के गुन्नौर और जुनावई क्षेत्र में बाढ़ प्रभावित गांवों की मुश्किलें कम नहीं हुई हैं। आधा दर्जन गांवों की सड़कें और खेत अब भी पानी से लबालब हैं। बाढ़ के पानी के कारण कई पुलिया जलमग्न हो गई हैं। इससे ग्रामीणों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

गांवों के संपर्क मार्गों पर पानी भरने से लोगों को आने-जाने में दिक्कत हो रही है। प्रशासन की ओर से प्रभावित क्षेत्रों पर नजर रखी जा रही है। जुनावई क्षेत्र के बझांगी गांव की आबादी में भी बाढ़ का पानी पहुंच गया है। इससे ग्रामीणों की चिंता बढ़ गई है। वहीं रघुपुर पुख्ता स्थित प्राथमिक विद्यालय में पानी भरने के कारण विद्यालय बंद करना पड़ा। बच्चों की पढ़ाई प्रभावित न हो, इसके लिए उन्हें दूसरे स्थान पर पढ़ाया जा रहा है।

बाढ़ के पानी से कई पशुशालाएं भी प्रभावित हुई हैं। ग्रामीणों को अपने पशुओं को सुरक्षित स्थानों पर रखने में परेशानी हो रही है। खेतों में पानी भरने से फसलों को भी नुकसान की आशंका बनी हुई है। प्रशासनिक अधिकारियों ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण कर स्थिति का जायजा लिया। अधिकारियों को प्रभावित गांवों में आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने और ग्रामीणों की समस्याओं पर तत्काल ध्यान देने के निर्देश दिए गए हैं। जलस्तर में कमी के बावजूद ग्रामीणों को अभी राहत मिलने का इंतजार है।

उड़ान | मुंबई, बेंगलुरु और हैदराबाद के यात्रियों को अक्टूबर में अतिरिक्त उड़ानों का लाभ मिलेगा

प्रयागराज से त्योहारों पर बढ़ेंगी मुंबई, बेंगलुरु और हैदराबाद की उड़ानें

एजेंसी, प्रयागराज

त्योहारी सीजन में प्रयागराज से मुंबई, बेंगलुरु और हैदराबाद जाने वाले हवाई यात्रियों को राहत मिलने वाली है। यात्रियों की बढ़ती संख्या और त्योहारों के दौरान बढ़ने वाली मांग को देखते हुए विमानन कंपनियों ने अक्टूबर के लिए अपने उड़ान शेड्यूल में बदलाव किया है। इसके तहत प्रयागराज एयरपोर्ट से इन प्रमुख शहरों के लिए अतिरिक्त विमान सेवाएं उपलब्ध होंगी।

इंडिगो एयरलाइंस 25 अक्टूबर से प्रयागराज से सप्ताह में चार अतिरिक्त दिन विमान सेवाएं शुरू करने जा रही है। तय कार्यक्रम के अनुसार सोमवार और बुधवार को मुंबई, मंगलवार को हैदराबाद तथा शुक्रवार को बेंगलुरु के लिए अतिरिक्त उड़ानें संचालित की जाएंगी। इससे इन शहरों की यात्रा करने वाले लोगों को अधिक विकल्प मिलेंगे और त्योहारों के दौरान टिकटों की उपलब्धता बेहतर होने की उम्मीद है। नई व्यवस्था का खास लाभ मुंबई जाने वाले यात्रियों को मिलेगा।

बुधवार को प्रयागराज से मुंबई के लिए दो उड़ानें उपलब्ध रहेंगी। इससे एक ही दिन में यात्रियों के पास यात्रा के लिए अधिक विकल्प होंगे। त्योहारों के समय बड़ी संख्या में लोग रोजगार, कारोबार और पारिवारिक कारणों से महानगरों से अपने घर लौटते हैं। ऐसे में अतिरिक्त उड़ानों से यात्रियों को सुविधा मिलने की उम्मीद है। हालांकि उड़ानों की संख्या बढ़ाने के साथ ही इंडिगो ने प्रयागराज से भुवनेश्वर जाने वाली गुरुवार की उड़ान को फिलहाल बंद करने का निर्णय लिया है। विमानन कंपनी के नए शेड्यूल में अक्टूबर के दौरान यह बदलाव लागू रहेगा। यात्रियों को टिकट बुक कराने से पहले संबंधित उड़ान की तारीख और समय की जानकारी जांचने की सलाह दी गई है।

त्योहारी सीजन समाप्त होने के बाद नवंबर में प्रयागराज एयरपोर्ट से इन अतिरिक्त उड़ानों की संख्या फिर कम होने की संभावना है। यानी अक्टूबर में यात्रियों को मिलने वाली अतिरिक्त सुविधा स्थायी नहीं होगी। विमानन कंपनियां मांग के आधार पर उड़ानों का संचालन कर रही हैं। त्योहारी सीजन में हवाई यात्रा की मांग बढ़ने के कारण प्रयागराज एयरपोर्ट पर यात्रियों की संख्या में भी इजाफा होने की उम्मीद है। मुंबई, बेंगलुरु और हैदराबाद के लिए अतिरिक्त सेवाएं शुरू होने से यात्रियों को यात्रा की योजना बनाने में आसानी होगी।त्योहारी सीजन में यात्रियों को अतिरिक्त उड़ानों का लाभ मिलेगा और यात्रा विकल्प बढ़ेंगे।

त्योहारों में बढ़ीं उड़ानें

त्योहारी सीजन के दौरान हवाई यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए एयरलाइंस ने अतिरिक्त उड़ानों की व्यवस्था की है। इससे खासकर मुंबई, बेंगलुरु और हैदराबाद जाने वाले यात्रियों को राहत मिलने की उम्मीद है। यात्रियों को अपनी सुविधा के अनुसार अलग-अलग दिनों में उड़ान चुनने का विकल्प मिलेगा। हालांकि, नवंबर में त्योहारों का सीजन समाप्त होने के बाद अतिरिक्त उड़ानों की संख्या फिर कम हो सकती है। एयरलाइंस मांग के आधार पर ही इन सेवाओं का संचालन कर रही हैं। यात्रियों को टिकट बुक कराने से पहले उड़ान की तारीख और समय की पुष्टि करने की सलाह दी गई है।

आईआईआईटी इलाहाबाद के इतिहास में पहली बार चार छात्रों को करोड़ों का पैकेज

एजेंसी, प्रयागराज

◆ **आईआईआईटी इलाहाबाद के बीटेक 2026 बैच में 96.25 प्रतिशत विद्यार्थियों का हुआ चयन**

भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईआईटी) इलाहाबाद के बीटेक 2026 बैच के विद्यार्थियों ने प्लेसमेंट में शानदार प्रदर्शन किया है। संस्थान के इतिहास में पहली बार चार छात्रों को कुल 1.58 करोड़ रुपये का पैकेज मिला है। इससे संस्थान के विद्यार्थियों की प्रतिभा और तकनीकी दक्षता का प्रदर्शन हुआ है।

बीटेक 2026 बैच के प्लेसमेंट के लिए कुल 480 विद्यार्थियों ने पंजीकरण कराया था। इनमें से 462 विद्यार्थियों का सफलतापूर्वक चयन हुआ। इस तरह बीटेक का कुल प्लेसमेंट प्रतिशत 96.25 रहा। बड़ी संख्या में विद्यार्थियों के चयन से संस्थान में उत्साह का माहौल है। विद्यार्थियों को विभिन्न कंपनियों में तकनीकी और अन्य महत्वपूर्ण भूमिकाओं के लिए अवसर मिले हैं। आईआईआईटी इलाहाबाद के एमटेक 2025 बैच के विद्यार्थियों ने भी प्लेसमेंट में अच्छा प्रदर्शन किया। कुल 145 पंजीकृत विद्यार्थियों में से 112 विद्यार्थियों का चयन हुआ।

इस तरह एमटेक में प्लेसमेंट प्रतिशत 77.24 रहा। संस्थान के अनुसार, बीटेक और एमटेक दोनों स्तरों पर विद्यार्थियों ने उद्योग की अपेक्षाओं के अनुरूप प्रदर्शन किया। संस्थान के निदेशक प्रो. मुकुल शरद सुटावने ने विद्यार्थियों के प्रदर्शन पर प्रसन्नता जताई। उन्होंने कहा कि बेहतर प्लेसमेंट परिणाम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, अनुभवी संकाय, मजबूत उद्योग संबंधों और विद्यार्थियों के लिए संचालित केंद्रित करियर विकास पहलों का परिणाम हैं।

बैरक में भेजने के दौरान हंगामा, छह बंदियों पर वार्डर से बदसलूकी का आरोप

भारतेन्दु संवाददाता, सिरसा

सिरसा जिला कारागार में रात बंदियों को बैरक में भेजने के दौरान जेल कर्मियों और बंदियों के बीच विवाद हो गया। आरोप है कि कुछ बंदियों ने जेल कर्मचारियों के साथ अभद्र व्यवहार किया और गाली-गलौज करते हुए माहौल बिगाड़ दिया। विवाद बढ़ने पर एक वार्डर के साथ बदसलूकी करने तथा उसकी वर्दी पकड़ने का भी आरोप लगाया गया। इस दौरान वार्डर की वर्दी का एक बटन टूट गया।

घटना के बाद जेल प्रशासन में हड़कंप मच गया। जेल अधिकारियों ने मामले की जानकारी उच्चाधिकारियों को दी और पुलिस को शिकायत दी गई। जेल डीएसपी राम कुमार की शिकायत के आधार पर सिविल लाइन थाना पुलिस ने छह बंदियों के खिलाफ केस दर्ज किया है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार, रात के समय जेल में बंदियों को निर्धारित प्रक्रिया के तहत उनकी बैरकों में भेजा जा रहा था। इसी दौरान कुछ बंदियों की जेल कर्मचारियों के साथ कहासुनी हो गई। आरोप है कि कहासुनी के बाद बंदियों ने कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार किया और अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। मामला बढ़ने पर एक वार्डर की वर्दी पकड़ ली गई, जिससे उसका बटन टूट गया।

पुलिस अब केस में नामजद छह बंदियों की भूमिका की जांच कर रही है। साथ ही घटना के दौरान मौजूद जेल कर्मचारियों और अन्य बंदियों से भी जानकारी जुटाई जा सकती है। पुलिस यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि विवाद की शुरुआत किस बात को लेकर हुई थी और इसमें कौन-कौन लोग शामिल थे। जेल प्रशासन की शिकायत के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है।

नीम के पेड़ पर फंदे से लटका मिला युवक का शव, सुसाइड नोट में मारपीट के आरोप

भारतेन्दु संवाददाता, रेवाड़ी। रेवाड़ी जिले के जाटूसाना थाना क्षेत्र के बेरली खुर्द गांव में गुरुवार सुबह उस समय सनसनी फैल गई, जब खेतों में एक युवक का शव नीम के पेड़ से फंदे पर लटका मिला। ग्रामीणों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही डायल-112 की टीम मौके पर पहुंची और शव को पेड़ से नीचे उतारा। इसके बाद कोसली डीएसपी और जाटूसाना थाना प्रभारी ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। मृतक की पहचान 32 वर्षीय अमित तंवर के रूप में हुई है। वह राजस्थान के ढाणी संपत का रहने वाला था और बेरली खुर्द गांव में एक व्यक्ति के पास काम करता था। उसका शव गांव से चौकी नंबर-2 की ओर जाने वाले रास्ते पर खेतों में मिला। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आवश्यक कार्रवाई शुरू की। पुलिस को मृतक के पास से एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है। बताया जा रहा है कि नोट में अमित ने गांव के तीन लोगों पर पैसे नहीं देने और उसके साथ मारपीट करने के आरोप लगाए हैं। सुसाइड नोट मिलने के बाद पुलिस मामले को गंभीरता से लेते हुए सभी पहलुओं की जांच कर रही है।

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि युवक ने किन परिस्थितियों में यह कदम उठाया और सुसाइड नोट में लगाए गए आरोप कितने सही हैं, इसका पता जांच पूरी होने के बाद ही चल सकेगा। पुलिस ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाने के साथ मामले से जुड़े लोगों से पूछताछ शुरू कर दी है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। मामले में पुलिस की जांच जारी है। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण करने के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। जांच अधिकारी सुसाइड नोट में दर्ज आरोपों के आधार पर गांव के लोगों से पूछताछ कर रहे हैं। पुलिस यह भी पता लगाने का प्रयास कर रही है कि अमित का किन लोगों से विवाद था और पैसे को लेकर क्या मामला सामने आया था। अधिकारियों के अनुसार जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

हरियाणा सरकार का बड़ा तोहफा: 35 लाख लाभार्थियों के खातों में ट्रांसफर किए 1129 करोड़ रुपए

लाडो लक्ष्मी योजना के तहत 10.10 लाख बहनों-बेटियों को 212.16 करोड़ रुपए की 11वीं किस्त मिली

भारतेन्दु संवाददाता, चंडीगढ़

हरियाणा सरकार ने गुरुवार को प्रदेश के 35.06 लाख पात्र लाभार्थियों के बैंक खातों में विभिन्न योजनाओं के तहत 1129.05 करोड़ रुपये की राशि सीधे ट्रांसफर की। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इस राशि को महिलाओं, किसानों, उद्योगों और आर्थिक संकट से जूझ रहे परिवारों के लिए महत्वपूर्ण राहत बताया। सरकार की ओर से एक साथ कई योजनाओं की राशि जारी की गई, जिससे अलग-अलग वर्गों के लाभार्थियों को आर्थिक सहायता मिली।

सबसे प्रमुख रूप से दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना की 11वीं किस्त जारी की गई। इसके तहत 10 लाख 10 हजार बहनों-बेटियों के खातों में 212 करोड़ 16 लाख रुपये पहुंचाए गए। योजना शुरू होने के बाद अब तक 11 किस्तों में कुल 2254 करोड़ 47 लाख रुपये लाभार्थियों को दिए जा चुके हैं।

सरकार का कहना है कि योजना के माध्यम से पात्र महिलाओं को नियमित आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। परिवार के कमाने वाले सदस्य की मृत्यु या स्थायी दिव्यांगता की स्थिति में आर्थिक सहायता देने वाली दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना यानी दयालु के तहत भी बड़ी राशि जारी की गई। इस योजना के तहत 4520 परिवारों को 168 करोड़ 13 लाख 21 हजार रुपये की सहायता दी गई।

इसमें दयालु योजना-2 के 70 परिवार भी शामिल हैं। कमाने वाले सदस्य के चले जाने से आर्थिक संकट में आए परिवारों के लिए यह सहायता महत्वपूर्ण मानी जा रही है। भावांतर भरपाई योजना के तहत 6177 किसानों के खातों में 49 करोड़ 89 लाख रुपये ट्रांसफर किए गए। इनमें 6012 आलू उत्पादक, 99 फूलगोभी उत्पादक और 66 शहद उत्पादक किसान शामिल हैं।

योजना के तहत निर्धारित फसल का बाजार भाव सरकार द्वारा तय संरक्षित मूल्य से कम रहने पर कीमत के अंतर की भरपाई की जाती है। इससे उन किसानों को आर्थिक राहत मिलती है जिन्हें बाजार में अपनी उपज का अपेक्षित भाव नहीं मिल पाता। हर घर-हर गृहिणी योजना के तहत पांच लाख महिलाओं के खातों में जुलाई की 19 करोड़ 68 लाख रुपये की सब्सिडी भी भेजी गई। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 500 रुपये में गैस सिलेंडर उपलब्ध कराया जाता है। इससे घरेलू बजट पर पड़ने वाले बोझ को कम करने में मदद मिलती है।

101 साल के स्वतंत्रता सेनानी पेंशन के लिए भटक रहे, डीसी से लगाई गुहार

भारतेन्दु संवाददाता, हिसार

हरियाणा के फतेहाबाद से सटे गांव हिजरावां कलां निवासी 101 वर्षीय स्वतंत्रता सेनानी नादर सिंह आज भी अपनी पेंशन के लिए दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं। नादर सिंह का दावा है कि आज तक उनकी पेंशन नहीं बन पाई है। इसी सिलसिले में वह गुरुवार को हिसार डीसी कार्यालय पहुंचे और अधिकारियों से पेंशन बनवाने की गुहार लगाई।

नादर सिंह के अनुसार वह पिछले कई वर्षों से फतेहाबाद प्रशासन के समक्ष पेंशन बनवाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उनकी समस्या का समाधान नहीं हो सका। अब उन्होंने हिसार प्रशासन से मदद की उम्मीद लगाई है। गौरतलब है कि पहले फतेहाबाद जिला हिसार का ही हिस्सा हुआ करता था। नादर सिंह के बेटे स्वरूप सिंह ने बताया कि उनके पिता ने आजाद हिंद फौज में रहकर लड़ाई लड़ी थी। वह पाकिस्तान से भारत आए थे। भारत आने के बाद उनके रिश्तेदार उन्हें अलवर लेकर गए।

वहां जिस टेंट में वे ठहरे थे, उसमें आग लग गई। आग में उनके महत्वपूर्ण दस्तावेज जलकर नष्ट हो गए। स्वरूप सिंह के मुताबिक दस्तावेज नष्ट होने के बाद से परिवार के सामने उनके पिता के स्वतंत्रता सेनानी होने का प्रमाण जुटाना बड़ी चुनौती बन गया। इसी कारण पेंशन का मामला भी वर्षों से अटका हुआ है।

हरियाणा में खिलाड़ियों के लिए बनेगा राज्य खेल पोर्टल, सुविधाओं की होगी मैपिंग

भारतेन्दु संवाददाता, चंडीगढ़

हरियाणा सरकार प्रदेश के पूरे खेल तंत्र को एकीकृत डिजिटल मंच से जोड़ने की तैयारी कर रही है। इसके लिए राज्य खेल पोर्टल स्थापित किया जाएगा। पोर्टल के माध्यम से प्रदेशभर में उपलब्ध खेल सुविधाओं और अवसंरचना की जानकारी एक जगह उपलब्ध कराई जाएगी। इससे खिलाड़ियों को अपनी जरूरत के अनुसार सुविधाओं की जानकारी हासिल करने में आसानी होगी।

मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी की अध्यक्षता में बुधवार को राज्य खेल प्रशासनिक समिति की पहली बैठक आयोजित की गई। बैठक में खेलों के विकास और खिलाड़ियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने को लेकर कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। प्रदेश की खेल अवसंरचना की व्यापक मैपिंग करने का फैसला भी लिया गया है।

इसके अलावा प्रदेश में होने वाली खेल गतिविधियों को एक मंच पर लाने के लिए साझा राज्य खेल कैलेंडर तैयार किया जाएगा। इससे विभिन्न खेल आयोजनों की जानकारी खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों और खेल क्लबों तक आसानी से पहुंच सकेगी। खेल गतिविधियों के बेहतर समन्वय में भी मदद मिलेगी। बैठक में निर्णय लिया गया कि मान्यता प्राप्त खिलाड़ी और खेल क्लब स्कूल-कॉलेजों, पंचायतों तथा शहरी निकायों में उपलब्ध खेल सुविधाओं का इस्तेमाल कर सकेंगे। इससे मौजूदा खेल संसाधनों का बेहतर उपयोग होगा और खिलाड़ियों को अभ्यास के लिए अतिरिक्त विकल्प मिलेंगे।

राज्य में जमीनी स्तर पर छिपी खेल प्रतिभाओं की पहचान कर उन्हें राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर तक तैयार करने के लिए टैलेंट-पाथवे फ्रेमवर्क विकसित किया जाएगा। इसके तहत खिलाड़ियों को शुरुआती स्तर से आगे बढ़ने के लिए जरूरी मार्गदर्शन और अवसर उपलब्ध कराने की व्यवस्था तैयार की जाएगी।

बहादुरगढ़ में पीएमओ से मारपीट के बाद डॉक्टरों का वर्क सस्पेंड

भारतेन्दु संवाददाता, झज्जर। झज्जर जिले के बहादुरगढ़ ट्रॉमा सेंटर में कार्यवाहक पीएमओ के साथ मारपीट के आरोप का मामला सामने आया है। आरोप एक्स-रे रूम में तैनात रेडियोग्राफर संदीप पर लगा है। बताया जा रहा है कि ड्यूटी से गैरहाजिरी को लेकर विवाद शुरू हुआ था। घटना के बाद स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टरों और कर्मचारियों में रोष फैल गया। मामले के विरोध में एचसीएमएस एसोसिएशन से जुड़े डॉक्टरों और कर्मचारियों ने काम बंद कर विरोध जताया। कर्मचारियों ने आरोपी रेडियोग्राफर के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। उनका कहना है कि स्वास्थ्य संस्थान में ड्यूटी के दौरान अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ इस तरह का व्यवहार स्वीकार नहीं किया जा सकता। विरोध के चलते ट्रॉमा सेंटर में स्वास्थ्य सेवाओं पर भी असर पड़ा।

सिरसा जेल के बंदियों को मिलेगी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी की सुविधा

भारतेन्दु संवाददाता, सिरसा

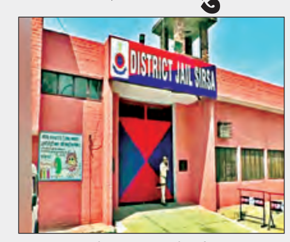

जिला जेल में बंद बंदियों को शिक्षा, ज्ञान और आधुनिक तकनीक से जोड़ने के लिए जल्द ही लाइब्रेरी और कंप्यूटर लैब की सुविधा शुरू की जाएगी। इस पहल का उद्देश्य बंदियों को पढ़ाई के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के साथ उन्हें कौशल विकास और आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ाना है। इससे बंदी जेल में रहते हुए अपने समय का सदुपयोग कर सकेंगे।

लाइब्रेरी के लिए समाजसेवी पंकज खेमका और अन्य संस्थाओं ने सहयोग का हाथ बढ़ाया है। इसी कड़ी में बाबा सरसाई नाथ बुक बैंक की ओर से जिला जेल प्रशासन को विभिन्न विषयों से संबंधित सैकड़ों उपयोगी पुस्तकें भेंट की गई हैं। इन पुस्तकों में सामान्य ज्ञान, साहित्य, शिक्षा और अन्य उपयोगी विषयों से संबंधित सामग्री शामिल है।

कंप्यूटर लैब शुरू होने के बाद बंदियों को आधुनिक तकनीक की जानकारी हासिल करने का अवसर मिलेगा। वे कंप्यूटर का बुनियादी ज्ञान प्राप्त करने के साथ डिजिटल माध्यम से पढ़ाई भी कर सकेंगे। इससे उन्हें जेल से बाहर निकलने के बाद रोजगार और अन्य अवसरों के लिए खुद को तैयार करने में मदद मिलेगी। लाइब्रेरी और कंप्यूटर सुविधा का लाभ उठाकर बंदी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी भी कर सकेंगे।

छछरौली में हाथियों ने रौंदी फसलें, छोटे किसानों ने मुआवजा नियमों पर उठाए सवाल

भारतेन्दु संवाददाता, छछरौली

अराइयांवाला गांव में जंगल से निकलकर आए हाथियों के झुंड ने खेतों में घुसकर किसानों की फसलों को भारी नुकसान पहुंचाया। हाथियों ने गन्ने और धान की खड़ी फसल को रौंद दिया, जबकि पॉपुलर के पौधे भी उखाड़ दिए। सुबह खेतों में पहुंचे किसानों ने फसल की हालत देखी तो उन्हें नुकसान का पता चला। जंगल में सात से आठ हाथियों का झुंड होने से ग्रामीणों में भी भय का माहौल है।

किसान जसबीर, रिंकू, राजकुमार, पप्पू राणा, रमेश और महेंद्र ने बताया कि हाथियों ने रात के समय खेतों में घुसकर काफी नुकसान किया। गन्ने की खड़ी फसल को रौंद दिया गया, जबकि धान के पौधे खेत में बिखरे पड़े मिले। पॉपुलर के कई पौधे भी उखड़े हुए थे। किसानों का कहना है कि मेहनत से तैयार की गई फसल के बर्बाद होने से उन्हें आर्थिक नुकसान उठाना पड़ेगा। किसानों ने बताया कि हाथियों के झुंड के दोबारा खेतों की ओर आने की आशंका बनी हुई है। इससे फसल की रखवाली करने वाले किसानों को अपनी सुरक्षा की चिंता भी सता रही है।

रात के समय खेतों में जाना जोखिम भरा हो गया है। ग्रामीणों ने वन विभाग से हाथियों की गतिविधियों पर नजर रखने और उन्हें आबादी व खेतों से दूर रखने के लिए प्रभावी कदम उठाने की मांग की है। ग्रामीणों का कहना है कि जंगल और खेतों के बीच पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था नहीं होने के कारण हाथी आसानी से खेतों तक पहुंच जाते हैं। किसानों ने संवेदनशील क्षेत्र में तारबंदी कराने की मांग की है, ताकि हाथियों का खेतों में प्रवेश रोका जा सके। साथ ही विभाग से प्रभावित खेतों का मौके पर निरीक्षण कर नुकसान का सही आकलन कराने की मांग की गई है।

किसानों ने फसल नुकसान के बदले मिलने वाले मुआवजे के मौजूदा नियमों पर भी असंतोष जताया। उनका कहना है कि छोटे किसानों की आय खेती पर निर्भर है और फसल नष्ट होने से उन्हें सीधा आर्थिक नुकसान होता है। ऐसे में मुआवजे की प्रक्रिया सरल और नुकसान के अनुरूप होनी चाहिए। किसानों ने विभाग से नियमों में बदलाव कर प्रभावित किसानों को उचित राहत देने की मांग की है। ग्रामीणों ने प्रशासन और वन विभाग से जल्द कार्रवाई की मांग करते हुए कहा कि यदि हाथियों की आवाजाही पर रोक लगाने के लिए ठोस कदम नहीं उठाए गए तो आने वाले दिनों में किसानों की फसलों और उनकी सुरक्षा पर खतरा बढ़ सकता है।

लुधियाना-जाखल पैसेंजर का बढ़ा रूट जींद तक चलेगी ट्रेन; समय-सारणी बदली

भारतेन्दु संवाददाता, हिसार

दैनिक यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए उत्तर रेलवे ने लुधियाना जंक्शन-जाखल जंक्शन पैसेंजर ट्रेन का विस्तार जींद जंक्शन तक कर दिया है। गाड़ी संख्या 54053 अप और 54054 डाउन अब जाखल से आगे जींद तक संचालित होगी। इससे लुधियाना, जाखल, टोहाना, नरवाना सहित मार्ग के अन्य स्टेशनों के यात्रियों को आवागमन में सुविधा मिलेगी।

रेलवे ने विस्तारित मार्ग के लिए नई समय-सारणी भी जारी की है। लुधियाना से जाखल के बीच ट्रेन के समय में कोई बदलाव नहीं किया गया है। गाड़ी संख्या 54054 डाउन लुधियाना जंक्शन से शाम 6:30 बजे रवाना होकर रात 9:40 बजे जाखल पहुंचेगी। इसके बाद ट्रेन रात 9:45 बजे जाखल से जींद के लिए रवाना होगी। जाखल से आगे ट्रेन हिम्मतपुरा, टोहाना, कालवन, धमतान साहिब, धारोदी, नरवाना, घासो, उचाना, गांव बड़ौदा और बरसोला होते हुए रात 11:30 बजे जींद जंक्शन पहुंचेगी। वापसी में गाड़ी संख्या 54053 अप जींद जंक्शन से सुबह 3:40 बजे रवाना होगी। रेलवे के अनुसार नई समय-सारणी 11 और 12 सितंबर से प्रभावी होगी।

इस विस्तार से रोजाना ट्रेन से सफर करने वाले यात्रियों को खास लाभ मिलेगा। खासकर नौकरी, कारोबार और अन्य दैनिक कार्यों के लिए इन शहरों के बीच आने-जाने वाले लोगों को अब जाखल से आगे जींद तक सीधी ट्रेन सुविधा उपलब्ध होगी। रेलवे के इस निर्णय से मार्ग के यात्रियों को अतिरिक्त सुविधा मिलने के साथ यात्रा का समय और साधन चुनने में भी आसानी होगी। यात्री नई समय-सारणी के अनुसार अपनी यात्रा की योजना बना सकेंगे। यात्रियों को अब नई समय-सारणी के अनुसार सफर की योजना बनाने में आसानी होगी।

फरीदाबाद में बेकाबू बाइक ग्रिल से टकराई, दो युवकों की मौके पर मौत

भारतेन्दु संवाददाता, फरीदाबाद। फरीदाबाद में गुरुवार अलसुबह करीब चार बजे सराय टोल प्लाजा के पास एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। फरीदाबाद से दिल्ली की ओर जा रही बाइक अचानक बेकाबू होकर सड़क किनारे लगी ग्रिल से जा टकराई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बाइक सवार दोनों युवकों को संभलने का मौका नहीं मिला। हादसे में सिर में गंभीर चोट लगने के कारण दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद आसपास मौजूद लोगों की भीड़ मौके पर जमा हो गई। राहगीरों ने हादसे की सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस टीम घटनास्थल पर पहुंची और दोनों युवकों के शवों को कब्जे में लिया। इसके बाद शवों को पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल भिजवाया गया। पुलिस ने हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी है। मृतकों की पहचान कृष्णा कॉलोनी निवासी 24 वर्षीय सोनू और 22 वर्षीय सुन्नी के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार सोनू बाइक चला रहा था, जबकि सुन्नी उसके पीछे बैठा था। दोनों गुरुवार सुबह करीब पौने चार बजे अपने घर से दिल्ली जाने के लिए निकले थे। बताया गया कि सराय टोल प्लाजा के पास पहुंचने पर बाइक अचानक बेकाबू हो गई और ग्रिल से टकरा गई। पुलिस हादसे की परिस्थितियों की जांच कर रही है। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंपे जाएंगे। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों शवों को कब्जे में लिया। पुलिस ने घटनास्थल से जरूरी साक्ष्य जुटाए और हादसे की परिस्थितियों की जांच शुरू कर दी। पोस्टमार्टम के बाद दोनों शव परिजनों को सौंपे जाएंगे।

न्यूज ब्रीफ

हरियाणा में महिला अनुबंध कर्मचारियों को झटका, अतिरिक्त सीएल की सुविधा वापस

भारतेन्दु संवाददाता, पंचकूला। हरियाणा के उच्च शिक्षा विभाग ने महिला अनुबंध कर्मचारियों को दी गई अतिरिक्त आकस्मिक छुट्टी (सीएल) की सुविधा वापस ले ली है। उच्च शिक्षा निदेशालय ने 28 जुलाई 2026 को जारी आदेश को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया है। इस आदेश के तहत पात्र महिला अनुबंध कर्मचारियों को अतिरिक्त आकस्मिक अवकाश देने का प्रावधान किया गया था। विभाग की ओर से आदेश वापस लेने के बाद अब महिला अनुबंध कर्मचारी इस अतिरिक्त सीएल का लाभ नहीं ले सकेंगी। निदेशालय ने स्पष्ट किया है कि 28 जुलाई को जारी निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू नहीं रहेंगे।

बेटे की हत्या करने आए थे बदमाश गोली लगने से पिता की मौत

भारतेन्दु संवाददाता, गुरुग्राम। गुरुग्राम में गुरुवार को बाइक सवार तीन बदमाशों ने बाप-बेटे को रास्ते में घेर लिया। बताया जा रहा है कि बदमाश बेटे को निशाना बनाने आए थे, लेकिन उसके पिता महेंद्र (40) को पेट में सटाकर गोली मार दी। गोली लगने से महेंद्र सड़क पर गिर पड़े। पुलिस ने उन्हें सेक्टर-10 सिविल अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। वारदात के बाद तीनों हमलावर फरार हो गए। परिजनों ने हत्या को पुरानी रंजिश से जोड़ते हुए बताया कि महेंद्र का एक बेटा हत्या के मामले में जेल में बंद है। पुलिस ने आरोपियों की पहचान और हत्या के कारणों की जांच शुरू कर दी है। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है।

पिहोवा में किसान महापंचायत, धान खरीद शुरू कराने की उठी मांग

भारतेन्दु संवाददाता, कुरुक्षेत्र। पिहोवा की अनाज मंडी में धान की सरकारी खरीद शुरू कराने और किसानों से जुड़े मुद्दों को लेकर राज्य स्तरीय किसान महापंचायत शुरू हुई। इसमें प्रदेशभर से किसान प्रतिनिधियों के साथ 10 किसान संगठनों के पदाधिकारी शामिल हुए। महापंचायत में धान खरीद के अलावा गन्ने और दूध के दाम बढ़ाने समेत किसानों की विभिन्न मांगों पर चर्चा की जा रही है। किसान प्रतिनिधि सरकार के समक्ष अपनी मांगें रखने की रणनीति पर भी विचार कर रहे हैं।

फतेहाबाद कोर्ट में गवाही देने पहुंचे एएसआई की हार्टअटैक से मौत

भारतेन्दु संवाददाता, रोहतक। जिले के महम क्षेत्र निवासी एएसआई सलिन उर्फ किन्नू का ड्यूटी के दौरान हार्ट फेल होने से निधन हो गया। वह भिवानी सीआईए स्टाफ में तैनात थे। बुधवार को सलिन अपने बेटे के साथ फतेहाबाद कोर्ट में गवाही देने पहुंचे थे। कोर्ट पहुंचते ही अचानक उन्हें हार्टअटैक आया। तबीयत बिगड़ने पर उन्हें संभालने का प्रयास किया गया, लेकिन उनकी जान नहीं बच सकी। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस विभाग में शोक की लहर दौड़ गई।परिजनों और सहकर्मियों को घटना की जानकारी दी गई। पुलिस विभाग के अधिकारियों ने सलिन के निधन पर शोक व्यक्त किया। पोस्टमार्टम की प्रक्रिया के बाद शव परिजनों को सौंपा जाएगा।

बिजली कटौती से फसलों की सिंचाई प्रभावित किसानों ने मांगी दो माह नियमित सप्लाई

भारतेन्दु संवाददाता, फतेहाबाद

फसल पकने में करीब एक माह का समय शेष रहने के बीच बिजली कटौती ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। लगातार बिजली सप्लाई बाधित होने से खेतों में सिंचाई प्रभावित हो रही है। किसानों का कहना है कि इस समय फसलों को पर्याप्त पानी की जरूरत है, लेकिन बिजली उपलब्ध नहीं होने के कारण समय पर सिंचाई नहीं हो पा रही। इससे फसल की पैदावार प्रभावित होने की आशंका बनी हुई है।

किसानों ने बिजली विभाग से आगामी दो महीनों तक पर्याप्त और नियमित बिजली सप्लाई उपलब्ध करवाने की मांग की है। इस संबंध में भारतीय किसान यूनियन खेती बचाओ, हरियाणा की ओर से गुरुवार को ग्रामीण बिजली विभाग रतिया के एसडीओ को मांग पत्र सौंपा गया। भाकियू खेती बचाओ के ब्लॉक प्रधान सतनाम सिंह लांबा ने कहा कि फसल पकने के अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। इस दौरान खेतों में सिंचाई के लिए पानी की बेहद आवश्यकता होती है। बिजली कटौती के कारण किसान जरूरत के अनुसार खेतों में पानी नहीं दे पा रहे हैं।

उन्होंने बताया कि करीब तीन माह पहले भी किसानों को बिजली सप्लाई की समस्या का सामना करना पड़ा था। उस समय विभाग ने समस्या का समाधान किया था, लेकिन अब फसल के महत्वपूर्ण समय में फिर बिजली संकट खड़ा हो गया है। उन्होंने बिजली विभाग से मांग की कि किसानों की फसल को ध्यान में रखते हुए कम से कम आगामी दो महीनों तक बिजली सप्लाई सुचारु रखी जाए। इससे किसान समय पर सिंचाई कर फसल को नुकसान से बचा सकेंगे। जिला प्रधान राजिंदर सिंह चहल ने कहा कि किसान बीज, खाद, दवाई और डीजल सहित खेती पर पहले ही काफी खर्च कर चुके हैं।

अब फसल के अंतिम समय में बिजली की कमी के कारण सिंचाई प्रभावित होना उनके लिए बड़ी चिंता का विषय है। उन्होंने विभाग से किसानों की समस्या का प्राथमिकता के आधार पर समाधान करने की मांग की। इस मौके पर बलजीत सिंह, गुरप्रीत सिंह और गांव लांबा के अन्य किसान मौजूद रहे। किसानों ने कहा कि फसल के इस महत्वपूर्ण चरण में नियमित बिजली सप्लाई बेहद जरूरी है।

दिल्ली से आदेश मिलने के बाद अंबाला मंडल ने जारी किए विभागीय कार्रवाई के निर्देश

रेलवे में भ्रष्टाचार की सजा रिटायरमेंट के बाद भी, दो साल आधी पेंशन रोकी

भारतेन्दु संवाददाता, अंबाला

◆ रेलवे बोर्ड ने पूरी ग्रेच्युटी स्थायी रूप से जब्त करने का दिया आदेश

सरकारी सेवा के दौरान भ्रष्टाचार के मामले में फंसे अधिकारियों के लिए सेवानिवृत्ति के बाद भी कार्रवाई से बचना आसान नहीं होगा। रेलवे बोर्ड ने अंबाला रेल मंडल के कमर्शियल ब्रांच कार्यालय के एक सेवानिवृत्त अधीक्षक के खिलाफ कड़ा फैसला लिया है। बोर्ड ने अधिकारी की दो साल तक 50 प्रतिशत मासिक पेंशन रोकने के साथ ही पूरी ग्रेच्युटी स्थायी रूप से जब्त करने का आदेश जारी किया है। इस कार्रवाई के बाद रेलवे में भ्रष्टाचार के मामलों में सेवानिवृत्ति के बाद भी विभागीय कार्रवाई जारी रहने का संदेश गया है।

रेलवे बोर्ड की ओर से जारी आदेश दिल्ली से अंबाला रेल मंडल को प्राप्त हुआ। आदेश मिलने के बाद मंडल स्तर पर भी लिखित आदेश जारी कर संबंधित अधिकारियों को कार्रवाई की जानकारी दी गई। रेलवे बोर्ड के निर्देशों के अनुसार सेवानिवृत्त अधीक्षक की मासिक पेंशन का आधा हिस्सा अगले दो वर्षों तक रोक दिया जाएगा। इसके अलावा उन्हें सेवानिवृत्ति के समय मिलने वाली पूरी ग्रेच्युटी भी स्थायी रूप से जब्त कर ली गई है। रेलवे की ओर से यह कार्रवाई रेलवे सेवा (पेंशन) नियम, 1993 के नियम-9 के तहत की गई है।

इस प्रावधान के तहत गंभीर अनियमितता या कदाचार के मामलों में सेवानिवृत्त कर्मचारी के खिलाफ भी विभागीय कार्रवाई की जा सकती है। इसी प्रावधान के आधार पर रेलवे बोर्ड ने संबंधित अधिकारी के खिलाफ पेंशन और ग्रेच्युटी को लेकर यह निर्णय लिया है। दिल्ली से आदेश मिलने के बाद अंबाला रेल मंडल ने भी आवश्यक विभागीय प्रक्रिया पूरी करते हुए लिखित आदेश जारी कर दिए हैं। रेलवे बोर्ड के निर्देशों की प्रति वरिष्ठ मंडल कार्मिक अधिकारी को भी भेजी गई है, ताकि पेंशन से संबंधित कार्रवाई नियमानुसार सुनिश्चित की जा सके। इस मामले से स्पष्ट है कि सरकारी कर्मचारी के सेवानिवृत्त होने के बाद भी गंभीर भ्रष्टाचार या कदाचार के मामलों में विभागीय कार्रवाई का रास्ता बंद नहीं होता। रेलवे बोर्ड की ओर से की गई यह कार्रवाई विभाग में जवाबदेही तय करने और भ्रष्टाचार के मामलों में सख्त रुख अपनाने का संकेत मानी जा रही है।

अधिकारी को दो वर्षों तक आधी पेंशन का नुकसान उठाना पड़ेगा, जबकि पूरी ग्रेच्युटी स्थायी रूप से जब्त होने से सेवानिवृत्ति के बाद मिलने वाला महत्वपूर्ण वित्तीय लाभ भी समाप्त हो गया है। रेलवे के इस फैसले से यह भी स्पष्ट हुआ है कि सेवानिवृत्ति के बाद मिलने वाले आर्थिक लाभ भी गंभीर भ्रष्टाचार के मामलों में सुरक्षित नहीं माने जा सकते। अधिकारी को दो वर्षों तक पेंशन का केवल आधा हिस्सा ही प्राप्त होगा। वहीं ग्रेच्युटी की पूरी राशि स्थायी रूप से जब्त किए जाने से आर्थिक नुकसान और बढ़ गया है। रेलवे की इस कार्रवाई को कर्मचारियों के लिए चेतावनी के तौर पर देखा जा रहा है कि सेवा के दौरान किए गए गंभीर कदाचार की जिम्मेदारी सेवानिवृत्ति के बाद भी खत्म नहीं होती।

न्यूज ब्रीफ

सहारनपुर के बाद बुलंदशहर रैली रद्द, रालोद ने अखिलेश पर साधा निशाना

एजेंसी ,नई दिल्ली । समाजवादी पार्टी (सपा) अध्यक्ष अखिलेश यादव की पश्चिमी उत्तर प्रदेश में प्रस्तावित रैलियां रद्द होने को लेकर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। सपा के साथ जारी जुबानी जंग के बीच राष्ट्रीय लोक दल (रालोद) ने अखिलेश यादव पर निशाना साधा है। रालोद प्रवक्ता रोहित अग्रवाल ने आरोप लगाया कि अखिलेश यादव के 'चवन्नी' वाले बयान से चौधरी परिवार और जाट समाज का अपमान हुआ है। उन्होंने दावा किया कि पश्चिमी यूपी में 36 बिरादरी के विरोध के चलते सपा को पहले सहारनपुर और अब बुलंदशहर की प्रस्तावित रैली रद्द करनी पड़ी। दरअसल, अखिलेश यादव का 11 सितंबर को बुलंदशहर दौरा प्रस्तावित था, जिसे अब रद्द कर दिया गया है। इससे पहले उनका सहारनपुर दौरा भी रद्द हो चुका है। रालोद ने इन घटनाओं को सपा के लिए राजनीतिक झटका बताते हुए कहा कि पश्चिमी यूपी में पार्टी को जनता के विरोध का सामना करना पड़ रहा है। वहीं, सपा की ओर से रैलियां रद्द होने को लेकर अलग कारण बताए जा सकते हैं। इस मुद्दे पर दोनों दलों के बीच बयानबाजी तेज होने की संभावना है।

आगरा में हलवाई का खौफनाक कदम, तीन ग्राहकों पर डाला खौलता तेल

एजेंसी, नई दिल्ली । आगरा के रकाबगंज थाना क्षेत्र में विवाद के बाद एक हलवाई ने तीन ग्राहकों पर कड़ाही का खौलता तेल फेंक दिया। घटना में मुकुल और उसके दो साथी पीयूष व सोनू गंभीर रूप से झुलस गए। तीनों घायलों को उपचार के लिए एसएन मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। जानकारी के अनुसार, ग्राहक किसी बात को लेकर हलवाई से विवाद कर रहे थे। इसी दौरान मामला बढ़ गया और गुस्से में हलवाई ने कड़ाही में रखा खौलता तेल तीनों पर डाल दिया। अचानक हुए हमले से मौके पर अफरा-तफरी मच गई। आसपास मौजूद लोगों ने झुलसे युवकों को तत्काल अस्पताल पहुंचाया। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की। पुलिस ने हलवाई के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। अधिकारियों के अनुसार, घटना के कारणों और विवाद की पूरी जानकारी जुटाई जा रही है। घायलों की स्थिति पर चिकित्सकों की निगरानी बनी हुई है।

केंद्र सरकार के विभागों में हिंदी अनुवादक के 532 पद

एजेंसी, नई दिल्ली । कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी) की संयुक्त हिंदी अनुवादक परीक्षा-2025 के तहत विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों में कुल 532 रिक्तियां अंतिम रूप से दर्ज की गई हैं। इनमें जूनियर ट्रांसलेटर, जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर, सब इंस्पेक्टर (हिंदी ट्रांसलेटर) और सीनियर ट्रांसलेटर/ट्रांसलेशन ऑफिसर के पद शामिल हैं। अंतिम रिक्ति विवरण के अनुसार सबसे अधिक 311 पद केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) में हैं। इन पदों पर चयन संयुक्त हिंदी अनुवादक परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा। इसके अलावा केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, विभागों और संगठनों में भी रिक्त पदों को भर्ती प्रक्रिया में शामिल किया गया है। एसएससी द्वारा जारी अंतिम रिक्तियों के बाद अभ्यर्थियों के लिए उपलब्ध पदों की संख्या स्पष्ट हो गई है। भर्ती प्रक्रिया में निर्धारित पात्रता और चयन मानकों को पूरा करने वाले उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। हिंदी अनुवाद से जुड़े इन पदों पर नियुक्ति पाने वाले अभ्यर्थियों को केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों में अनुवाद संबंधी जिम्मेदारियां दी जाएंगी।

प्रयागराज में जनगणना की तैयारियां तेज, 16 नवंबर से होगी स्वगणना

एजेंसी, नई दिल्ली

प्रयागराज में जनगणना 2027 के दूसरे चरण की तैयारियां तेज हो गई हैं। दूसरा चरण एक दिसंबर से शुरू होगा, जबकि इससे पहले 16 नवंबर से स्वगणना की प्रक्रिया आरंभ की जाएगी। जनगणना कार्य को समयबद्ध और व्यवस्थित ढंग से पूरा करने के लिए प्रशासनिक स्तर पर तैयारियों की समीक्षा की जा रही है। तैयारियों को लेकर आयोजित समीक्षा बैठक में अधिकारियों ने संबंधित कर्मचारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

बताया गया कि जनगणना के दूसरे चरण से पहले स्वगणना की प्रक्रिया शुरू होगी, जिसमें लोग निर्धारित प्रक्रिया के तहत अपने परिवार और सदस्यों से जुड़ी जानकारी स्वयं दर्ज कर सकेंगे। जनगणना कार्य के तहत सबसे पहले नक्शे भरे जाएंगे। इसके बाद निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार फील्ड स्तर पर अन्य कार्यों को पूरा किया जाएगा। प्रशासन ने इसके लिए प्रशिक्षण व्यवस्था पर विशेष जोर दिया है। अधिकारियों के अनुसार, मास्टर ट्रेनर का चयन पहले ही किया जा चुका है। इन मास्टर ट्रेनरों को लखनऊ में प्रशिक्षण दिया जाएगा।

प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद मास्टर ट्रेनर जिले में तैनात फील्ड ट्रेनरों को प्रशिक्षित करेंगे। इसके बाद फील्ड ट्रेनर गणनाकर्मियों को जनगणना से संबंधित प्रक्रिया, प्रपत्र भरने और व्यावहारिक दिशा-निर्देशों की जानकारी देंगे। समीक्षा बैठक में फील्ड कार्य को निर्धारित समयसीमा में पूरा करने और सभी स्तरों पर बेहतर समन्वय बनाए रखने पर जोर दिया गया।

ब्रिक्स सम्मेलन का कनॉट प्लेस पर नहीं पड़ेगा असर, तीनों दिन खुला रहेगा बाजार

एजेंसी, नई दिल्ली

जी-20 सम्मेलन के सफल आयोजन के बाद देश की राजधानी दिल्ली अब ब्रिक्स सम्मेलन की मेजबानी के लिए तैयार है। सम्मेलन को लेकर राजधानी में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है और वीवीआईपी आवाजाही को ध्यान में रखते हुए लुटियंस दिल्ली के कई इलाकों में यातायात संबंधी पाबंदियां लागू की गई हैं। हालांकि, दिल्ली के प्रमुख व्यावसायिक केंद्र कनॉट प्लेस पर इन प्रतिबंधों का कारोबार पर बड़ा असर नहीं पड़ेगा।

कनॉट प्लेस के व्यापारियों ने स्पष्ट किया है कि सम्मेलन के तीनों दिन बाजार पूरी तरह खुला रहेगा। दुकानें, रेस्तरां और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को सामान्य रूप से संचालित किया जाएगा। व्यापारियों ने लोगों से अपील की है कि वे यातायात सलाह को ध्यान में रखते हुए कनॉट प्लेस आएं और खरीदारी के साथ खान-पान का भी आनंद लें। व्यापारियों का कहना है कि कनॉट प्लेस दिल्ली की पहचान और प्रमुख कारोबारी केंद्रों में शामिल है। यहां रोजाना बड़ी संख्या में स्थानीय लोग और पर्यटक खरीदारी, भोजन और मनोरंजन के लिए पहुंचते हैं।

ऐसे में अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन के कारण बाजार बंद रखने से व्यापारियों और ग्राहकों दोनों को परेशानी हो सकती थी। इसी वजह से बाजार को सामान्य रूप से खुला रखने का निर्णय लिया गया है। हालांकि, सम्मेलन के दौरान सुरक्षा एजेंसियों की ओर से जारी दिशा-निर्देशों का पालन करना सभी के लिए जरूरी होगा। वीवीआईपी मूवमेंट के समय कुछ सड़कों पर यातायात का मार्ग बदला जा सकता है या आवाजाही सीमित हो सकती है। ऐसे में व्यापारियों ने ग्राहकों को सलाह दी है कि वे घर से निकलने से पहले संबंधित ट्रैफिक एडवाइजरी जरूर देख लें और उसी के अनुसार अपनी यात्रा की योजना बनाएं। कनॉट प्लेस के आसपास सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी विशेष सतर्कता बरती जा रही है।

सम्मेलन में आने वाले विदेशी प्रतिनिधियों और वीवीआईपी मेहमानों की आवाजाही को देखते हुए पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां लगातार निगरानी रखेंगी। इसके बावजूद व्यापारियों को उम्मीद है कि बाजार में सामान्य गतिविधियां जारी रहेंगी और कारोबार प्रभावित नहीं होगा।

दिल्ली में बनेगी अपनी एसडीईआरएफ एनडीआरएफ की तर्ज पर होगी आधुनिक फोर्स

एजेंसी, नई दिल्ली

राजधानी में आपदाओं के दौरान राहत और बचाव कार्य को अधिक तेज और प्रभावी बनाने के लिए दिल्ली सरकार ने स्टेट डिजास्टर इमरजेंसी रिस्पॉन्स फोर्स (एसडीईआरएफ) के गठन की तैयारी शुरू कर दी है। यह फोर्स राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ) की तर्ज पर विकसित की जाएगी और जरूरत पड़ने पर स्थानीय स्तर पर तुरंत राहत एवं बचाव अभियान चलाएगी। आपदा की स्थिति में राहत और बचाव दल के मौके पर पहुंचने में होने वाली देरी कई बार जान-माल के नुकसान को बढ़ा देती है। इसी चुनौती को देखते हुए सरकार राजधानी के लिए एक ऐसी विशेष टीम तैयार करना चाहती है, जो भूकंप, इमारत गिरने, आग, बाढ़, जलभराव और अन्य आपात स्थितियों में तत्काल कार्रवाई कर सके। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली सचिवालय में एसडीईआरएफ के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर एसडीईआरएफ के गठन को लेकर विस्तार से चर्चा की। बैठक में फोर्स की संरचना, प्रशिक्षण, आधुनिक उपकरणों, तैनाती और आपदा के समय विभिन्न विभागों के बीच बेहतर समन्वय जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार किया गया।

सरकार का उद्देश्य ऐसी प्रशिक्षित और सक्षम टीम तैयार करना है, जो दिल्ली में किसी भी आपदा की सूचना मिलते ही घटनास्थल पर पहुंचकर राहत कार्य शुरू कर सके। फोर्स को अत्याधुनिक बचाव उपकरणों और तकनीकी संसाधनों से लैस करने पर भी जोर दिया जाएगा। इसके लिए जवानों को विशेष प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की जाएगी, ताकि वे कठिन परिस्थितियों में भी प्रभावी ढंग से अभियान चला सकें।

सत्य निकेतन हादसे के बाद आपदा प्रबंधन और त्वरित प्रतिक्रिया व्यवस्था को मजबूत करने की जरूरत पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। सरकार का मानना है कि स्थानीय स्तर पर प्रशिक्षित विशेष बल होने से आपदा के शुरुआती घंटों में महत्वपूर्ण मदद मिल सकेगी। एसडीईआरएफ के गठन के बाद दिल्ली में आपदा प्रबंधन की मौजूदा व्यवस्था को मजबूती मिलने की उम्मीद है।

व्यापारियों की दुकानों पर संकट, कांग्रेस ने उठाई आवाज

एजेंसी, नई दिल्ली

बिना वैकल्पिक व्यवस्था दुकानें हटाने का विरोध

मोदीनगर में गाजियाबाद-सहारनपुर रेलवे लाइन पर प्रस्तावित फोरलेन रेलवे ओवरब्रिज (आरओबी) को लेकर प्रभावित व्यापारियों की समस्याएं सामने आने लगी हैं। महाकाली मार्केट, इंदिरा कॉम्प्लेक्स और राजा कॉम्प्लेक्स के दुकानदारों को बिना वैकल्पिक व्यवस्था के हटाए जाने की आशंका के विरोध में जिला कांग्रेस कमेटी ने आवाज उठाई है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं और व्यापारियों ने बृहस्पतिवार को जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा और प्रभावित दुकानदारों के लिए उचित व्यवस्था किए जाने की मांग की।

कांग्रेस नेताओं का कहना है कि प्रस्तावित आरओबी क्षेत्र के विकास और यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है, लेकिन परियोजना की जद में आने वाले व्यापारियों के हितों की अनदेखी नहीं की जानी चाहिए। वर्षों से दुकानें चलाकर परिवार का पालन-पोषण करने वाले व्यापारियों के सामने दुकानें हटने की स्थिति में रोजी-रोटी का संकट खड़ा हो सकता है। ज्ञापन में मांग की गई कि किसी भी दुकान को हटाने से पहले प्रभावित व्यापारियों के लिए वैकल्पिक स्थान की व्यवस्था की जाए।

कांग्रेस ने कहा कि प्रशासन को व्यापारियों के साथ संवाद कर उनकी समस्याओं और सुझावों को सुनना चाहिए। साथ ही, जिन दुकानदारों की दुकानें परियोजना से प्रभावित हो रही हैं, उनके पुनर्वास और उचित मुआवजे की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जानी चाहिए। व्यापारियों ने भी प्रशासन के सामने अपनी चिंताएं रखीं। उनका कहना है कि अचानक दुकानें हटाए जाने से कारोबार पूरी तरह प्रभावित होगा और परिवारों की आर्थिक स्थिति बिगड़ सकती है। ऐसे में उन्हें पर्याप्त समय देने के साथ नई जगह पर कारोबार स्थापित करने में मदद मिलनी चाहिए। कांग्रेस कमेटी ने जिलाधिकारी से मामले में हस्तक्षेप कर व्यापारियों के हित में समाधान निकालने की अपील की।

आगरा में 73 मदरसों को नोटिस, अंग्रेजी माध्यम की कक्षाएं चलाने का आरोप

एजेंसी, नई दिल्ली

नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंचने वाले यात्रियों का स्वागत अब आसमान में लहराता 100 फीट ऊंचा विशाल तिरंगा करेगा। एयरपोर्ट की टर्मिनल बिल्डिंग के सामने दाईं ओर स्मारकीय ध्वजस्तंभ स्थापित किया जाएगा। इसके निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और इसके लिए भव्य प्लेटफार्म के साथ मजबूत फाउंडेशन तैयार किया जा रहा है। निर्माण एजेंसी ने ध्वजस्तंभ के लिए निर्धारित स्थान पर नींव तैयार करने का काम शुरू कर दिया है। फाउंडेशन का निर्माण पूरा होने के बाद करीब 100 फीट ऊंचा ध्वजस्तंभ स्थापित किया जाएगा। इसके बाद उस पर विशाल राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा।

टर्मिनल बिल्डिंग के सामने ऊंचाई पर स्थापित होने वाला यह तिरंगा एयरपोर्ट के मुख्य प्रवेश क्षेत्र से ही यात्रियों और आगंतुकों को स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। आधुनिक और भव्य टर्मिनल के बीच विशाल राष्ट्रीय ध्वज एयरपोर्ट की सुंदरता को और बढ़ाएगा। एयरपोर्ट पर आने वाले देश-विदेश के यात्रियों के लिए यह तिरंगा आकर्षण का प्रमुख केंद्र बनने की उम्मीद है। विशाल ध्वज न केवल एयरपोर्ट की पहचान को मजबूत करेगा, बल्कि यहां पहुंचने वाले लोगों में देश के प्रति गौरव और सम्मान की भावना भी पैदा करेगा। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को आधुनिक सुविधाओं और भव्य स्वरूप के साथ विकसित किया जा रहा है। ऐसे में टर्मिनल के सामने स्थापित होने वाला विशाल तिरंगा इसके स्वरूप में राष्ट्रीय भावना का महत्वपूर्ण रंग जोड़ेगा। दिन में दूर से दिखाई देने वाला यह ध्वज एयरपोर्ट परिसर को अलग पहचान बनाने में मदद करेगा। ध्वजस्तंभ का निर्माण पूरा होने के बाद एयरपोर्ट के प्रवेश क्षेत्र का दृश्य और अधिक आकर्षक नजर आएगा। यात्रियों के स्वागत के साथ यह तिरंगा राष्ट्रीय एकता, गौरव और देशभक्ति का प्रतीक भी बनेगा।

नियमों के फेर में फंसा जन्म-मृत्यु का सबूत, मेरठवासी परेशान

एजेंसी, नई दिल्ली

मेरठ में जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने की प्रक्रिया में कड़े नियम आम लोगों के लिए परेशानी का कारण बन गए हैं। खासकर दो साल से अधिक देरी से किए जाने वाले आवेदनों में लोगों को लंबी प्रशासनिक प्रक्रिया से गुजरना पड़ रहा है। प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आवेदकों को विभिन्न अधिकारियों के कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। नियमों के अनुसार, जन्म या मृत्यु की घटना के 21 दिनों के भीतर पंजीकरण कराने पर नगर निगम स्तर पर प्रक्रिया अपेक्षाकृत आसान रहती है। लेकिन समय सीमा बीतने के बाद आवेदन की प्रक्रिया जटिल होती जाती है। देरी अधिक होने पर आवेदकों से अतिरिक्त दस्तावेज, शपथपत्र और संबंधित अधिकारियों की अनुमति मांगी जाती है। दो साल से अधिक पुराने मामलों में प्रक्रिया और कठिन हो जाती है।

नोएडा एयरपोर्ट का अंतरराष्ट्रीय टर्मिनल तैयार, अक्टूबर से शुरू होगी सुरक्षा जांच

एजेंसी, नई दिल्ली

विदेश उड़ानों का इंतजार जल्द होगा खत्म

नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से अंतरराष्ट्रीय उड़ानों का इंतजार कर रहे यात्रियों के लिए बड़ी खबर है। एयरपोर्ट के अंतरराष्ट्रीय टर्मिनल का निर्माण कार्य लगभग पूरा हो चुका है। फिलहाल टर्मिनल के अंदर फिनिशिंग और अंतिम चरण के कार्य किए जा रहे हैं। निर्माण पूरा होने के बाद अब एयरपोर्ट के अंतरराष्ट्रीय संचालन की दिशा में महत्वपूर्ण प्रक्रिया शुरू होने वाली है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड के अधिकारियों के अनुसार, अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के संचालन के लिए सुरक्षा मानकों का पूरा होना सबसे महत्वपूर्ण पहलू है।

इसी को देखते हुए नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो की टीम अक्टूबर से एयरपोर्ट के सुरक्षा इंतजामों की जांच शुरू कर सकती है। सुरक्षा जांच में टर्मिनल और यात्रियों से जुड़े विभिन्न सुरक्षा प्रबंधों का निरीक्षण किया जाएगा। अंतरराष्ट्रीय टर्मिनल में यात्रियों के आगमन और प्रस्थान से संबंधित सुविधाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है। टर्मिनल के अंदर कई स्थानों पर फिनिशिंग का काम जारी है। अधिकारियों का कहना है कि निर्माण कार्य पूरा होने के बाद आवश्यक अनुमतियों और सुरक्षा मंजूरी की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी। नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो की जांच अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के संचालन की तैयारी में अहम मानी जा रही है।

टीम एयरपोर्ट पर सुरक्षा व्यवस्था, यात्रियों की जांच, प्रवेश और निकास व्यवस्था तथा अन्य निर्धारित सुरक्षा मानकों का जायजा लेगी। निर्धारित मानकों को पूरा करने के बाद अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के संचालन का रास्ता साफ हो सकेगा। नोएडा एयरपोर्ट के शुरू होने से दिल्ली-एनसीआर के साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश के यात्रियों को भी बड़ी सुविधा मिलने की उम्मीद है। अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के संचालन से यात्रियों को विदेश यात्रा के लिए बेहतर विकल्प मिलेगा और मौजूदा हवाई अड्डों पर दबाव कम करने में भी मदद मिल सकती है।

आईआईआईटी प्रयागराज का दीक्षा समारोह:728 विद्यार्थियों को उपाधियां, 22 पदक से होंगे सम्मानित

एजेंसी, नई दिल्ली

प्रयागराज। भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईआईटी) प्रयागराज का 21वां दीक्षा समारोह 12 सितंबर को आयोजित किया जाएगा। समारोह में संस्थान के कुल 728 विद्यार्थियों को विभिन्न पाठ्यक्रमों की उपाधियां प्रदान की जाएंगी। दीक्षा समारोह को लेकर संस्थान में तैयारियां अंतिम चरण में हैं। इस अवसर पर विद्यार्थियों की शैक्षणिक उपलब्धियों को भी विशेष रूप से सम्मानित किया जाएगा। समारोह के दौरान शैक्षणिक क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को कुल 22 पदक प्रदान किए जाएंगे। इनमें अध्यक्ष स्वर्ण पदक प्रमुख सम्मान होगा, जो उत्कृष्ट शैक्षणिक प्रदर्शन के लिए दिया जाएगा।

अध्यक्ष स्वर्ण पदक दिव्यांश ओमर को प्रदान किया जाएगा। इसके अलावा अन्य मेधावी विद्यार्थियों को भी उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए विभिन्न पदकों से सम्मानित किया जाएगा। दीक्षा समारोह विद्यार्थियों के लिए उनके शैक्षणिक जीवन के महत्वपूर्ण पड़ावों में से एक होगा। उपाधि प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों में अलग-अलग पाठ्यक्रमों के छात्र शामिल होंगे। संस्थान की ओर से समारोह को यादगार बनाने के लिए विशेष व्यवस्थाएं की जा रही हैं।

इस अवसर पर विद्यार्थियों के साथ उनके अभिभावक, शिक्षक और संस्थान के अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। समारोह में विद्यार्थियों को भविष्य में अपने ज्ञान और तकनीकी कौशल का उपयोग देश और समाज के विकास में करने के लिए प्रेरित किया जाएगा। मेधावी विद्यार्थियों का सम्मान अन्य छात्रों को भी बेहतर शैक्षणिक प्रदर्शन के लिए प्रोत्साहित करेगा। दीक्षा समारोह के दौरान विद्यार्थियों के लिए यह अवसर केवल उपाधि प्राप्त करने तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि उनके भविष्य की नई शुरुआत का प्रतीक भी होगा। संस्थान के अधिकारी और शिक्षक विद्यार्थियों को बदलती तकनीकी दुनिया में नई संभावनाओं का लाभ उठाने तथा अपने कौशल को लगातार विकसित करने के लिए प्रेरित करेंगे।

तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में तेजी से हो रहे बदलावों को देखते हुए विद्यार्थियों से नवाचार, अनुसंधान और उद्यमिता पर विशेष ध्यान देने की उम्मीद की जाएगी। समारोह में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों की उपलब्धियों को रेखांकित करते हुए उन्हें आगे भी इसी तरह मेहनत करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।

चुनाव आयोग की शर्त को चुनौती, दिल्ली हाई कोर्ट ने याचिका पर नहीं किया विचार

कांग्रेस को हाई कोर्ट की सलाह, एसआईआर मुद्दे पर जनहित याचिका करें दाखिल

एजेंसी, नई दिल्ली

विशेष सघन पुनरीक्षण (एसआईआर) से जुड़ी निर्वाचन आयोग की एक शर्त को चुनौती देने वाली याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने गुरुवार को विचार करने से इनकार कर दिया। अदालत ने कहा कि याचिका में उठाया गया मुद्दा व्यापक जनहित से जुड़ा है, इसलिए इसे जनहित याचिका के तौर पर दायर किया जाना चाहिए। अदालत के सुझाव के बाद याचिकाकर्ताओं ने अपनी मौजूदा याचिका वापस ले ली। याचिका में विशेष सघन पुनरीक्षण की प्रक्रिया से प्रभावित कुछ मतदाताओं के लिए लागू उस शर्त को चुनौती दी गई थी, जिसके तहत संबंधित लोगों को एक घोषणा-पत्र जमा करना होता है।

इस घोषणा-पत्र में उन्हें यह बताना होता है कि वे पहली बार मतदाता सूची में शामिल होने के लिए आवेदन कर रहे हैं। याचिकाकर्ताओं ने निर्वाचन आयोग की इस शर्त को चुनौती देते हुए अदालत से इसमें हस्तक्षेप करने की मांग की थी। याचिकाकर्ताओं का कहना था कि एसआईआर प्रक्रिया के दौरान मतदाताओं पर इस तरह की घोषणा देने की शर्त लागू करने से पात्र मतदाताओं के लिए परेशानी पैदा हो सकती है। उनका तर्क था कि किसी मतदाता सूची में नाम शामिल कराने या उससे संबंधित प्रक्रिया में पहले से मौजूद मतदाताओं को ऐसी घोषणा देने के लिए बाध्य करना उचित नहीं माना जाना चाहिए।

इसी आधार पर उन्होंने निर्वाचन आयोग की व्यवस्था को न्यायिक जांच के दायरे में लाने की मांग की। मामले की सुनवाई के दौरान दिल्ली हाई कोर्ट ने याचिका की प्रकृति पर विचार किया। अदालत ने संकेत दिया कि मामला केवल कुछ व्यक्तिगत याचिकाकर्ताओं तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका प्रभाव बड़ी संख्या में मतदाताओं पर पड़ सकता है। इसलिए अदालत ने सुझाव दिया कि इस मुद्दे को उचित तरीके से जनहित याचिका के माध्यम से उठाया जाए। अदालत के इस सुझाव के बाद याचिकाकर्ताओं ने अपनी याचिका वापस लेने का फैसला किया। इसका अर्थ यह है कि अदालत ने याचिका के आरोपों या निर्वाचन आयोग की संबंधित शर्त की वैधता पर कोई अंतिम फैसला नहीं दिया है।

कांग्रेस की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने सुनवाई ठुकराई

याचिकाकर्ता अब उचित प्रक्रिया के तहत जनहित याचिका दाखिल कर इस मुद्दे को फिर अदालत के समक्ष उठा सकते हैं। विशेष सघन पुनरीक्षण का उद्देश्य मतदाता सूची को अधिक व्यवस्थित और अद्यतन करना है।

इस प्रक्रिया के दौरान मतदाताओं से संबंधित दस्तावेज और आवश्यक घोषणाएं मांगी जा सकती हैं। हालांकि, ऐसी प्रक्रियाओं को लेकर राजनीतिक दलों और अन्य पक्षों की ओर से समय-समय पर सवाल भी उठाए जाते रहे हैं। उनका कहना है कि मतदाता सूची में नाम शामिल कराने की प्रक्रिया ऐसी होनी चाहिए, जिससे पात्र नागरिकों को अनावश्यक कठिनाइयों का सामना न करना पड़े। इस मामले में कांग्रेस की ओर से निर्वाचन आयोग की संबंधित शर्त को चुनौती दी गई थी।

हाई कोर्ट के मौजूदा रुख के बाद अब इस मुद्दे पर आगे की कानूनी कार्रवाई जनहित याचिका के माध्यम से होने की संभावना है। यदि याचिकाकर्ता दोबारा अदालत का रुख करते हैं, तो निर्वाचन आयोग की शर्त और उसके मतदाताओं पर पड़ने वाले प्रभाव को व्यापक जनहित के संदर्भ में उठाया जा सकता है। फिलहाल दिल्ली हाई कोर्ट ने मौजूदा याचिका पर सुनवाई नहीं की और इसे वापस लेने की अनुमति देते हुए मामले को जनहित याचिका के रूप में प्रस्तुत करने का रास्ता सुझाया है। इस कारण निर्वाचन आयोग की संबंधित शर्त पर कानूनी विवाद अभी समाप्त नहीं हुआ है।

न्यूज ब्रीफ

लघु नाटिका से दिया नशामुक्ति का संदेश

भारतेन्दु संवाददाता, कांगड़ा। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला जमानाबाद के प्रांगण में एकदिवसीय राष्ट्रीय सेवा योजना शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का शुभारंभ प्रधानाचार्य एकता गौतम ने किया। उन्होंने विद्यार्थियों को निस्वार्थ भाव से समाजसेवा करने के लिए प्रेरित किया। शिविर के दौरान एनएसएस स्वयंसेवकों ने स्कूल परिसर में बरसात के दौरान उगे अवांछित पौधों को हटाया तथा अवरुद्ध नालियों की सफाई कर निकासी व्यवस्था को दुरुस्त किया। स्वयंसेवकों ने विद्यालय की मुख्य फुलवारी की भी सफाई कर उसे व्यवस्थित किया। कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करने के लिए लघु नाटिका प्रस्तुत की गई। एंटी ड्रग क्लब के सदस्यों ने भी नशे के खिलाफ चर्चा में भाग लिया। कार्यक्रम के अंत में स्वयंसेवकों ने आसपास स्वच्छता बनाए रखने और कूड़ा-कचरा न फैलाने की शपथ ली। शिविर में कार्यक्रम अधिकारी अतुल चौधरी, सपना कुमारी सहित अन्य अध्यापक मौजूद रहे।

कांगड़ा जिले में 12 सितंबर को लोक अदालतों में 15000 मामलों का होगा निस्तारण

भारतेन्दु संवाददाता, धर्मशाला। हिमाचल प्रदेश विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा आपसी समझौता करवाने के लिए 12 सितंबर को ज़िला व उपमण्डल न्यायालयों पर राष्ट्रीय लोक अदालतों का आयोजन किया जा रहा है।सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण आर. मिहुल शर्मा देते हुए बताया कि जिला कांगड़ा में लगभग 15000 मामलों को सुनवाई के लिए रखा गया है। जिनमें बैंक से संबंधित, श्रम विवाद, बिजली व पानी के बिल, वैवाहिक विवाद, चैक बाऊसिंग, पूर्व मुकदमेबाजी व लंबित मामलों पर सुनवाई होगी। वे व्यक्ति जो मुकदमे से पहले संबंधित व्यक्ति अथवा विभाग से समझौता करने का इच्छुक है तो वह संबंधित कोर्ट में आवेदन कर सकता है। उन्होंने आम जनता से आग्रह किया है कि 12 सितंबर को इन लोक अदालत के जरिए अपने मामले सुलझाकर समय और धन की बचत करें।

आर्थिक आधार पर आरक्षण की मांग को लेकर गोहर में निकाली आक्रोश रैली

भारतेन्दु संवाददाता, मंडी। जातिगत आरक्षण के विरोध में देवभूमि सवर्ण संगठन ने वीरवार को गोहर उपमंडल में चैलचौक से एसडीएम कार्यालय तक आक्रोश रैली निकाली। प्रदर्शनकारियों ने जाति के आधार पर आरक्षण व्यवस्था समाप्त कर आर्थिक आधार पर आरक्षण लागू करने की मांग उठाई। रैली के बाद तहसीलदार गोहर के माध्यम से राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश और मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा गया। संगठन के सदस्यों ने कहा कि वे आरक्षण के विरोध में नहीं हैं, लेकिन इसका आधार जाति के बजाय आर्थिक स्थिति होनी चाहिए। उनका कहना था कि किसी भी जाति और धर्म के आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्ति को आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए। प्रदर्शनकारियों ने यूजीसी रोलबैक, कानून और जातिगत आरक्षण के खिलाफ भी नाराजगी जताई। उन्होंने केंद्र सरकार की नीतियों पर सवाल उठाते हुए कहा कि वोट बैंक की राजनीति से वे आहत हैं। रैली में महिलाओं सहित बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। इस दौरान राजू भंगरोहिया, रविन्द्र राणा, टेक सिंह ठाकुर और अन्य मौजूद रहे।

14 माह में बनकर तैयार हुआ डढंब स्कूल का अतिरिक्त भवन : केवल सिंह पठानिया

भारतेन्दु संवाददाता, धर्मशाला। शाहपुर के विधायक व उपमुख्य सचेतक केवल सिंह पठानिया ने वीरवार को राजकीय उच्च विद्यालय डढंब में 33 लाख रुपए की लागत से निर्मित तीन अतिरिक्त कमरों वाले भवन का लोकार्पण किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि स्कूल के इस अतिरिक्त भवन का निर्माण मात्र 14 माह में पूरा किया गया है। उन्होंने भवन के लिए 33 लाख रुपये की धनराशि उपलब्ध करवाने पर मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार शिक्षा के क्षेत्र में लगातार महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। प्रदेश के कुछ सरकारी स्कूलों में सीबीएसई पाठ्यक्रम शुरू किया गया है, जिससे सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों की संख्या बढ़ी है। आने वाले समय में अन्य स्कूलों में भी सीबीएसई पाठ्यक्रम शुरू करने की योजना है। उन्होंने बताया कि वर्तमान सरकार के कार्यकाल में इस पंचायत में लगभग 1 से 1.50 करोड़ रुपए विभिन्न विकास कार्यों पर खर्च किए जा चुके हैं। वहीं, चंबी मैदान के विकास पर करीब 4 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं और कार्य प्रगति पर है। पठानिया ने कहा कि डढम्ब पंचायत में पेयजल व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए करीब 29 लाख रुपये खर्च कर तीन हैंडपंप स्थापित किए गए हैं, जबकि तीनों हैंडपंपों में विद्युत मोटर भी लगाई गई हैं। इस अवसर पर उन्होंने उपस्थित लोगों को जामुन, गलगल तथा नींबू के पौधे भेंट कर ज्यादा से ज्यादा पौधारोपण करने का आह्वान किया।

प्रदेश में 16 सितंबर तक धीमा रहेगा मानसून, कोई अलर्ट नहीं

अनिल कुमार शर्मा, भारतेन्दु संवाददाता, शिमला। हिमाचल प्रदेश में मानसून की रफ्तार धीमी पड़ गई है। राज्य के कई हिस्सों में गुरुवार को मौसम साफ रहा। राजधानी शिमला में पिछले तीन दिनों से बारिश नहीं हुई है। निचले और मैदानी क्षेत्रों में बारिश कम होने से उमस बढ़ गई है।

मौसम विभाग ने 16 सितंबर तक प्रदेश के कुछ हिस्सों में बारिश की संभावना जताई है, लेकिन इस अवधि में कहीं भी भारी बारिश का अलर्ट या चेतावनी जारी नहीं की गई है। विभाग के अनुसार इस दौरान मानसून के धीमे रहने के आसार हैं। प्रदेश में सितंबर की शुरुआत में मानसून सक्रिय रहा और कई हिस्सों में अच्छी बारिश हुई। इसके बाद बारिश का दौर कमजोर पड़ गया। बारिश का दौर कम होने से भूस्खलन के कारण बंद सड़कों को बहाल करने के काम में तेजी आई है। राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र के अनुसार वीरवार शाम तक प्रदेश में भूस्खलन के कारण 61 सड़कें बंद थीं। आठ बिजली ट्रांसफार्मर और दो पेयजल योजनाएं भी प्रभावित रहीं।

मंडी जिले में 30, कुल्लू में 11 और कांगड़ा में 10 सड़कें बंद हैं। चंबा जिले के डलहौजी में छह और शिमला जिले के रामपुर में दो बिजली ट्रांसफार्मर ठप हैं। रामपुर में दो पेयजल योजनाएं भी बंद हैं। मौसम विभाग के अनुसार 11 सितंबर को सिरमौर, सोलन, कांगड़ा और मंडी जिलों के कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इस दिन भी प्रदेश में भारी बारिश का कोई अलर्ट जारी नहीं किया गया है। 12 से 16 सितंबर के बीच कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला, सोलन, सिरमौर और बिलासपुर जिलों के कुछ क्षेत्रों में बारिश होने की संभावना है।

राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र की रिपोर्ट के अनुसार मानसून सीजन में बारिश से जुड़े हादसों में 288 लोगों की मौत हुई है, जबकि 518 लोग घायल हुए हैं और चार लोग लापता हैं। मृतकों में 172 की मौत सड़क हादसों में हुई है। 116 लोगों की जान भूस्खलन, फ्लैश फ्लड, फिसलने, बहने और अन्य बारिश जनित हादसों में गई है।

1,638 करोड़ की संपत्ति तबाह, 127 घर पूरी तरह ध्वस्त

मानसून सीजन में प्रदेश में 127 घर, 17 दुकानें और 469 पशुशालाएं पूरी तरह ध्वस्त हुई हैं। 500 घरों को आंशिक नुकसान पहुंचा है। मानसून से प्रदेश में 1,638 करोड़ रुपये की चल और अचल संपत्ति को नुकसान हुआ है। इसमें लोक निर्माण विभाग को अकेले 1,218 करोड़ रुपये का नुकसान शामिल है। हिमाचल प्रदेश में इस साल मानसून ने 30 जून को दस्तक दी थी। प्रदेश में एक जून से 10 सितंबर तक सामान्य से 11 प्रतिशत कम बारिश दर्ज की गई है। हिमाचल प्रदेश से मानसून की सामान्य विदाई 24 सितंबर के आसपास मानी जाती है।

नेरचौक मेडिकल कॉलेज को सुपर स्पेशलिटी हब बनाने को लेकर नड्डा से मिले विधायक गांधी

भारतेन्दु संवाददाता, मंडी। मंडी जिला के बल्ह विधानसभा क्षेत्र के विधायक इंद्र सिंह गांधी ने नेरचौक मेडिकल कॉलेज एवं प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं की बदहाल स्थिति को लेकर गंभीर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि नेरचौक मेडिकल कॉलेज को प्रदेश के एक प्रमुख स्वास्थ्य संस्थान के रूप में विकसित करने के लिए केंद्र सरकार के सहयोग से यहां सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक, पैरामेडिकल संस्थान तथा मेडिकल यूनिवर्सिटी जैसी महत्वपूर्ण परियोजनाओं को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है।

बल्ह की स्वास्थ्य समस्याओं को लेकर सौंपा मांगपत्र विधायक इंद्र सिंह गांधी ने कहा कि उन्होंने दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा से मुलाकात कर बल्ह विधानसभा क्षेत्र सहित हिमाचल प्रदेश की स्वास्थ्य सुविधाओं से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने कहा कि मुलाकात के दौरान उन्होंने बल्ह की जनता को स्वास्थ्य सेवाओं में आ रही समस्याओं, नेरचौक मेडिकल कॉलेज की आवश्यकताओं तथा क्षेत्र में चिकित्सा शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार को लेकर अपनी बात रखी और केंद्रीय मंत्री को मांगपत्र सौंपा। उन्होंने कहा कि नेरचौक मेडिकल कॉलेज में सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक की स्थापना, पैरामेडिकल संस्थान के निर्माण तथा मेडिकल यूनिवर्सिटी के लिए उपलब्ध भूमि का उपयोग करने सहित कई महत्वपूर्ण मांगें केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के समक्ष रखी गई हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि केंद्र सरकार के स्तर पर इन विषयों पर सकारात्मक पहल होगी और नेरचौक को भविष्य में आधुनिक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा के बड़े केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। इंद्र सिंह गांधी ने कहा कि पैरामेडिकल संस्थान के निर्माण के लिए केंद्र सरकार की करीब 12 करोड़ रुपए की राशि विभाग के पास लंबित है। इसके साथ ही मेडिकल कॉलेज नेरचौक के साथ लगभग 10 बीघा भूमि भी उपलब्ध है, जहां पैरामेडिकल संस्थान का निर्माण किया जा सकता है।

दियोटसिद्ध के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को मिली पेंशन

बैंक खातों में पहुंची राशि, मंदिर न्यास ने व्यवस्था में किए अहम बदलाव

भारतेन्दु संवाददाता, हमीरपुर। उत्तर भारत की प्रमुख सिद्धपीठ बाबा बालक नाथ मंदिर दियोटसिद्ध से सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों को लंबे इंतजार के बाद पेंशन सुविधा मिलना शुरू हो गई है।

पहली पेंशन राशि कर्मचारियों के बैंक खातों में पहुंच गई है। इससे सेवानिवृत्त कर्मचारियों में खुशी का माहौल है। राज्य सरकार ने करीब एक वर्ष पहले पेंशन योजना को स्वीकृति प्रदान की थी, लेकिन तकनीकी कारणों के चलते इसका लाभ मिलने में देरी हुई। पेंशन मिलने के बाद कर्मचारी वीरवार को उपायुक्त और अतिरिक्त उपायुक्त कार्यालय पहुंचे, जहां उनका सम्मान किया गया। डीसी गंधर्व राठौर ने बताया कि मंदिर न्यास की व्यवस्थाओं में सुधार के लिए पिछले छह महीनों तक व्यापक अध्ययन किया गया। इस दौरान प्रत्येक विभाग, कार्य और प्रक्रिया की समीक्षा कर कमियों तथा सुधार की संभावनाओं का आकलन किया गया। इसके बाद नई मानक संचालन प्रक्रिया तैयार कर मंदिर में लागू की गई है। इसका उद्देश्य श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करवाने के साथ न्यास के कार्यों में पारदर्शिता सुनिश्चित करना है।

उन्होंने बताया कि मंदिर कर्मचारियों के लिए नई वेशभूषा निर्धारित की गई है। विशेष रूप से चढ़ावे की गिनती करने वाले कर्मचारियों के लिए बिना जेब वाली वेशभूषा अनिवार्य की गई है। इससे गिनती प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी और श्रद्धालुओं का विश्वास भी मजबूत होगा। मंदिर परिसर की सुरक्षा व्यवस्था को भी सुदृढ़ किया गया है। नए सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और महत्वपूर्ण स्थानों पर अतिरिक्त निगरानी की व्यवस्था की गई है। चढ़ावे की गिनती के दोनों केंद्रों पर लगातार निगरानी रहेगी तथा सीसीटीवी फुटेज को लंबे समय तक सुरक्षित रखा जाएगा।

उपायुक्त ने कहा कि नई व्यवस्था तैयार करते समय अधिकारियों के साथ श्रद्धालुओं से भी सुझाव लिए गए। दर्शन, स्वच्छता, पेयजल और विश्राम जैसी सुविधाओं को लेकर प्राप्त प्रतिक्रियाओं को प्रक्रिया में शामिल किया गया है। उन्होंने कहा कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पेंशन देने में देरी जरूर हुई, लेकिन तकनीकी त्रुटियां दूर कर अब योजना लागू कर दी गई है। पेंशन की अधिकतम सीमा 25 हजार रुपये है। कर्मचारियों द्वारा सेवा अवधि में निर्धारित नियमों के अनुसार जमा की गई राशि को पेंशन योजना का आधार बनाया गया है। उन्होंने कहा कि मंदिर की सेवा में जीवन समर्पित करने वाले कर्मचारियों का सम्मान करना न्यास का दायित्व है।

चांदपुर में विधायक जम्वाल ने किया नए वाहन का शुभारंभ

भारतेन्दु संवाददाता, बिलासपुर। सदर विधानसभा क्षेत्र के विधायक त्रिलोक जम्वाल ने चांदपुर स्थित एक वाहन शोरूम में नए वाहन का विधिवत शुभारंभ किया।

इस अवसर पर स्थानीय लोग, शोरूम प्रबंधन और कर्मचारी मौजूद रहे। विधायक ने शोरूम प्रबंधन और क्षेत्रवासियों को नए प्रतिष्ठान के लिए शुभकामनाएं दीं। समारोह को संबोधित करते हुए विधायक त्रिलोक जम्वाल ने कहा कि चांदपुर जैसे प्रमुख क्षेत्र में वाहन शोरूम खुलने से स्थानीय युवाओं को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। उन्होंने कहा कि इस तरह के व्यावसायिक प्रतिष्ठानों से क्षेत्र की आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलता है। स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर उपलब्ध होने से युवाओं को अपने क्षेत्र में ही काम करने का अवसर मिलेगा। विधायक ने कहा कि वाहनों की बिक्री से प्रदेश सरकार को वस्तु एवं सेवा कर तथा अन्य करों के रूप में राजस्व प्राप्त होता है। इससे सरकारी आय में वृद्धि होने के साथ क्षेत्र के विकास को भी गति मिलती है। उन्होंने स्थानीय उद्यमियों और व्यापारियों से क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने का आह्वान किया। कार्यक्रम में बिलासपुर भाजपा के मीडिया प्रभारी सुदेश ठाकुर भी विशेष रूप से उपस्थित रहे।

करेरी के लिए बस सेवा शुरू करने पर पंचायत प्रतिनिधियों ने जताया विधायक का आभार

भारतेन्दु संवाददाता, धर्मशाला। शाहपुर विधानसभा के करेरी क्षेत्र के लोगों के लिए 79 वर्षों बाद बस सेवा शुरू होने पर वीरवार को रैत स्थित कांग्रेस कार्यालय में लोगों ने उपमुख्य सचेतक एवं स्थानीय विधायक केवल सिंह पठानिया का आभार व्यक्त किया। इस मौके पर पंचायत खड़ी बही की प्रधान रानी देवी, उपप्रधान हेमराज, पंचायत सदस्यों एवं अन्य क्षेत्रवासियों ने शाहपुर के विधायक एवं उपमुख्य सचेतक केवल सिंह पठानिया से मुलाकात कर उनका आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर केवल सिंह पठानिया ने कहा कि जनता की समस्याओं का समाधान और क्षेत्र में बेहतर परिवहन सुविधाएं उपलब्ध करवाना उनकी प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि सरकार के सहयोग से क्षेत्र की वर्षों पुरानी मांग को पूरा किया गया है और आगे भी जनहित से जुड़े कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाएगा।

राष्ट्र निर्माण और संगठन की असली ताकत है मातृशक्ति : जीतराम कटवाल

भारतेन्दु संवाददाता, बिलासपुर। झंडूता विधानसभा क्षेत्र के विधायक जीतराम कटवाल ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी ताकत उसका संगठनात्मक ढांचा है। यह संगठन केवल चुनाव जीतने का साधन नहीं, बल्कि राष्ट्र निर्माण का एक व्यापक जन-अभियान है। उन्होंने जोर देकर कहा कि जिस राजनीतिक व सामाजिक दल की मातृशक्ति मजबूत होगी, समाज में उसकी जड़ें उतनी ही अधिक गहरी और सुदृढ़ होंगी।

विधायक कटवाल वीरवार को भाजपा महिला मोर्चा के झंडूता एवं शाहतलाई मंडलों की संयुक्त बैठक को संबोधित कर रहे थे। बैठक में महिला मोर्चा के संगठनात्मक कार्यों की गहन समीक्षा की गई और आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा तय की गई। जीतराम कटवाल ने कहा कि भाजपा की मूल विचारधारा 'राष्ट्र प्रथम और संगठन सर्वोपरि' की है। इस विचार को धरातल पर उतारने में महिला कार्यकर्ताओं की भूमिका सबसे प्रभावी साबित होती है। उन्होंने आह्वान किया कि प्रत्येक बूथ पर सक्रिय महिला कार्यकर्ताओं की टोली गठित की जाए, जो सीधे परिवारों से संवाद स्थापित कर केंद्र सरकार की जनकल्याणकारी नीतियों और योजनाओं की जानकारी हर घर तक पहुंचाए। विधायक ने कहा कि भारतीय संस्कृति में नारी को समाज की दिशा निर्धारित करने वाली शक्ति माना गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश 'विकसित भारत' के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है और यह लक्ष्य आधी आबादी की सक्रिय सहभागिता के बिना संभव नहीं है।

जबली खुली जेल में बंद कैदी की एम्स में मौत, न्यायिक जांच शुरू

भारतेन्दु संवाददाता, बिलासपुर। मुक्त कारागार (खुली जेल) जबली में न्यायिक हिरासत में सजा काट रहे एक कैदी की तबीयत बिगड़ने के बाद एम्स कोठीपुरा में मौत हो गई। मृतक की पहचान लखवीर सिंह (40) पुत्र देवराज, निवासी बाग ठेडू, तहसील घुमारवीं, जिला बिलासपुर के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार 9 सितंबर की रात कैदी की तबीयत अचानक गंभीर हो गई, जिसके बाद उसे उपचार के लिए एम्स कोठीपुरा ले जाया गया। यहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। न्यायिक हिरासत में मौत होने के कारण मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी बिलासपुर के निर्देश पर मामले की न्यायिक जांच शुरू कर दी गई है। न्यायिक मजिस्ट्रेट की निगरानी में आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी की गई। शव का पोस्टमार्टम मेडिकल बोर्ड द्वारा करवाया गया तथा पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी की गई। अधिकारियों के अनुसार मौत के वास्तविक कारणों का पता पोस्टमार्टम और विसरा जांच रिपोर्ट आने के बाद ही चल सकेगा।

बाईपास रोड का जर्जर बस स्टॉप बना परेशानी का सबब, छत गिरने का खतरा

भारतेन्दु संवाददाता, कांगड़ा। प्रदेश सरकार ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में लोगों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करवाने के दावे कर रही है, लेकिन कांगड़ा में कई स्थानों पर सार्वजनिक सुविधाओं की स्थिति इन दावों के विपरीत नजर आ रही है।

कांगड़ा बाईपास रोड पर स्थित बस स्टॉप लंबे समय से जर्जर हालत में है, जिससे यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बस स्टॉप की छत और अन्य हिस्से काफी खराब हो चुके हैं। छत की हालत ऐसी है कि किसी भी समय इसका कोई हिस्सा गिर सकता है, ऐसे में यहां बस का इंतजार करने वाले यात्रियों की सुरक्षा को लेकर भी चिंता बनी हुई है। यात्रियों का कहना है कि बस स्टॉप होने के बावजूद उन्हें बैठने और बारिश व धूप से बचने की पर्याप्त सुविधा नहीं मिल रही है। स्थानीय लोगों के अनुसार सुबह के समय यहां दूध विक्रेताओं, कर्मचारियों और अन्य यात्रियों की काफी आवाजाही रहती है। टांडा होते हुए पालमपुर, धर्मशाला और अन्य क्षेत्रों की ओर जाने वाले यात्रियों के लिए यह बस स्टॉप महत्वपूर्ण है। प्रतिदिन बड़ी संख्या में लोग यहां बसों का इंतजार करते हैं, लेकिन जर्जर ढांचे के कारण उन्हें सड़क किनारे खड़े होकर बस का इंतजार करना पड़ता है। स्थानीय निवासी हेमलता, किशोर चंद, रूमी देवी, बारखु राम, कुलभूषण कुमार, रिंपी देवी, रश्मी देवी, पप्पू कुमार और सलोचना देवी सहित अन्य लोगों ने प्रदेश सरकार और नगर परिषद कांगड़ा से बस स्टॉप की जल्द मरम्मत करवाने की मांग की है।

लोगों ने कहा कि बरसात और तेज धूप के दौरान परेशानी और बढ़ जाती है। समय रहते मरम्मत न होने पर हादसे की आशंका बनी हुई है।

क्या कहना है नगर परिषद अध्यक्ष का

नगर परिषद कांगड़ा की अध्यक्ष सुमन वर्मा ने कहा कि मामला उनके ध्यान में आया है और इसे नगर परिषद की आगामी बैठक में रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि यात्रियों की सुविधा के लिए ऐसे स्थानों को नए तरीके से विकसित कर बेहतर बनाया जाएगा, ताकि लोगों को बैठने सहित अन्य आवश्यक सुविधाएं मिल सकें और शहर की सुंदरता भी बढ़े।

संसदीय समिति का अध्ययन दौरा संपन्न, अनुराग ने की खनन व इस्पात क्षेत्र की प्रमुख इकाइयों की समीक्षा

भारतेन्दु संवाददाता, हमीरपुर। पूर्व केंद्रीय कैबिनेट मंत्री व सांसद अनुराग सिंह ठाकुर की अध्यक्षता में कोयला, खान व इस्पात संबंधी संसदीय स्थायी समिति का कोच्चि अध्ययन दौरा तीन महत्वपूर्ण बैठकों के साथ संपन्न हुआ। समिति ने देश की खनिज एवं इस्पात क्षमताओं को मजबूत करने से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों की विस्तृत समीक्षा की।

अध्ययन दौरे के अंतिम दिन समिति ने खान मंत्रालय के प्रमुख सार्वजनिक उपक्रमों नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड और हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के कामकाज की समीक्षा की। अनुराग सिंह ठाकुर और समिति के सदस्यों ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ उत्पादन क्षमता, परिचालन दक्षता, क्षमता विस्तार योजनाओं तथा गैर-लौह धातुओं की बढ़ती राष्ट्रीय मांग को पूरा करने के लिए आवश्यक रणनीतिक पहलों पर चर्चा की। ये धातुएं औद्योगिक विनिर्माण और स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण के लिए महत्वपूर्ण हैं। इसके बाद समिति ने इस्पात मंत्रालय से संबंधित दो विस्तृत सत्रों में देश की आपूर्ति श्रृंखला और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने पर विचार-विमर्श किया। KIOCL लिमिटेड, MSTC लिमिटेड और MECON लिमिटेड के प्रतिनिधियों के साथ भारत में लौह अयस्क हैंडलिंग बुनियादी ढांचे के उन्नयन पर चर्चा की गई। समिति ने इसे लॉजिस्टिक्स लागत कम करने और परिचालन दक्षता बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण बताया। अंतिम सत्र में समिति ने नैशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन और नैशनल स्टील लिमिटेड के कामकाज की व्यापक समीक्षा की। अनुराग ने परिचालन व्यवस्था के आधुनिकीकरण, इस्पात उत्पादन में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने तथा देश के महत्वाकांक्षी बुनियादी ढांचा एवं आर्थिक विकास लक्ष्यों में इन महत्वपूर्ण उद्योगों की प्रभावी भूमिका सुनिश्चित करने पर जोर दिया। उन्होंने आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य के अनुरूप खनिज एवं इस्पात क्षेत्र को और मजबूत करने की आवश्यकता रेखांकित की।

अवसर लुहनू मैदान से 330 किलोमीटर लंबे 'संकल्प एक्सपीडिशन-2026' का शुभारंभ

कैडेट्स गोबिंद सागर में करेंगे 330 किलोमीटर नौकायन

अमर सिंह ठाकुर, भारतेन्दु संवाददाता, बिलासपुर। युवाओं के व्यक्तित्व निर्माण के लिए केवल किताबी शिक्षा पर्याप्त नहीं है। उन्हें चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में निर्णय लेना, टीम के साथ काम करना और विपरीत परिस्थितियों में धैर्य बनाए रखना भी सीखना चाहिए।

साहसिक अभियानों के माध्यम से युवाओं में नेतृत्व, अनुशासन और आत्मविश्वास जैसे गुण विकसित होते हैं। यह बात एम्स बिलासपुर के कार्यकारी निदेशक लेफ्टिनेंट जनरल डॉ. दलजीत सिंह, वीएसएम, एवीएसएम सेवानिवृत्त ने बुधवार को लुहनू मैदान में आयोजित 'संकल्प एक्सपीडिशन-2026' के शुभारंभ अवसर पर कही। उन्होंने कहा कि जल अभियान कैडेट्स को आरामदायक माहौल से बाहर निकलकर वास्तविक चुनौतियों का सामना करने का अवसर प्रदान करते हैं। ऐसे अनुभवों से नेतृत्व क्षमता, निर्णय लेने की दक्षता, आत्मनिर्भरता और कठिन परिस्थितियों में संयम बनाए रखने का आत्मविश्वास विकसित होता है। उन्होंने एनसीसी कैडेट्स से अभियान को केवल साहसिक यात्रा न मानकर इससे मिलने वाले अनुभवों को जीवन में उतारने का आह्वान किया।

लेफ्टिनेंट जनरल डॉ. दलजीत सिंह ने लुहनू मैदान से नौकाओं को हरी झंडी दिखाकर करीब 330 किलोमीटर लंबे अभियान का विधिवत शुभारंभ किया। इससे पहले एनसीसी कैडेट्स ने मुख्य अतिथि को गार्ड ऑफ ऑनर दिया। अभियान में चार राज्यों से पहुंचे करीब 70 एनसीसी कैडेट्स और प्रशिक्षक दल भाग ले रहे हैं। शुभारंभ के बाद कैडेट्स ने गोविंद सागर झील में नौकायन शुरू किया और पहले दिन करीब 32 किलोमीटर की दूरी तय कर सलनू तक पहुंचे। अभियान की खास बात यह रही कि एक नौका का संचालन पूरी तरह महिला कैडेट्स ने किया। सफलतापूर्वक नौका संचालन कर महिला कैडेट्स ने अपने आत्मविश्वास, नेतृत्व क्षमता और चुनौतियों का सामना करने के जज्बे का परिचय दिया। अभियान के शुभारंभ अवसर पर बिलासपुर के विभिन्न विद्यालयों के करीब 200 एनसीसी कैडेट्स भी मौजूद रहे। फ्लैग-ऑफ के बाद बहुउद्देश्यीय सांस्कृतिक भवन परिसर में नशामुक्ति, नशीले पदार्थों के दुरुपयोग की रोकथाम और मानसिक स्वास्थ्य को लेकर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कैडेट्स ने नुक्कड़ नाटक के माध्यम से नशे के दुष्प्रभावों से बचने का संदेश दिया।

एम्स बिलासपुर के लेफ्टिनेंट कर्नल डॉ. भूपेंद्र यादव सेवानिवृत्त तथा बाल मनोवैज्ञानिक शिवरंजनी सिंह ने कैडेट्स को तनाव, मानसिक दबाव, आत्महत्या की रोकथाम और नशे से बचाव के उपाय बताए। कैडेट्स ने विशेषज्ञों से सवाल भी किए। नशामुक्ति विषय पर आयोजित प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में डीएवी बरमाणा ने प्रथम स्थान हासिल किया। अभियान के कमांडिंग ऑफिसर कमांडर सज्जन कुमार ने बताया कि पहले दिन 32 किलोमीटर नौकायन पूरा किया गया। अभियान के दौरान कैडेट्स गोविंद सागर झील में करीब 330 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे। कार्यक्रम में डीएवी पब्लिक स्कूल की प्रधानाचार्या मोनिका वात्स्यायन, डीएसपी मदन लाल, बिलासपुर कॉलेज के प्राचार्य डॉ. पी.एस. कटवाल, कर्नल रूपेश चंदेल, होमगार्ड कमांडेंट मेजर कौंडल और डॉ. अंजनी राणा सहित अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे।

नूरपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, नशा तस्कर की 3 .32 करोड़ की संपत्ति जब्त

भारतेन्दु संवाददाता, इंदौरा। नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस जिला नूरपुर ने बड़ी कार्रवाई करते हुए चरस तस्करी के आरोपी की करीब 3.32 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त करवाई है। मामले में सक्षम प्राधिकारी, नई दिल्ली ने जिला पुलिस की वित्तीय जांच को सही मानते हुए संपत्ति की जब्ती की पुष्टि की है।

एएसपी नूरपुर धर्म चंद वर्मा ने बताया कि 29 दिसंबर 2025 को पुलिस थाना डमटाल में एनडीपीएस अधिनियम की धारा 20 और 29 के तहत मामला दर्ज किया गया था। इस मामले में आरोपी बलविंदर उर्फ बिल्ला पुत्र ज्ञान चंद, निवासी छन्नी, तहसील इंदौरा, जिला कांगड़ा को 1 किलो 852 ग्राम चरस के साथ गिरफ्तार किया गया था। जांच के दौरान पुलिस ने आरोपी की चल-अचल संपत्ति की वित्तीय जांच की। इसमें मादक पदार्थों की अवैध तस्करी से अर्जित आय से जुड़ी संदिग्ध संपत्तियों की पहचान की गई। पुलिस ने होटल-सह-रेस्तरां, दुकानों, मोटर वाहनों, अचल संपत्तियों और बैंक खातों में उपलब्ध धनराशि को अस्थायी रूप से फ्रीज कर रिपोर्ट सक्षम प्राधिकारी को भेजी। जांच में कुल संपत्ति का मूल्य 3,32,32,352.94 रुपए पाया गया था। सक्षम प्राधिकारी ने 9 सितंबर 2026 के आदेश के तहत 3,32,30,941 रुपए मूल्य की संपत्ति की जब्ती की पुष्टि की है।

पुलिस के अनुसार 10 सितंबर 2026 तक नूरपुर जिले में नशे के अवैध कारोबार से जुड़े 17 मामलों में आरोपियों की कुल 29,95,92,857 रुपए की संपत्ति जब्त करवाई जा चुकी है। कुछ अन्य मामले भी सक्षम प्राधिकारी के समक्ष विचाराधीन हैं। पुलिस ने कहा कि नशा तस्करों के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा।

न्यूज ब्रीफ

पारस का नेशनल बास्केटबॉल के लिए चयन

भारतेन्दु संवाददाता, अर्की। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय डुमैहर (अर्की) के कक्षा नौवीं के छात्र पारस ठाकुर पुत्र अमित ठाकुर, गांव देवरा, का चयन 51वीं सब-जूनियर नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप के लिए हुआ है। प्रतियोगिता 27 सितंबर से 4 अक्तूबर 2026 तक विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश में बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित की जाएगी। हिमाचल प्रदेश बास्केटबॉल टीम का प्रशिक्षण शिविर 13 सितंबर से पांवटा साहिब, सिरमौर में आयोजित होगा, जिसमें पारस भाग लेंगे और राष्ट्रीय प्रतियोगिता में हिमाचल का प्रतिनिधित्व करेंगे। विद्यालय के डीपीई राज कुमार पाल ने बताया कि मंडी में आयोजित स्टेट चैंपियनशिप में पारस ने शानदार प्रदर्शन किया, जिसके आधार पर उनका चयन हुआ। प्रधानाचार्य अरुण कुमार, पीईटी नागेश शर्मा, समस्त स्टाफ और विद्यालय प्रबंधन समिति ने पारस व उनके अभिभावकों को बधाई देते हुए उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दीं।

पड्डल मैदान में होगा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल

भारतेन्दु संवाददाता, मंडी। ऐतिहासिक पड्डल मैदान में 1 से 10 अक्तूबर तक 'शास्त्र महोत्सव व इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल' का आयोजन किया जाएगा। महोत्सव का उद्देश्य प्रदेश की छिपी प्रतिभाओं को मंच प्रदान करने के साथ स्थापित कलाकारों को भी अपनी कला प्रदर्शित करने का अवसर देना है। महोत्सव के दौरान तीन दिन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल होगा, जिसमें सांस्कृतिक, सामाजिक और मानवीय मूल्यों पर आधारित संदेशप्रद फिल्मों का निशुल्क प्रदर्शन किया जाएगा। इसके अलावा चार सांस्कृतिक संध्याओं में हिमाचली लोक संस्कृति, लाइट क्लासिकल व हिंदी-फिल्मी गीत, नृत्य, नाट्य, बॉडी बिल्डिंग और स्टैंडअप कॉमेडी प्रस्तुतियां होंगी। 50 वर्ष से अधिक आयु के दंपतियों के लिए रैंप वॉक भी आयोजित होगी। पड्डल मैदान में मेले का भी आयोजन होगा, जिसमें बच्चों और बड़ों के मनोरंजन के लिए झूले व विभिन्न स्टॉल लगाए जाएंगे। सांस्कृतिक कार्यक्रमों के ऑडिशन 11 से 13 सितंबर तक होटल कन्फर्ट, मंडी में सुबह 11 से शाम 5 बजे तक होंगे। ऑडिशन निशुल्क रहेंगे।

फाइन आर्ट्स शिक्षक भर्ती परीक्षा का परिणाम घोषित

अनिल कुमार, भारतेन्दु संवाददाता, हमीरपुर। हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग (एचपीआरसीए) ने स्कूल शिक्षा विभाग में फाइन आर्ट्स के शिक्षकों के 118 पदों को पोस्ट कोड-26033 के अंतर्गत फिक्स मानदेय के आधार पर भरने के लिए आयोजित कंप्यूटर बेस्ड स्क्रीनिंग टेस्ट (सीबीटी) का परिणाम घोषित कर दिया है। यह परीक्षा परिणाम आयोग की वेबसाइट एचपीआरसीए.एचपी.जीओवी.इन पर उपलब्ध करवा दिया गया है। आयोग के सचिव डॉ. विक्रम महाजन ने बताया कि फाइन आर्ट्स के शिक्षकों के 118 पदों के लिए 152 उम्मीदवारों ने आवेदन किया था, जिनमें से 128 उम्मीदवारों ने सीबीटी परीक्षा दी थी। इस परीक्षा में उत्तीर्ण 106 उम्मीदवारों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जा रहा है, जो कि 24 सितंबर को सुबह 10 बजे से आयोग के परिसर में आरंभ होगी। इसकी सूचना उम्मीदवारों को उनके ईमेल आईडी पर दी जाएगी। उन्हें अलग से बुलावा पत्र नहीं भेजे जाएंगे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय इन उम्मीदवारों को अपने साथ सभी आवश्यक दस्तावेजों की मूल प्रतियां, इनकी सेल्फ अटेस्टेड फोटो प्रतियों के दो-दो सेट, आवेदन पत्र की डाउनलोड कॉपी और आईडी प्रूफ इत्यादि साथ लाने होंगे। सचिव ने बताया कि अगर कोई उम्मीदवार निर्धारित तिथि को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए उपस्थित नहीं होता है तो उसे कोई और अवसर नहीं दिया जाएगा।

सायर उत्सव के लिए गायन व नृत्य के ऑडिशन शुरू

भारतेन्दु संवाददाता, अर्की। राज्य स्तरीय सायर उत्सव की सांस्कृतिक संध्याओं में प्रस्तुति देने के लिए गायन और नृत्य के ऑडिशन शुरू हो गए हैं। तीन दिन तक चलने वाले इन ऑडिशन के पहले दिन 14 प्रतिभागियों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। ऑडिशन के दौरान प्रतिभागियों ने गायन में अपनी सुर परीक्षा दी। ऑडिशन प्रक्रिया में निर्णायक मंडल के सदस्य डीएन शर्मा, नरेंद्र सिंह और नरेंद्र कुमार मौजूद रहे। उन्होंने बताया कि पहले दिन अर्की क्षेत्र के साथ-साथ सोलन और शिमला जिलों से पहुंचे प्रतिभागियों ने भी उत्साहपूर्वक भाग लिया। उन्होंने कहा कि ऑडिशन का उद्देश्य प्रतिभाशाली कलाकारों का चयन कर उन्हें राज्य स्तरीय सायर उत्सव की सांस्कृतिक संध्याओं में मंच प्रदान करना है। उन्होंने बताया कि 11 और 12 सितंबर को सुबह 11 बजे से शाम 3 बजे तक गायन और नृत्य के ऑडिशन लिए जाएंगे। इच्छुक प्रतिभागी निर्धारित समय पर पहुंचकर ऑडिशन में भाग ले सकते हैं। आयोजकों ने अधिक से अधिक प्रतिभागियों से इसमें हिस्सा लेने का आह्वान किया है।

'मेरे माहिया' गीत हुआ रिलीज

भारतेन्दु संवाददाता, मंडी। फीट ऑफ फायर फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत रोमांटिक गीत 'मेरे माहिया' दर्शकों और श्रोताओं के लिए रिलीज कर दिया गया है। प्रेम और भावनाओं से भरपूर इस गीत को लेकर कलाकारों और पूरी टीम में खासा उत्साह है। गीत के निर्माता राजा सिंह मल्होत्रा हैं, जबकि परियोजना का निर्देशन एवं प्रबंधन अमित भाटिया ने किया है। गीत के रिलीज होने के बाद इसे श्रोताओं से अच्छी प्रतिक्रिया मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। 'मेरे माहिया' में प्रेम की भावनाओं और रिश्तों की खूबसूरती को संगीतमय अंदाज में प्रस्तुत किया गया है। निर्माताओं का कहना है कि गीत को युवा वर्ग की पसंद और भावनाओं को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। फाउंडेशन की टीम ने उम्मीद जताई कि यह गीत संगीत प्रेमियों के बीच अपनी अलग पहचान बनाने में सफल रहेगा और दर्शकों का भरपूर प्यार हासिल करेगा।

अज्ञात महिला की पहचान के लिए मांगा जनसहयोग

भारतेन्दु संवाददाता, नूरपुर। चक्की खड्ड के समीप थपकौर क्षेत्र में एक अज्ञात महिला का शव बरामद हुआ है। महिला की अभी तक पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस के अनुसार महिला की अनुमानित आयु 45 से 50 वर्ष, रंग गेहुआं तथा कद करीब पांच फुट दो इंच है। शव मिलने के बाद पुलिस ने महिला की पहचान के लिए प्रयास तेज कर दिए हैं। पोस्टमार्टम करवाने के बाद शव को सिविल अस्पताल नूरपुर में रखा गया है। मामले की पुष्टि एसपी धर्मचंद वर्मा ने की है। पुलिस ने क्षेत्रवासियों से अपील की है कि महिला की पहचान में सहयोग करें और संबंधित सूचना व फोटो को अपने व्हाट्सऐप समूहों तथा सामाजिक माध्यमों पर अधिक से अधिक साझा करें, ताकि महिला के परिजनों तक सूचना पहुंचाई जा सके। यदि किसी व्यक्ति को महिला के संबंध में कोई जानकारी हो अथवा वह पहचानता हो, तो तुरंत थाना डमटाल से संपर्क करने की अपील की गई है।

विद्यार्थियों को दी करियर विकल्पों की जानकारी

भारतेन्दु संवाददाता, बिलासपुर। जिला रोजगार कार्यालय बिलासपुर के माध्यम से पीएम श्री राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बरमाणा और राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला ऋषिकेश में करियर मार्गदर्शन सत्र आयोजित किए गए। इस दौरान अधिकारियों ने 11वीं और 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों को बारहवीं के बाद उपलब्ध विभिन्न करियर विकल्पों, आवश्यक योग्यताओं तथा प्रवेश प्रक्रिया की जानकारी दी। जिला रोजगार अधिकारी राजेश मेहता ने बताया कि विद्यार्थियों को उनकी रुचि और क्षमता के अनुरूप करियर चुनने में मार्गदर्शन देने के लिए ऐसे सत्र आयोजित किए जाते हैं। विद्यार्थियों को विभिन्न रोजगार अवसरों और सरकारी योजनाओं की जानकारी भी दी गई। सत्र में विद्यार्थियों को नशे एवं मादक पदार्थों के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करते हुए स्वस्थ जीवनशैली अपनाने का संदेश दिया गया। उन्हें खेलकूद और सांस्कृतिक गतिविधियों में सक्रिय भागीदारी के लिए भी प्रेरित किया गया। इस अवसर पर ललित शर्मा, राजेश जसवाल, नरेश कुमार, दिव्यांशु सहित शिक्षक व अन्य अधिकारी मौजूद रहे।

कांग्रेस का किला ध्वस्त, शिमला जिला परिषद में लहराया भाजपा का परचम

भूपेंद्र सिंह सिसोदिया अध्यक्ष और भरत सिंह कलांटा उपाध्यक्ष निर्वाचित

◆ तीन मंत्री और चार विधायक, फिर भी कांग्रेस चारों खाने चित

अनिल कुमार शर्मा, भारतेन्दु संवाददाता, शिमला। शिमला जिला परिषद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद पर भाजपा ने कब्जा कर कांग्रेस को बड़ा राजनीतिक झटका दिया है। करीब साढ़े तीन महीने से लंबित चुनाव में भाजपा उम्मीदवार भूपेंद्र सिंह सिसोदिया अध्यक्ष निर्वाचित हुए, जबकि उपाध्यक्ष पद पर भाजपा समर्थित निर्दलीय सदस्य भरत सिंह कलांटा ने जीत दर्ज की।

अध्यक्ष पद के चुनाव में भूपेंद्र सिंह सिसोदिया को 13, कांग्रेस उम्मीदवार को 10 मत मिले और दो मत निरस्त हुए। उपाध्यक्ष पद पर भरत सिंह कलांटा को 14, कांग्रेस उम्मीदवार को 10 मत मिले और एक मत निरस्त हुआ।

इस तरह 25 सदस्यीय जिला परिषद में दोनों प्रमुख पद भाजपा के खाते में चले गए। शिमला जिला को लंबे समय से कांग्रेस का मजबूत राजनीतिक गढ़ माना जाता रहा है। मौजूदा समय में जिले से कांग्रेस के तीन कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह, अनिरुद्ध सिंह और रोहित ठाकुर तथा इन्हें मिलाकर सात विधायक हैं। इसके बावजूद जिला परिषद के दोनों शीर्ष पदों पर कांग्रेस अपना उम्मीदवार नहीं जिता सकी। खास बात यह है कि पिछली बार जिला परिषद अध्यक्ष का पद कांग्रेस की झोली में था। इस बार भाजपा ने न केवल अध्यक्ष पद हासिल किया, बल्कि उपाध्यक्ष पद पर भी अपना समर्थित उम्मीदवार जिताकर जिला परिषद में अपनी राजनीतिक पकड़ मजबूत करने का संकेत दिया है। जिला परिषद के दोनों प्रमुख पदों पर भाजपा की जीत को अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी के लिए राजनीतिक राहत के तौर पर देखा जा रहा है। लंबे इंतजार के बाद आए इन नतीजों ने शिमला की जिला राजनीति में भाजपा को बढ़त और कांग्रेस को आत्ममंथन की स्थिति में ला दिया है।

102 दिन बाद हाईकोर्ट के आदेश पर हुआ चुनाव

जिला परिषद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव लंबे समय से अटके हुए थे। जिला परिषद के चुनाव परिणाम 31 मई और 1 जून को घोषित हुए थे, लेकिन स्पष्ट बहुमत नहीं होने के कारण अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव को लेकर खींचतान बनी रही। इससे पहले अगस्त के पहले सप्ताह में बुलाई गई बैठक में भाजपा और कांग्रेस के सदस्य शामिल नहीं हुए थे और चुनाव नहीं हो सके थे। चुनाव टाले जाने का मामला प्रदेश हाईकोर्ट भी पहुंचा। हाईकोर्ट के आदेश के बाद गुरुवार को बचत भवन में उपायुक्त अनुपम कश्यप की अध्यक्षता में चुनाव प्रक्रिया पूरी हुई। 25 सदस्यीय जिला परिषद में अध्यक्ष पद के लिए 13 सदस्यों का समर्थन जरूरी था और भाजपा उम्मीदवार ने ठीक 13 मत हासिल कर यह आंकड़ा पूरा कर लिया।

कहानी कथन से शिक्षण को रोचक व प्रभावी बनाने पर जोर

भारतेन्दु संवाददाता, चलवाड़ा। तृप्ता पब्लिक वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय चलवाड़ा में अध्यापकों के व्यावसायिक विकास व शिक्षण कौशल को प्रभावी बनाने के उद्देश्य से 'कहानी कथन को शिक्षण पद्धति के रूप में अपनाने' विषय पर एकदिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया।

कार्यशाला में विद्यालय के प्रधानाचार्य राकेश राणा और स्रोत व्यक्ति कल्पना शर्मा विशेष रूप से उपस्थित रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित कर गायत्री मंत्र के उच्चारण के साथ किया गया। इसके बाद प्रधानाचार्य ने मुख्य अतिथि शगुन और स्रोत व्यक्ति कल्पना शर्मा को स्मृति चिह्न भेंट कर सम्मानित किया। स्रोत व्यक्ति कल्पना शर्मा ने कहानी कथन को शिक्षण प्रक्रिया से जोड़ने के विभिन्न तरीकों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि कहानी के माध्यम से विद्यार्थियों की कल्पनाशक्ति, रचनात्मकता, अभिव्यक्ति, सुनने की क्षमता और विषय के प्रति रुचि बढ़ाई जा सकती है।

उन्होंने विभिन्न गतिविधियों और उदाहरणों के माध्यम से शिक्षकों को इस पद्धति के व्यावहारिक पहलुओं से अवगत करवाया। प्रधानाचार्य राकेश राणा ने कहा कि बदलते समय के साथ शिक्षण की नई एवं रचनात्मक पद्धतियों को अपनाना आवश्यक है। ऐसी कार्यशालाएं शिक्षकों के ज्ञान और कौशल को विकसित करने में सहायक होती हैं। कार्यशाला में विद्यालय के 56 अध्यापकों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया।

विद्यार्थियों की अनदेखी से आक्रोशित एबीवीपी ने की विश्वविद्यालय में तालाबंदी

22वें दिन भी जारी रही भूख हड़ताल

अनिल कुमार, भारतेन्दु संवाददाता, हमीरपुर। हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय हमीरपुर में विद्यार्थियों की मांगों को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की भूख हड़ताल 22वें दिन भी लगातार जारी रही। पिछले 22 दिनों से विद्यार्थी अपनी जायज मांगों को लेकर संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन सरकार और विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से अब तक विद्यार्थियों की सुध लेने के लिए कोई ठोस पहल नहीं की गई है।

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के विभाग संयोजक भवानी ठाकुर ने कहा कि विद्यार्थी परिषद लंबे समय से विद्यार्थियों की मूलभूत एवं जायज मांगों को सरकार और प्रशासन के समक्ष रख रही है। परिषद की प्रमुख मांगों में हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय में कुलपति के रिक्त पद को शीघ्र भरना, सेल्फ फाइनेंस मॉडल पर चल रहे विश्वविद्यालय को सरकार की ओर से पर्याप्त वित्तीय सहयोग प्रदान करना तथा कैंपस की मूलभूत सुविधाओं से जुड़ी मांगों को पूरा करना शामिल है।

उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों ने अपनी आवाज सरकार तक पहुंचाने के लिए लोकतांत्रिक तरीके से हर संभव प्रयास किया। इसी कड़ी में विद्यार्थी परिषद द्वारा गांधी चौक हमीरपुर में विशाल छात्र रैली का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 2500 विद्यार्थियों ने एकजुट होकर अपनी मांगों के समर्थन में आवाज बुलंद की। इतनी बड़ी संख्या में विद्यार्थियों के सड़क पर उतरने के बावजूद सरकार की ओर से उनकी समस्याओं को गंभीरता से नहीं लिया गया। भवानी ने कहा कि 22 दिन से विद्यार्थी भूख हड़ताल पर बैठे हैं, लेकिन विडंबना यह है कि इतने लंबे समय के बाद भी न तो सरकार का कोई प्रतिनिधि विद्यार्थियों से मिलने पहुंचा और न ही विश्वविद्यालय प्रशासन का कोई जिम्मेदार अधिकारी उनकी सुध लेने आया। यह केवल विद्यार्थियों की मांगों की अनदेखी नहीं, बल्कि प्रदेश के भविष्य की आवाज को नजरअंदाज करने जैसा है।

उन्होंने स्पष्ट किया कि विद्यार्थी परिषद किसी टकराव की पक्षधर नहीं है, लेकिन जब 22 दिनों तक विद्यार्थियों की आवाज सुनने वाला कोई नहीं हो, तो आंदोलन को आगे बढ़ाना विद्यार्थियों की मजबूरी बन जाता है।

बसंतपुर स्कूल में हिंदी शिक्षक की कमी हुई दूर ग्रामीणों ने विधायक अवस्थी का जताया आभार

भारतेन्दु संवाददाता, अर्की। उपमंडल अर्की के अंतर्गत राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय बसंतपुर में लंबे समय से रिक्त चल रहे हिंदी शिक्षक के पद को भर दिया गया है। विद्यालय में टीजीटी (हिंदी) नंद लाल की तैनाती हुई है। उन्होंने वीरवार को विद्यालय पहुंचकर कार्यभार संभाल लिया। विद्यालय के कार्यकारी प्रधानाचार्य लेखराम पंवर ने उनकी ज्वाइनिंग करवाई।

बसंतपुर पंचायत के उपप्रधान धनीराम ठाकुर ने हिंदी शिक्षक के रिक्त पद को भरने के लिए अर्की के विधायक संजय अवस्थी का विशेष आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि विद्यालय में काफी समय से हिंदी शिक्षक का पद रिक्त होने के कारण विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित हो रही थी। इस समस्या को देखते हुए उन्होंने विधायक के समक्ष शिक्षक की तैनाती का आग्रह किया था। धनीराम ठाकुर ने कहा कि विधायक संजय अवस्थी के प्रयासों से अब विद्यालय में हिंदी विषय का शिक्षक उपलब्ध हो गया है। इससे विद्यार्थियों की पढ़ाई सुचारू होने के साथ उन्हें विषय की बेहतर शिक्षा मिल सकेगी। उन्होंने कहा कि शिक्षक की तैनाती से अभिभावकों और ग्रामीणों में भी खुशी का माहौल है। पंचायत उपप्रधान ने समस्त पंचायतवासियों और अभिभावकों की ओर से विधायक संजय अवस्थी का आभार जताते हुए उम्मीद जताई कि क्षेत्र की अन्य शिक्षा संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए भी इसी तरह प्रयास जारी रहेंगे।

पद्मश्री विजय ने एसपीयू कुलपति से की भेंट

भारतेन्दु संवाददाता, मंडी। पद्मश्री सम्मान से अलंकृत प्रसिद्ध कला इतिहासकार विजय शर्मा ने सरदार पटेल विश्वविद्यालय मंडी के कुलपति आचार्य ललित कुमार अवस्थी से भेंट की। कुलपति ने उनका हिमाचली टोपी व स्मृति चिह्न भेंट कर स्वागत किया। इस दौरान मंडी की ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और उसे नई पीढ़ी से जोड़ने को लेकर चर्चा हुई। बैठक में मंडी में संग्रहालय की स्थापना, पहाड़ी चित्रकला पर कार्यशाला, कला एवं संस्कृति आधारित डिप्लोमा पाठ्यक्रम तथा 'मंडी@500' के माध्यम से पांच शताब्दियों की विरासत के संरक्षण पर विचार-विमर्श किया गया। कुलपति ने कहा कि विश्वविद्यालय मंडी की विरासत के अकादमिक अध्ययन और संरक्षण को प्राथमिकता दे रहा है। बाद में विजय शर्मा ने इतिहास विभाग के विशेष व्याख्यान में विद्यार्थियों को संबोधित किया।

स्वारघाट में 10 .50 ग्राम चिट्टे के साथ मंडी के तीन युवक गिरफ्तार

अमर सिंह ठाकुर, भारतेन्दु संवाददाता, बिलासपुर। नशा तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत स्पेशल डिटेक्टिव टीम बिलासपुर और स्वारघाट पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने कैंचीमोड़ पर नाकाबंदी के दौरान एक कार से 10.50 ग्राम चिट्टा (हेरोइन) बरामद कर मंडी जिले के तीन युवकों को गिरफ्तार किया है।

मामले की जांच आगे बढ़ाते हुए पुलिस ने पंजाब में दबिश देकर मुख्य सप्लायर को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार 7 सितंबर को कैंचीमोड़ के समीप नियमित चैकिंग के दौरान एक कार को रोका गया। तलाशी लेने पर उसमें सवार तीन युवकों के कब्जे से 10.50 ग्राम हेरोइन बरामद हुई। आरोपियों की पहचान प्रेम लाल (31) और चमन लाल (30), निवासी सकरोहा, तहसील बल्ह, जिला मंडी तथा ललित कुमार (41), निवासी जतरौर, डाकघर सकरोहा, तहसील बल्ह, जिला मंडी के रूप में हुई है। पुलिस थाना स्वारघाट में एनडीपीएस एक्ट की धारा 21 व 29 के तहत मामला दर्ज किया गया।

गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने आरोपियों के मोबाइल फोन, बैंक खातों और अन्य डिजिटल रिकॉर्ड की जांच की। तकनीकी विश्लेषण में पंजाब के एसबीएस नगर जिले के सुधा माजरा निवासी मलविंद्र सिंह (31) की कथित तौर पर मुख्य सप्लायर के रूप में पहचान हुई। इसके बाद पुलिस टीम ने पंजाब में दबिश देकर उसे गिरफ्तार कर लिया। प्रारंभिक जांच में पैसों के लेन-देन के लिए दूसरों के बैंक खातों के इस्तेमाल की बात भी सामने आई है।

विद्यार्थियों को नवाचार स्वरोजगार के अवसरों की दी जानकारी

भारतेन्दु संवाददाता, घुमारवीं। स्वामी विवेकानंद राजकीय महाविद्यालय घुमारवीं की संस्थागत नवाचार परिषद द्वारा 'सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्रालय के नवोद्यम केंद्र : उच्च शिक्षण संस्थानों में नवाचार को बढ़ावा' विषय पर गतिविधि आयोजित की गई। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों और शिक्षकों में नवाचार, उद्यमिता तथा स्वरोजगार के प्रति जागरूकता बढ़ाना था। देशभर में ऑनलाइन माध्यम से आयोजित कार्यक्रम में मुख्यातिथि डॉ. दीपान साहू और उत्कृष्ट माथुर ने विद्यार्थियों को नवाचार व नए उद्यमों से जुड़े अवसरों की जानकारी दी।

विद्यार्थियों को नए विचार विकसित करने, नमूना तैयार करने, मार्गदर्शन, बौद्धिक संपदा अधिकार तथा तकनीक आधारित उद्यमिता के विभिन्न पहलुओं से अवगत करवाया गया। कॉलेज के प्राचार्य प्रो. प्रीतम लाल ने विद्यार्थियों को ऐसे कार्यक्रमों में सक्रिय भागीदारी के लिए प्रेरित किया।

दूसरी बार संसद रत्न सम्मान मिलने पर भाजपा नेताओं ने अनुराग ठाकुर को दी बधाई

अनिल कुमार, भारतेन्दु संवाददाता, हमीरपुर। भाजपा जिला हमीरपुर के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने हमीरपुर सांसद अनुराग सिंह ठाकुर को दूसरी बार प्रतिष्ठित संसद रत्न सम्मान प्राप्त करने पर बधाई दी।

भाजपा नेताओं ने कहा कि अनुराग सिंह ठाकुर ने अपनी उत्कृष्ट संसदीय कार्यशैली, प्रभावी भागीदारी और जनहित से जुड़े विषयों को संसद में मजबूती से उठाकर न केवल हमीरपुर और हिमाचल प्रदेश, बल्कि पूरे देश का गौरव बढ़ाया है। जिलाध्यक्ष राकेश ठाकुर, विधायक इंद्रदत्त लखनपाल और आशीष शर्मा, वरिष्ठ प्रदेश प्रवक्ता एवं सुजानपुर के पूर्व विधायक राजिंदर सिंह राणा, पूर्व विधायक विजय अग्निहोत्री, डॉ. अनिल धीमान और कमलेश कुमारी, जिला परिषद अध्यक्ष अनीता देवी सहित पार्टी पदाधिकारियों अजय रिंटू शर्मा, अजमेर ठाकुर, देशराज शर्मा, हरीश शर्मा, विनोद ठाकुर छंब, राजकुमारी ठाकुर तथा बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ताओं ने अनुराग सिंह ठाकुर को इस उपलब्धि के लिए शुभकामनाएं दीं।

संसद रत्न सम्मान की विशेषता यह है कि यह सामान्य पुरस्कारों की तरह केवल नामांकन आधारित सम्मान नहीं है, बल्कि संसद में सांसदों और संसदीय समितियों के प्रदर्शन से जुड़े तथ्यात्मक एवं निर्धारित मानकों के आधार पर प्रदान किया जाता है। इस सम्मान की शुरुआत वर्ष 2010 में पूर्व राष्ट्रपति डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम के सुझाव पर हुई थी। इसका उद्देश्य संसद में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले जनप्रतिनिधियों को प्रोत्साहित करना है। पुरस्कारों का चयन संसदीय प्रदर्शन से जुड़े उपलब्ध आंकड़ों, जिनमें बहसों में भागीदारी, प्रश्न पूछना, निजी सदस्य विधेयक तथा संसदीय समितियों की कार्यप्रणाली और रिपोर्ट आदि शामिल हैं, के आधार पर किया जाता है। अनुराग सिंह ठाकुर को इससे पहले वर्ष 2019 में 16वीं लोकसभा के दौरान संसद रत्न सम्मान की व्यक्तिगत श्रेणी में सम्मानित किया गया था। उस समय उन्हें ज्यूरी कमेटी स्पेशल अवार्ड प्रदान किया गया था। वह यह सम्मान प्राप्त करने वाले पहले भाजपा सांसदों में शामिल रहे। यह सम्मान उनके विशिष्ट संसदीय प्रदर्शन और संसद में प्रभावी योगदान की राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता था।

समीक्षा | एडीसी अभिषेक गर्ग ने स्वास्थ्य, शिक्षा और महिला एवं बाल विकास विभाग को दिए निर्देश

18 को हमीरपुर में दी जाएगी कृमिनाशक दवा

अनिल कुमार, भारतेन्दु संवाददाता, हमीरपुर। राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस के तहत 18 सितंबर को जिला हमीरपुर के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों और शिक्षण संस्थानों में एक से 19 साल तक के सभी बच्चों, किशोरों और नवयुवाओं, जिनकी संख्या लगभग 1,31,000 है, को कृमिनाशक दवाई एल्बेंडाजोल दी जाएगी। इनमें एक से 5 वर्ष तक के 27,419 बच्चों को विटामिन-ए की खुराक भी दी जाएगी। स्वास्थ्य विभाग के विभिन्न टीकाकरण एवं प्रतिरक्षण कार्यक्रमों की जिला स्तरीय टास्क फोर्स की बैठक की अध्यक्षता करते हुए एडीसी अभिषेक गर्ग ने यह जानकारी दी।

उन्होंने बताया कि बच्चे के पेट में कृमि होने पर उसका शारीरिक विकास प्रभावित हो सकता है और वह अनीमिया जैसी बीमारी की चपेट में भी आ सकता है। इसलिए, 19 वर्ष तक के हर बच्चे एवं युवा के लिए कृमिनाशक दवाई बहुत ही जरूरी है। बच्चों में आंखों की समस्याओं के निवारण के लिए विटामिन-ए दवाई बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि सभी आशा व आंगनबाड़ी वर्कर्स और शिक्षण संस्थानों के नोडल अधिकारी एवं प्रभारी शिक्षक बच्चों को अपनी उपस्थिति में ही यह दवाई खिलाना सुनिश्चित करें। कोई भी बच्चा इससे छूटना नहीं चाहिए। किन्हीं कारणों से छूटे बच्चों को 25 सितंबर को यह दवाई दी जाएगी। स्वास्थ्य विभाग के अन्य प्रतिरक्षण एवं टीकाकरण कार्यक्रमों की समीक्षा करते हुए एडीसी ने कहा कि जिला में 14-15 वर्ष के आयु वर्ग की 1947 यानि लगभग 66 प्रतिशत लड़कियों को सर्विकल कैंसर रोधी टीका लगाया जा चुका है।

इससे छूटी लड़कियों के टीकाकरण के लिए स्कूल स्तर पर अभियान चलाया गया है। शिक्षण संस्थानों के नोडल अधिकारी एवं शिक्षक इस आयु वर्ग की सभी लड़कियों के टीकाकरण के लिए सक्रिय योगदान दें। अभिषेक गर्ग ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग छोटे बच्चों को अलग-अलग समय पर विभिन्न वैक्सीनों की कुल 27 खुराकें निशुल्क प्रदान कर रहा है। ये वैक्सीन बच्चों को 12 बीमारियों से बचाती हैं। इसी तरह एचपीवी का टीका लड़कियों को भविष्य में सर्विकल कैंसर से बचाएगा। एडीसी ने राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम और अन्य योजनाओं की समीक्षा भी की। बैठक में जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. अजय अत्री ने कृमि मुक्ति दिवस, एचपीवी और अन्य प्रतिरक्षण कार्यक्रमों का विस्तृत ब्यौरा प्रस्तुत किया। इस अवसर पर सभी बीएमओ, शिक्षा और अन्य विभागों के अधिकारी भी उपस्थित थे।

किरपा राम चौहान अध्यक्ष देवराज महासचिव चुने गए

भारतेन्दु संवाददाता, अर्की। उपमंडल अर्की की ग्राम पंचायत पलोग के मांजू गांव स्थित देव कुरगन मंदिर परिसर में ग्रामवासियों की बैठक समाजसेवी धर्मसिंह चौहान की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में देव कुरगन सांस्कृतिक व सुधार समिति मांजू की नई कार्यकारिणी का सर्वसम्मति से गठन किया गया।

बैठक की शुरुआत में समिति की पुरानी कार्यकारिणी को भंग किया गया। इसके बाद उपस्थित ग्रामवासियों की सहमति से नई कार्यकारिणी का चुनाव करवाया गया। इसमें किरपा राम चौहान को अध्यक्ष, चंद्र प्रकाश चौहान को उपाध्यक्ष, देवराज चौहान को महासचिव, रमेश भार्गव को वित्त सचिव, चमन सिंह को सह-सचिव तथा बाबूराम शर्मा को लेखा परीक्षक चुना गया। नवनिर्वाचित पदाधिकारियों ने ग्रामवासियों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि मंदिर से जुड़े कार्यों तथा क्षेत्र के विकास को प्राथमिकता देते हुए सभी को साथ लेकर कार्य किया जाएगा। उन्होंने समिति की गतिविधियों को सफल बनाने में ग्रामीणों के सहयोग और सहभागिता को महत्वपूर्ण बताया। बैठक में देवता के गुर वेद प्रकाश चौहान, शालीग राम शर्मा, पुरुषोत्तम शर्मा और देवेंद्र शर्मा विशेष रूप से उपस्थित रहे। इसके अलावा पंचायत उपप्रधान वेद प्रकाश, पूर्व प्रधान योगेश चौहान सहित अन्य ग्रामीण मौजूद रहे।

पेज स्पिरानैक खूबसूरत गोल्फ खिलाड़ी

पेज स्पिरानैक अमेरिका की प्रसिद्ध गोल्फ खिलाड़ी, सोशल मीडिया व्यक्तित्व और खेल प्रशिक्षक हैं। उनका जन्म 26 मार्च 1993 को व्हीट रिज, कोलोराडो, अमेरिका में हुआ था। उन्होंने कम उम्र से ही गोल्फ खेलना शुरू किया और कॉलेज स्तर पर भी शानदार प्रदर्शन किया।

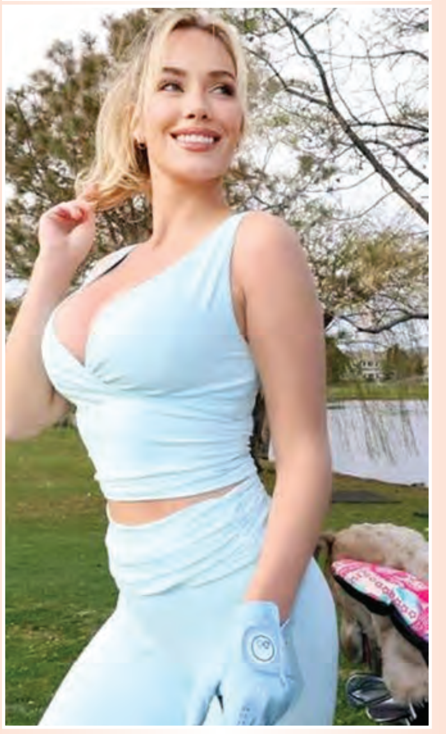

जूनियर महिला हॉकी एशिया कप

भारत ने पाक को 19-0 से रौंदा

रिकॉर्ड जीत के साथ सेमीफाइनल में किया प्रवेश, दक्षिण कोरिया या मलेशिया से होगा मुकाबला

एजेंसी, मोकी

भारतीय जूनियर महिला हॉकी टीम ने शानदार आक्रामक प्रदर्शन करते हुए वीरवार को महिला जूनियर एशिया कप-2026 के क्वार्टर फाइनल में पाकिस्तान को 19-0 से रौंदकर सेमीफाइनल में जगह बना ली। भारत ने मुकाबले के चारों क्वार्टर में गोल दागे और एकतरफा जीत दर्ज की। भारत ने पहले क्वार्टर में पांच, दूसरे में पांच, तीसरे में तीन और अंतिम क्वार्टर में छह गोल किए। भारतीय टीम ने शुरुआत से ही पाकिस्तान पर दबाव बनाए रखा और पहले पांच मिनट में ही दो पेनल्टी कॉर्नर हासिल किए, हालांकि दोनों मौकों को गोल में नहीं बदला जा सका। सातवें मिनट में पूजा साहू ने पेनल्टी कॉर्नर को गोल में बदलकर भारत का खाता खोला। इसके दो मिनट बाद रोशनी ऐंद ने फील्ड गोल कर बढ़त 2-0 कर दी। 11वें मिनट में तनुश्री दिनेश कडू ने डिफ्लेक्शन के जरिए गोल किया।

इसके बाद पाकिस्तान की टीम ने सर्किल के अंदर फाउल किया और भारत को पेनल्टी स्ट्रोक मिला। सुखवीर कौर ने 13वें मिनट में इसे आसानी से गोल में बदल दिया। इसके तुरंत बाद सानिका चंद्रकांत माने ने फील्ड गोल कर भारत को पहले क्वार्टर के अंत में 5-0 की बढ़त दिला दी।

दूसरे क्वार्टर में भी भारत का दबदबा जारी रहा। मधु सिदार ने 16वें मिनट में और गीता यादव ने 18वें मिनट में गोल कर स्कोर 7-0 कर दिया। सानिका माने ने 23वें मिनट में अपना दूसरा गोल किया, जबकि तनुजा टोप्पो ने 25वें मिनट में गोल कर भारत की बढ़त 9-0 कर दी। 27वें मिनट में पूजा मलिक ने पेनल्टी कॉर्नर को गोल में बदलकर भारत को 10-0 से आगे कर दिया। हाफ टाइम तक भारत ने आठ पेनल्टी कॉर्नर और एक पेनल्टी स्ट्रोक हासिल कर लिया था। तीसरे क्वार्टर में पूर्णिमा यादव ने 33वें मिनट में पेनल्टी कॉर्नर पर डिफ्लेक्शन के जरिए गोल किया। मधु सिदार ने 39वें मिनट में अपना दूसरा गोल किया, जबकि सुप्रिया ने 40वें मिनट में पेनल्टी कॉर्नर को गोल में बदलकर भारत को 13-0 की बढ़त दिला दी।

अंतिम क्वार्टर में भारत ने छह और गोल दागे। कृष्णा शर्मा ने 48वें मिनट में टूर्नामेंट का अपना पहला गोल किया। पूजा मलिक ने 49वें मिनट में दूसरा गोल और 51वें मिनट में तीसरा गोल करके अपनी हैट्रिक पूरी की। सुप्रिया ने 54वें मिनट में पेनल्टी कॉर्नर पर अपना दूसरा गोल किया। बिनिमा धन ने 55वें मिनट में फील्ड गोल किया, जबकि रोशनी ऐंद ने 60वें मिनट में अपना दूसरा गोल कर भारत की जीत का स्कोर 19-0 कर दिया।

आंकड़े भी भारत के एकतरफा दबदबे की गवाही देते हैं। भारत ने कुल 19 गोल किए, जबकि उसे 18 पेनल्टी कॉर्नर और एक पेनल्टी स्ट्रोक मिला। पाकिस्तान पूरे मुकाबले में न तो कोई गोल कर सका और न ही पेनल्टी कॉर्नर या पेनल्टी स्ट्रोक हासिल कर सका। अब 12 सितंबर को सेमीफाइनल में भारत का सामना क्वार्टर फाइनल-4 में दक्षिण कोरिया और मलेशिया के बीच होने वाले मुकाबले के विजेता से होगा।

पूजा मलिक को चुना प्लेयर ऑफ द मैच

एशियन गेम्स से पहले मिले डोपिंग के दो मामले

एजेंसी, नई दिल्ली। एशियन गेम्स से पहले भारत के दो खेलों में डोपिंग के मामले सामने आए हैं। 17 साल के एक भारतीय तैराक पर प्रतिबंधित टरबुटालाइन मिलने के बाद 18 महीने का बैन लगाया गया है, जिससे वह एशियन गेम्स में हिस्सा नहीं ले सकेगा। वहीं ग्रीको रोमन पहलवान दीपक के 31 मई को लिए गए यूरिन सैंपल में प्रतिबंधित क्लोमीफीन मिला है। दीपक का मामला अभी डोपिंग रोधी प्रक्रिया में है और उन पर फिलहाल अस्थायी निलंबन नहीं लगाया गया है।

दोनों खिलाड़ी एशियन गेम्स के लिए क्वालिफाई कर चुके थे। तैराक ने दो इवेंट के लिए जगह बनाई थी, जबकि दीपक ने 31 मई को लखनऊ में हुए चयन ट्रायल में जीत हासिल कर टीम में जगह बनाई थी। 17 सान के तैराक के सैंपल में फरवरी में टरबुटालाइन पाया गया था। यह एंटी-डोपिंग नियमों के तहत प्रतिबंधित बीटा-2 एगोनिस्ट है। इसके बाद उसका नाम एशियन गेम्स की संभावित टीम से हटा दिया गया था।

स्पोर्ट्स विंडो

चैंपियंस लीग में राफिन्हा के दो गोल से बार्सिलोना ने फेयेनोर्ड को 5-1 से हराया

एजेंसी, बार्सिलोना। राफिन्हा के दो गोल की बदौलत बार्सिलोना ने बुधवार को चैंपियंस लीग अभियान की शानदार शुरुआत करते हुए फेयेनोर्ड को 5-1 से हरा दिया। बार्सिलोना के लिए राफिन्हा के अलावा करीम अदेयेमी, लामिन यामाल और स्थानापन्न गैब्रियल जीसस ने गोल किए। फेयेनोर्ड की ओर से सेम स्टेइन ने एकमात्र गोल किया। बार्सिलोना ने मैच के तीसरे मिनट में ही बढ़त बना ली। रॉबर्ट लेवांडोव्स्की और फेरान टोरेस के जाने के बाद केंद्रीय स्ट्राइकर की भूमिका निभा रहे राफिन्हा ने पेनल्टी क्षेत्र में दो डिफेंडरों को छकाया और शानदार अंदाज में गेंद को गोल में पहुंचाया। इस गोल के साथ राफिन्हा ने इस सत्र में पांच मैचों में अपने गोलों की संख्या आठ कर ली है। बार्सिलोना ने इसके बाद अपनी बढ़त दोगुनी कर दी। करीम अदेयेमी ने पेनल्टी क्षेत्र के बाहर से शानदार लंबी दूरी का शॉट लगाकर गेंद को फेयेनोर्ड के गोलकीपर ट्यार्क एर्नस्ट की पहुंच से दूर गोल में पहुंचा दिया। फेयेनोर्ड ने वापसी की कोशिश की और अनीस हाज मूसा ने बार्सिलोना के गोलकीपर जोआन गार्सिया को नजदीकी पोस्ट पर बचाव करने के लिए मजबूर किया। हालांकि बार्सिलोना का दबदबा कायम रहा। जोआओ कांसोलो ने गिवाइरो रीड को छकाने के बाद शॉट लगाया, लेकिन गेंद पोस्ट के बाहरी हिस्से से टकराकर बाहर चली गई। दूसरे हाफ में राफिन्हा ने अपना दूसरा गोल किया।

विश्व तीरंदाजी पैरा सीरीज : शीतल देवी ने साधा गोल्ड पर निशाना

एजेंसी, अहमदाबाद। मेजबान भारत ने विश्व तीरंदाजी पैरा सीरीज के तीसरे चरण में चार स्वर्ण, तीन रजत और आठ कांस्य सहित कुल 15 पदक जीतकर अपने अभियान का शानदार समापन किया। पदक तालिका में हालांकि भारत पांच स्वर्ण पदक जीतने वाले चेक गणराज्य से पीछे दूसरे स्थान पर रहा। चीन ने दो स्वर्ण, छह रजत और पांच कांस्य पदकों के साथ तीसरा स्थान हासिल किया। इस प्रतियोगिता ने भारत के पैरा तीरंदाजों को 18 से 24 अक्टूबर तक आइची-नागोया में होने वाले एशियाई पैरा खेलों के लिए तैयारी का अच्छा मौका मिला। भारत की स्वर्ण पदक जीतने की मुहिम का नेतृत्व पैरालंपिक चैंपियन हरविंदर सिंह ने किया। उन्होंने विजय सुंडी के साथ मिलकर पैरा रिकर्व पुरुष युगल का खिताब जीता। हरविंदर ने प्रतियोगिता अंतिम दिन भावना के साथ जोड़ी बनाकर पैरा रिकर्व मिश्रित टीम स्पर्धा में भी स्वर्ण पदक हासिल किया।

भारत-अफगानिस्तान टी20 सीरीज से बाहर हो सकते हैं हर्षित राणा

एजेंसी, नई दिल्ली। भारत के तेज गेंदबाज हर्षित राणा अफगानिस्तान के खिलाफ 13 सितंबर से शुरू होने वाली तीन मैचों की टी-20 सीरीज से बाहर हो सकते हैं। राणा अभी हैमस्ट्रिंग चोट से पूरी तरह नहीं उबर पाए हैं और उन्हें फिट होने में और समय लगेगा। राणा को अफगानिस्तान के खिलाफ तीनों टी-20 मैचों के लिए फिटनेस के आधार पर भारतीय टीम में शामिल किया गया है। उन्हें एशियन गेम्स के लिए चुनी गई भारतीय टीम में भी जगह मिली है। बीसीसीआई के एक सूत्र ने कहा, वह अभी हैमस्ट्रिंग चोट से पूरी तरह ठीक नहीं हुए हैं। उन्हें और समय लगेगा। हर्षित राणा ने भारत के लिए अपना आखिरी मैच इंग्लैंड दौरे पर खेला था। इसके बाद से वह चोट के कारण टीम से बाहर हैं। राणा को वॉशिंगटन सुंदर जैसी हैमस्ट्रिंग चोट लगी है। हालांकि, सुंदर अब फिट हो चुके हैं और उन्हें अफगानिस्तान के खिलाफ टी-20 सीरीज के लिए फिट घोषित किया गया है।

भारत से मैच के लिए ब्राजील फुटबॉल टीम में विनीसियस-राफिन्हा शामिल

एजेंसी, कोलकाता। ब्राजील के स्टार खिलाड़ी विनीसियस जूनियर और राफिन्हा 3 अक्तूबर को कोलकाता में साल्ट लेक स्टेडियम में भारत के खिलाफ मैदान पर उतरेंगे। कोच कार्लो एंसेलोटी ने ऑस्ट्रेलिया और भारत के खिलाफ फ्रेंडली मैचों के लिए 26 सदस्यीय टीम घोषित कर दी है। इसमें विनीसियस, राफिन्हा, मार्क्विन्होस और ब्रूनो गुइमारेस जैसे बड़े नाम शामिल हैं। ब्राजील और भारत के बीच यह पहला अंतरराष्ट्रीय मुकाबला होगा। मैच कोलकाता के साल्ट लेक स्टेडियम में शाम 7:30 बजे खेला जाएगा। 2026 वर्ल्ड कप में नॉर्वे से हारकर राउंड ऑफ 16 से बाहर होने के बाद एंसेलोटी ने ब्राजील की टीम में बदलाव शुरू कर दिया है। उन्होंने पेड्रो मोरिस्को, ओटावियो, माउरो जूनियर, ब्रेनो बिडोन और गेब्रियल बोन्टेम्पो जैसे युवा खिलाड़ियों को मौका दिया है। इनमें कुछ खिलाड़ी 2028 लॉस एंजिल्स ओलिंपिक के लिए भी पात्र हैं। वहीं नेमार ने 34 साल की उम्र में अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास ले लिया है, जबकि कासेमिरो और गोलकीपर एलिसन को इस बार टीम में जगह नहीं मिली। दूसरी ओर विनीसियस जूनियर, राफिन्हा, कप्तान मार्क्विन्होस और ब्रूनो गुइमारेस जैसे प्रमुख खिलाड़ियों पर एंसेलोटी ने भरोसा कायम रखा है।

ईस्ट जोन तीसरी बार दलीप ट्रॉफी चैंपियन

साउथ जोन के खिलाफ फाइनल ड्रॉ रहने पर 14 साल बाद जीता खिताब

एजेंसी, बेंगलुरु

ईस्ट जोन तीसरी बार दलीप ट्रॉफी चैंपियन बन गया है। चेन्नई में साउथ जोन के खिलाफ फाइनल ड्रॉ रहा, लेकिन पहली पारी में बढ़त के आधार पर ईस्ट जोन को विजेता घोषित किया गया। कप्तान ईशान किशन के दोहरे शतक की मदद से टीम ने पहली पारी में 708 रन बनाए थे। ईशान को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। ईस्ट जोन ने इससे पहले 2011-12 और 2012-13 में दलीप ट्रॉफी जीती थी। 2011-12 में टीम ने फाइनल में सेंट्रल जोन को पारी और 20 रन से हराया था। वहीं, 2012-13 का फाइनल ड्रॉ रहा था और पहली पारी में बढ़त के आधार पर ईस्ट जोन चैंपियन बना था। अब टीम ने 14 साल बाद तीसरी बार ट्रॉफी अपने नाम की।

ईशान किशन रहे सीजन के टॉप स्कोरर

दलीप ट्रॉफी 2026 में ईस्ट जोन के कप्तान ईशान किशन सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे। उन्होंने 3 मैचों में 409 रन बनाए, जिसमें उनका सर्वोच्च स्कोर 270 रन रहा। साउथ जोन के तिलक वर्मा 266 रन के साथ दूसरे और ईस्ट जोन के कुमार कुशाग्र 224 रन के साथ तीसरे नंबर पर रहे। ईस्ट जोन ने पहली पारी में 708 रन का बड़ा स्कोर बनाया। कप्तान ईशान किशन ने 270 रन की पारी खेली थी। कुमार कुशाग्र ने 101, शिखर मोहन ने 85 और अभिमन्यु ईश्वरन ने 72 रन बनाए। वैभव सूर्यवंशी ने 44 रन का योगदान दिया।

यूएस ओपन : ज्वेरेव-खाचानोव सेमीफाइनल में

ज्वेरेव ने क्वार्टर फाइनल में बोटिक वैन और खाचानोव ने अलेक्जेंडर को हराया

एजेंसी, न्यूयॉर्क

शीर्ष वरीयता प्राप्त अलेक्जेंडर ज्वेरेव का अमेरिकी ओपन टेनिस टूर्नामेंट में क्वार्टर फाइनल तक का सफर उतार-चढ़ाव भरा रहा था, लेकिन उन्हें सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए किसी तरह की परेशानी नहीं हुई। ज्वेरेव ने क्वार्टर फाइनल में बोटिक वैन डे ज़ैंडशल्प को 6-2, 7-5, 6-1 से आसानी से हराया। इस तरह से उन्होंने मौजूदा सत्र के सभी ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट के अंतिम चार में जगह बनाने की विशिष्ट उपलब्धि हासिल की। फ्रेंच ओपन चैंपियन और विंबलडन उपविजेता ज़्वेरेव सेमीफाइनल में शुक्रवार को करेन खाचानोव का सामना करेंगे, जबकि दूसरे सेमीफाइनल में अमेरिकी खिलाड़ी बेन शेल्टन और फ्रांसिस टियाफो आमने-सामने होंगे। वहीं, खाचानोव इस साल प्रत्येक ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट के कम से कम तीसरे दौर तक पहुंचे, लेकिन यहां वह सेमीफाइनल में जगह बनाने में सफल रहे। उन्होंने अलेक्जेंडर ब्लॉक्स के मैच के बीच से हट जाने के बाद अंतिम चार में जगह सुरक्षित की।

एलेना रायबकिना और कोको गॉफ के बीच होगा महिला एकल का सेमीफाइनल

एजेंसी, न्यूयॉर्क। यूएस ओपन टेनिस के विमेंस सिंगल्स में कोको गॉफ और एलेना रायबकिना सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। गॉफ ने मिर्रा एंड्रीवा को हराया, वहीं रायबकिना ने झेंग किनवेन को 3-6, 6-1, 6-4 से शिकस्त दी। इस जीत के साथ रायबकिना पहली बार वर्ल्ड नंबर-1 बनीं। अब सेमीफाइनल में गॉफ और रायबकिना आमने-सामने होंगी। विमेंस सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में गॉफ ने पहला सेट 2-6 से गंवा दिया था। दूसरे सेट के टाईब्रेक में वह दो मैच पॉइंट पर थीं, लेकिन दोनों बचाकर सेट अपने नाम किया। इसके बाद निर्णायक सेट में उन्होंने एंड्रीवा को 6-2 से हराकर मुकाबला जीत लिया। वहीं, नंबर-1 रायबकिना ने झेंग के खिलाफ पहला सेट गंवाने के बाद लगातार दो सेट जीतकर मुकाबला अपने नाम किया।

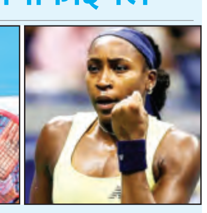

नेपाल पहुंची भारत की आठवीं राहत खेप, अब तक 130 टन मदद

नेपाल बाढ़: 1367 शव बरामद, पहचान में जुटे विशेषज्ञ

एजेंसी, नई दिल्ली

नेपाल में भीषण बाढ़ और भूस्खलन के बाद राहत एवं बचाव अभियान लगातार जारी है। भारत ने मानवीय सहायता बढ़ाते हुए बुधवार को 35 टन राहत और बचाव सामग्री की आठवीं खेप भारतीय वायुसेना के विमान से काठमांडू भेजी। इसके साथ भारत की ओर से अब तक नेपाल को 130 टन से अधिक राहत सामग्री उपलब्ध कराई जा चुकी है। राहत सामग्री में टेंट, कंबल, स्वच्छता किट, सौर लैंप, दवाएं और बचाव उपकरण शामिल हैं। भारत ने नेपाल में राहत अभियान 26 अगस्त से शुरू किया था। नेपाल पुलिस के अनुसार, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों से अब तक 1367 शव बरामद किए जा चुके हैं, जिनमें 102 की पहचान हो चुकी है। अन्य शवों की पहचान के लिए डीएनए नमूने जुटाए जा रहे हैं और भारत समेत कई देशों के फोरेंसिक विशेषज्ञ नेपाली एजेंसियों की सहायता कर रहे हैं। भारत ने राहत कार्यों में मदद के लिए 54 विशेषज्ञ भी नेपाल भेजे हैं, जिनमें सुरंग बचाव और फोरेंसिक विशेषज्ञ शामिल हैं।

चिलिमे में भारत-नेपाल की संयुक्त बचाव मुहिम जारी

रसुवा जिले के चिलिमे जलविद्युत परियोजना में नेपाली और भारतीय सेना की संयुक्त टीम खोज एवं बचाव अभियान चला रही है। टीम सर्विस सुरंग के अंदर करीब 105 मीटर तक पहुंच चुकी है। वहीं, सड़क से मलबा हटाने का काम भी जारी है। लापता लोगों और अज्ञात शवों की पहचान के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित तकनीक की भी मदद ली जा रही है। इस तकनीक के जरिये तस्वीरों और वीडियो में चेहरों का मिलान कर संभावित पहचान की जा रही है।

सेंसेक्स 138 अंक बढ़कर 74,903 पर बंद, निफ्टी भी 46 अंक चढ़ा

एजेंसी, मुंबई। घरेलू शेयर बाजार में गुरुवार को लगातार दूसरे सत्र की गिरावट के बाद तेजी लौट आई। सेंसेक्स 138 अंक चढ़कर 74,903 के स्तर पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 46 अंक की बढ़त के साथ 23,478 पर पहुंच गया। बाजार में बैंकिंग और मीडिया कंपनियों के शेयरों में अधिक खरीदारी देखने को मिली, जिससे प्रमुख सूचकांकों को मजबूती मिली। इससे पहले बुधवार को सेंसेक्स में 813 अंक और निफ्टी में 204 अंक की बड़ी गिरावट दर्ज की गई थी। गुरुवार की बढ़त को निवेशकों के लिए राहत के तौर पर देखा गया। घरेलू संस्थागत निवेशकों की लगातार खरीदारी से भी बाजार को सहारा मिला। पिछले सात दिनों में घरेलू संस्थागत निवेशकों ने 12,356 करोड़ रुपये के शेयर खरीदे हैं। वहीं, विदेशी संस्थागत निवेशकों ने इसी अवधि में 3,538 करोड़ रुपये की बिकवाली की। एशियाई बाजारों में कारोबार मिलाजुला रहा। जापान के निक्केई में बढ़त रही, जबकि दक्षिण कोरिया के कोस्पी और हांगकांग के हैंगसेंग में गिरावट दर्ज की गई। इससे पहले बुधवार को अमेरिकी बाजारों में भी कमजोरी रही थी। इसके बावजूद घरेलू बाजार में बैंकिंग और मीडिया शेयरों में खरीदारी के चलते सकारात्मक माहौल बना रहा।

मुंबई से तंजानिया के लिए शुरू होगी इंडिगो की सीधी उड़ान

एजेंसी, नई दिल्ली

देश की प्रमुख विमान सेवा कंपनी इंडिगो मुंबई से तंजानिया के दार एस सलाम के लिए सीधी दैनिक उड़ान सेवा शुरू करने जा रही है। एयरलाइंस के अनुसार यह सेवा 20 नवंबर से शुरू होगी। इस नई उड़ान के साथ इंडिगो मुंबई और दार एस सलाम के बीच सीधी हवाई कनेक्टिविटी उपलब्ध कराने वाली एकमात्र भारतीय विमान सेवा कंपनी बन जाएगी। यात्रियों के लिए उड़ानों की बुकिंग शुरू कर दी गई है। टिकट इंडिगो की आधिकारिक वेबसाइट, मोबाइल ऐप और अधिकृत यात्रा साझेदारों के माध्यम से बुक किए जा सकते हैं।

मुंबई से उड़ान संख्या 6ई 1851 रात 2.20 बजे रवाना होगी और स्थानीय समयानुसार सुबह 6.05 बजे दार एस सलाम पहुंचेगी। वापसी की उड़ान 6ई 1852 सुबह 7.05 बजे दार एस सलाम से रवाना होकर दोपहर 3.55 बजे मुंबई पहुंचेगी। कंपनी के मुताबिक भारत और तंजानिया के बीच व्यापार, निवेश, पर्यटन, शिक्षा और सांस्कृतिक संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं।

तंजानिया भारत के महत्वपूर्ण व्यापारिक साझेदारों में शामिल है और विनिर्माण, कृषि तथा स्वास्थ्य क्षेत्र में सहयोग बढ़ रहा है। इंडिगो के अनुसार सीधी दैनिक उड़ान से दोनों देशों के बीच यात्रियों की आवाजाही आसान होगी। इससे व्यापारिक गतिविधियों, निवेश, पर्यटन और शैक्षिक आदान-प्रदान को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

अडानी एयरपोर्ट्स बनी दुनिया की तीसरी सबसे मूल्यवान ऑपरेटर

नए निवेश से अडानी एयरपोर्ट्स का मूल्यांकन 19 अरब डॉलर पहुंचा

एजेंसी, अहमदाबाद

अडानी समूह की प्रमुख कंपनी अडानी एयरपोर्ट्स होल्डिंग्स ने टेमासेक, ब्लैकरॉक, अल्फा वेव ग्लोबल और प्रेमजी इन्वेस्ट जैसे बड़े निवेशकों से एक अरब डॉलर यानी करीब 8,300 करोड़ रुपये की नई इक्विटी पूंजी जुटाई है। वह स्पेन की एना तथा थाईलैंड के एयरपोर्ट्स ऑफ थाईलैंड के बाद दुनिया की तीसरी सबसे मूल्यवान एयरपोर्ट ऑपरेटर बन गई है।

अदाणी एयरपोर्ट्स में 5.24% हिस्सेदारी निवेशकों की

निवेश सौदा तीन चरणों में पूरा होगा और जुलाई 2027 तक निवेशकों के पास कंपनी की करीब 5.54 प्रतिशत हिस्सेदारी होगी। कंपनी के अनुसार, जुटाई गई राशि का इस्तेमाल उसके आठ मौजूदा हवाई अड्डों के आधुनिकीकरण, यात्री क्षमता बढ़ाने और टर्मिनल सुविधाओं को विश्वस्तरीय बनाने में किया जाएगा। अडानी एयरपोर्ट्स का लक्ष्य भविष्य में अपने नेटवर्क की सालाना यात्री क्षमता को 20 करोड़ तक पहुंचाना है। वर्तमान में कंपनी मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे समेत आठ प्रमुख हवाई अड्डों का संचालन करती है। यह भारत के कुल हवाई यात्री यातायात का करीब 25 प्रतिशत और हवाई कार्गो यातायात का लगभग 33 प्रतिशत हिस्सा संभालती है।

साझेदारी भारत और आगा खान डेवलपमेंट नेटवर्क के रिश्तों को मिलेगी नई मजबूती

पीएम मोदी से मिले प्रिंस रहीम आगा खान

एजेंसी, नई दिल्ली

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को भारत दौरे पर आए प्रिंस रहीम आगा खान पंचम से मुलाकात की। इस दौरान दोनों के बीच भारत और आगा खान डेवलपमेंट नेटवर्क के बीच विभिन्न क्षेत्रों में चल रहे सहयोग को और मजबूत करने पर चर्चा हुई। बातचीत में स्वास्थ्य, कृषि, ग्रामीण विकास, युवाओं और महिला सशक्तीकरण जैसे विषय प्रमुख रहे।

प्रधानमंत्री मोदी ने मुलाकात के बाद प्रिंस रहीम के पिता और दिवंगत आगा खान चतुर्थ के योगदान को याद करते हुए विकास के क्षेत्र में उनके कार्यों की सराहना की। उन्होंने कहा कि भारत और आगा खान डेवलपमेंट नेटवर्क के बीच साझेदारी को आगे बढ़ाने के तरीकों पर विचार किया गया है।

प्रिंस रहीम ने जयशंकर से भी की मुलाकात

प्रिंस रहीम आगा खान पंचम बुधवार को नई दिल्ली पहुंचे थे। फरवरी 2025 में अपने पिता प्रिंस करीम अल-हुसैनी आगा खान चतुर्थ के निधन के बाद इस्माइली समुदाय के 50वें इमाम की जिम्मेदारी संभालने के बाद यह उनकी पहली भारत यात्रा है। अपने करीब एक सप्ताह के दौरे के दौरान प्रिंस रहीम कई महत्वपूर्ण नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। इससे पहले उन्होंने उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और विदेश मंत्री एस. जयशंकर से भी मुलाकात की। विदेश मंत्रालय के अनुसार, उनकी यात्रा भारत और आगा खान डेवलपमेंट नेटवर्क के बीच लंबे समय से चले आ रहे सहयोग की समीक्षा करने तथा इसे भविष्य की जरूरतों के अनुरूप और प्रभावी बनाने का महत्वपूर्ण अवसर है। दोनों पक्ष सामाजिक विकास, विरासत संरक्षण समेत कई क्षेत्रों में चल रहे कार्यक्रमों पर भी चर्चा करेंगे। स्वास्थ्य के क्षेत्र में सहयोग से बेहतर सेवाओं को बढ़ावा देने, कृषि और ग्रामीण विकास से स्थानीय समुदायों की आजीविका मजबूत करने तथा युवाओं के लिए अवसर बढ़ाने पर ध्यान दिया जा सकता है। महिला सशक्तीकरण को साझेदारी के प्रमुख क्षेत्रों में शामिल करना भी समावेशी विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।